राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 26

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शनिवार, 6 जुलाई, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

रक्षा उत्पादन में 'मेक इन इंडिया' का नया कीर्तिमान

>>3

यात्रा

तितलियां, अभयारण्य और कीजिए मंदिरों के दर्शन

रायपुर : अगर आपको रंग-बिरंगी तितलियां भाती हैं तो चले आइए भोरमदेव अभयारण्य। कवर्धा जिले में स्थित इस अभयारण्य में 130 से अधिक प्रजाति की तितलियों के साथ जलाशय और प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। ● पेज-7

संपादकीय

संविधान बदलने का फर्जी विमर्श : इसकी जानबूझकर अनदेखी की जा रही है कि मोदी सरकार के विगत दस वर्षों के शासन में आठ संविधान संशोधन हुए और इन सभी का समर्थन विपक्ष ने किया। **उमेश चतुर्वेदी** का आलेख।

उचित नहीं नीट के खात्मे की मांग : यह ध्यान रहे तो बेहतर कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश की पुरानी व्यवस्था में परेशानी का कोई ठिकाना न था। **प्रो. निरंजन कुमार** का दृष्टिकोण। ● पेज-8

विमर्श

प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अंकुश : भारत जैसे देश में शिक्षा और नौकरी के लिए योग्यता मापने की किसी भी परीक्षा का आयोजन स्वयं में एक बड़ी चुनौती है। डा. **संजय वर्मा** का आलेख।

नीतीश तो बने रहे, मुरेठा उतर गया : राजनीति में पत्ते हमेशा सीधे नहीं पड़ते, कभी-कभी उलटे भी पड़ जाते हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक दांव उलटा पड़ गया, जिसे दर्शाती **आलोक मिश्रा** की डायरी। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

जोश नई राहों का

जज्बे की जीत

इंटरव्यू में यूं करें प्रभावित ● पेज-13

ओलिंपिक की चकाचौंध में खोए बिना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें खिलाड़ी : मोदी

- प्रधानमंत्री ने पेरिस ओलिंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से की बातचीत
- कहा, मैं पेरिस से लौटने के बाद आपके स्वागत की प्रतीक्षा करूंगा

26 से 11 अगस्त तक खेले जाएंगे पेरिस ओलिंपिक

100 से ज्यादा एथलीट अब तक कर चुके हैं क्वालीफाई

7 पदक जीतकर टोक्यो में भारत ने किया था सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

पेरिस ओलिंपिक में भाग लेने जा रही भारतीय टुकड़ी के साथ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा व अन्य। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस ओलिंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को जीत-हार का दबाव न लेते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की सलाह देते हुए कहा कि आपको ओलिंपिक की चकाचौंध में खोए बगैर फोकस बनाए रखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय खिलाड़ी पेरिस में पुराने सभी रिकार्ड तोड़कर देश के लिए गौरव लेकर आएंगे। मैं ओलिंपिक से लौटने के बाद खिलाड़ियों के स्वागत की प्रतीक्षा करूंगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को खिलाड़ियों से व्यक्तिगत और आनलाइन बातचीत में कहा, आप अपनी तपस्या से इस स्थान तक पहुंचे हैं। खेल के मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाला देश के लिए गौरव लेकर आता है। मैं आपका फिर से प्रतीक्षा करूंगा जब आप 11 अगस्त को ओलिंपिक समाप्त होने के बाद लौटेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहें ताकि देश आपको देख सके क्योंकि जीत हार तो अलग लेकिन ओलिंपिक खेलना ही बहुत बड़ी बात है। खिलाड़ी विफल होने पर भी कभी परिस्थिति को दोष नहीं देता। हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलिंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अपने खेल के अलावा बाकी खेलों को भी देखने का मौका होता है ताकि नया सीख सकें। ओलिंपिक 2036 की मेजबानी की भारत की दावेदारी कामयाब रहने को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से इस दावे को मजबूत करने के लिए पेरिस में व्यवस्थाओं का अनुभव साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी 2036 ओलिंपिक की मेजबानी का दावा मजबूत करने में काम आएगी।

नीरज से बोले पीएम, तुम्हारी मां के हाथ का चूरमा खाना है

पीएम ने बातचीत के दौरान नीरज से मजाकिया अंदाज में कहा, चूरमा आया नहीं तेरा अभी तक। इस पर नीरज ने कहा कि सर चूरमा लेकर आएंगे इस बार। पिछली बार दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था लेकिन आपको हरियाणा का देसी घी और गुड़ का चूरमा खिलाएंगे। इस पर पीएम ने कहा कि मुझे तो तेरी मां के हाथ का चूरमा खाना है। वहीं, प्रधानमंत्री ने पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी से पूछा कि तुम्हारे बालकृष्ण कहा हैं। प्रियंका ने बताया कि बाल गोपाल भी उनके साथ स्विट्जरलैंड में ही हैं। प्रधानमंत्री के पूछने पर कि क्या वह इस बार भी उन्हें ओलिंपिक में लेकर जा रही हैं, प्रियंका ने हां में जवाब देते हुए कहा कि यह उनका या बाल गोपाल का भी दूसरा ओलिंपिक है।

ईमानदार अभ्यर्थियों के हित में नहीं नीट-यूजी को पूर्ण रद करना : केंद्र

केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल कर इस मांग का किया विरोध

माला दीक्षित ● जागरण

- कहा, बड़े पैमाने पर परीक्षा की गोपनीयता भंग होने के सुबूत नहीं
- ऐसे में संपूर्ण परीक्षा व उसका रिजल्ट निरस्त करना तर्कसंगत नहीं

नीट पीजी 11 अगस्त को, दो चरणों में होगी परीक्षा

नई दिल्ली : मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट-पीजी 11 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने शुक्रवार को कहा कि 11 अगस्त को दो पालियों में नीट-पीजी का आयोजन किया जाएगा। (पेज-5)

नई दिल्ली : केंद्र सरकार व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी), 2024 को पूर्ण रूप से निरस्त करने की मांग का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि संपूर्ण परीक्षा रद करने से उन लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों के हित खतरे में पड़ेंगे जिन्होंने परीक्षा में कोई गैरकानूनी व अनुचित तरीका नहीं अपनाया। सरकार ने कहा, वह उन लाखों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ईमानदारी से प्रश्नपत्र हल किया। परीक्षा की गोपनीयता भंग होने के सुबूत नहीं होने पर संपूर्ण परीक्षा और उसका घोषित रिजल्ट निरस्त करना तर्कसंगत नहीं होगा।

केंद्र सरकार और एनटीए ने ये बातें नीट-यूजी, 2024 को पूर्ण रूप से निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा कराए जाने की मांग वाली दो दर्जन से ज्यादा याचिकाओं के जवाब में दाखिल अलग-अलग हलफनामों में कही हैं। मामले में शीर्ष कोर्ट आठ जुलाई को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका नीट के 56 सफल अभ्यर्थियों ने भी दाखिल की है जिसमें पूरी परीक्षा निरस्त करने का विरोध किया गया है। हालांकि वह याचिका अभी सुनवाई पर नहीं आई है। नीट-यूजी के जरिये ही एमबीबीएस, बीडीएस आदि में प्रवेश होता है।

केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि किसी भी परीक्षा में प्रतिस्पर्धी अधिकार होते हैं और कोई अनुचित साधन अपनाए बगैर बड़ी संख्या में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के हितों को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। सरकार इन याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं ले रही है और सरकार नीट-यूजी देने वाले छात्रों की चिंताओं को समझती है। मौजूदा मामले में सरकार ने समाधान उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार सभी प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मानती है कि किसी भी परीक्षा के प्रश्नपत्रों में गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि कुछ आपराधिक तत्वों के इशारे पर किसी अपराध के कारण गोपनीयता भंग हुई है तो उस व्यक्ति को दंड सुनिश्चित करने के लिए पूरी कानूनी ताकत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

हलफनामे में कहा गया है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लाया गया है जो 21 जून से प्रभावी हो गया है। इसमें सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से संबंधित अपराधों में सख्त सजा के प्रविधान हैं। नीट-यूजी में अनियमितताओं के कुछ कथित मामले सामने आए हैं। सीबीआइ ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा, 'कथित लीक के प्रयास का पांच मई को आयोजित पूरी परीक्षा के आयोजन पर असर नहीं पड़ा क्योंकि इसमें शामिल पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में नगण्य है। इस कारण पूरी परीक्षा को रद करना व्यापक जनहित, विशेष रूप से सफल अभ्यर्थियों के करियर की संभावनाओं के लिए बेहद प्रतिकूल और काफी हानिकारक होगा।' परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर कदाचार का दावा पूरी तरह से निराधार एवं भ्रामक है।

नीट मामले में बिहार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा पेज>>5

ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत, किएर स्टार्मर बने नए पीएम

- लेबर पार्टी को मिलीं 412 सीटें, सुनक की कंजरवेटिव पार्टी 121 पर सिमटी
- भारतीय मूल के 26 उम्मीदवार हाउस आफ कामंस के लिए हुए निर्वाचित

ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के साथ शुक्रवार को पीएम नियुक्त होने के उपरांत 10, डाउनिंग स्ट्रीट (पीएम आवास) पहुंचे किएर स्टार्मर, साथ में उनकी पत्नी विक्टोरिया। एपी

लंदन : प्रेट्र : ब्रिटेन में गुरुवार को हुए चुनाव में लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर 14 वर्ष बाद सत्ता में वापसी की है। अब तक 650 में से 648 सीटों के नतीजे आए हैं, जिसमें लेबर पार्टी को 412 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कंजरवेटिव पार्टी को 121 सीटें प्राप्त हुई हैं। ब्रिटेन में बहुमत का आंकड़ा 326 है। इसी के साथ लेबर पार्टी के नेता किएर स्टार्मर ब्रिटेन के आधिकारिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्टार्मर ने बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से भेंट की। किएर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने पहले संबोधन में कहा, बदलाव की शुरुआत हो गई है। किसी देश में बदलाव करना स्विच दबाने जैसा नहीं होता, इसमें कुछ समय लगेगा। सार्वजनिक सेवा एक विशेषाधिकार है। आपने लेबर पार्टी के लिए वोट किया हो या नहीं। मेरी सरकार आपके लिए काम करेगी। किएर ने पहले ब्रिटिश एशियाई पीएम ऋषि सुनक के काम को भी सराहा।' वहीं, सुनक ने हार के बाद पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा, इन परिणामों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। इस बीच पीएम स्टार्मर ने मंत्रियों की नियुक्ति भी शुरू कर दी है। उन्होंने एंजेला रेनर को डिप्टी पीएम, राचेल रीव्स को पहली महिला वित्त मंत्री नामित किया है। डेविड लैमी को विदेश, जान हीली को रक्षा व येत्ते कूपर को गृह मंत्री बनाया है। डेविड लैमी भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्षधर रहे हैं। वे कह चुके हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह पहले माह भारत का दौरा करेंगे। भारतीय मूल के 26 प्रत्याशी चुनाव में जीत कर हाउस आफ कामंस पहुंचे हैं। पिछले चुनाव में भारतीय मूल के 15 सांसद जीते थे। (पेज-11 भी देखें)

किएर स्टार्मर को चुनाव में शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं। मैं आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूं।
– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में चार शहरों में ईडी के छापे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

10 से अधिक एसटीपी के विस्तार और नवीनीकरण की टेंडर प्रक्रिया में करोड़ों के घोटाले का मामला

- दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई व हैदराबाद में कंपनियों के कार्यालयों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापे

दिल्ली जल बोर्ड के 10 से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के विस्तार और नवीनीकरण की टेंडर प्रक्रिया में करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में ईडी ने गुरुवार को दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में अलग-अलग जगहों पर आठ घंटे तक छापेमारी की। जल बोर्ड में ठेका लेने वाली कंपनियों के दफ्तरों व अधिकारियों के घरों पर छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध दस्तावेज जब्त करने की बात सामने आई है। जल बोर्ड घोटाले में मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए ईडी ने जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने मेसर्स यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पप्पनकला, निलोठी, नजफगढ़, केशोपुर, कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी और कोंडली में 10 एसटीपी के विस्तार के लिए अक्टूबर 2022 में विभिन्न संयुक्त उद्यम संस्थाओं को 1,943 करोड़ रुपये के चार टेंडर दिए गए थे। आरोप है कि सभी निविदाओं में तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें दो कंपनियों को एक-एक टेंडर, एक कंपनी को दो टेंडर मिले। प्राथमिकी में कहा गया कि निविदा की शर्तों को इस तरह बनाया गया कि कुछ चुनिंदा कंपनियां ही निविदाओं में भाग ले सकें। शुरू में लागत का अनुमान 1,546 करोड़ रुपये था, पर टेंडर प्रक्रिया के दौरान इसे संशोधित कर 1,943 करोड़ कर दिया गया था। तीन कंपनियों को बढ़ी हुई दरों पर ठेके दिए गए। ईडी की जांच में पता चला कि तीन कंपनियों ने निविदाएं हासिल करने के लिए ताइवान प्रोजेक्ट से जारी एक ही अनुभव प्रमाणपत्र जल बोर्ड में जमा किया था, जिसे बिना सत्यापन के स्वीकार किया कर लिया। इसके बाद मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को चार निविदाओं से संबंधित कार्य का उप-ठेका दिया गया। ईडी ने 41 लाख रुपये नकद, कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं।

जल बोर्ड के पूर्व सलाहकर पर 15 मई को दर्ज किया गया था केस पेज>>2

बिहार में पुल गिरने के मामलों में 11 और इंजीनियर निलंबित

पटना : बिहार के सारण और सिवान जिले में जल संसाधन विभाग के छह पुल गिरने के बाद एक्शन में आई नीतीश कुमार की सरकार ने 11 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही निर्माण में लगी एजेंसी को आगे कोई काम न देने का निर्णय भी लिया है। (पेज-5)

विश्वास.News

फर्जी दावे के साथ नेहरू की तस्वीर प्रसारित ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज-6

युवाओं की पैरीक्षा

आज का मैच (पहला टी-20)

भारत vs जिंबाब्वे

शाम 4:30 बजे | स्थान : हरारे

प्रसारण : सोनी स्पोर्ट्स

सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार के विरोध के लिए मुस्लिम छात्रों को जरिया बनाएगी जमीयत

नेमिष हेमंत ● जागरण

- जमीयत उलेमा-ए-हिंद प्रबंधन समिति ने दो दिवसीय अधिवेशन में पारित किया प्रस्ताव
- शिक्षा संस्थानों में टकराव के रास्ते पर बढ़ी जमीयत, कहा-जबरदस्ती का विरोध करें युवा

जमीयत उलेमा ए हिन्द के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। जागरण

नई दिल्ली : कभी आधुनिक शिक्षा की पैरोकारी करने वाली जमीयत उलेमा-ए-हिंद शिक्षा संस्थानों में टकराव के नए रास्ते पर आगे बढ़ रही है, और ढाल छात्रों को बनाया है। जमीयत ने स्कूलों में सरस्वती वंदना, गीतों और सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियों को अधार्मिक बताते हुए मुस्लिम छात्रों से बहिष्कार और विरोध का आह्वान किया है। साथ ही मुस्लिम छात्रों के लिए कुरआन पढ़ने और कंठस्थ कराने तथा फारसी शिक्षा की वकालत की है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति के दो दिवसीय अधिवेशन के अंतिम दिन शुक्रवार को इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया।

जमीयत मुख्यालय में आयोजित अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में मुसलमानों से आग्रह किया गया है कि वे अपने बच्चों में तौहीद (एकेश्वरवाद) में विश्वास पैदा करें और शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी बहुदेववादी प्रथाओं में भाग लेने से बचें। अगर इस संबंध में संस्थान की ओर से जबरदस्ती की जाए तो विरोध करें और कानूनी कार्रवाई करें।

एक दिन पहले युवाओं से आधुनिक शिक्षा से देश सेवा का आह्वान किया गया था पेज>>6

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कोई जन्मजात नहीं होता अपराधी, बनाया जाता है

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, अपराध के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं, कहा-हर संत का बीता हुआ कल होता है और हरेक पापी का भविष्य होता है

- खंडपीठ ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार हुए आरोपित को दी सशर्त जमानत

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपराधी पैदा नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं। किसी के अपराध करने के पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं। निसंदेह हर संत का एक बीता हुआ कल होता है और हरेक पापी का एक भविष्य होता है। सर्वोच्च अदालत ने इस टिप्पणी के साथ दो हजार के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार हुए एक आरोपित की चार साल से रुकी सुनवाई पर टिप्पणी करते हुए उसे सशर्त जमानत दे दी।

विगत तीन जुलाई के अपने आदेश में जस्टिस जेबी पार्डीवाला और उज्ज्वल भुयन की खंडपीठ ने कहा कि लोग जन्म से अपराधी नहीं होते हैं। हर इंसान में मानवीय गुणों को उभारने की गुंजाइश होती है। इसीलिए किसी भी अपराधी के सुधरने की उम्मीद को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। प्रायः यह मूलभूत मानवीय सिद्धांत वयस्क या किशोर अपराधियों के संबंध में विचार करते हुए लोग भूल जाते हैं। अपराध करने की कई वजहें हो सकती हैं। यह कारक आर्थिक, सामाजिक या नैतिक मूल्यों का ह्रास, मां-बाप की अनदेखी आदि हो सकते हैं। अपराध किसी आवेश या परिस्थितिजन्य भी हो सकते हैं।

खंडपीठ ने कहा, अपराध कितना ही गंभीर क्यों नहीं हो, एक अपराधी को जल्द से जल्द सुनवाई का अधिकार है। लेकिन एक अरसे से सुनवाई अदालतें और हाई कोर्ट कानून के इस बहुत ही मान्य सिद्धांत को भूल गए हैं। उन्हें समझना होगा कि जमानत को सजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर संबंधित अदालत समेत कोई राज्य या अभियोजन पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपित के मूलभूत अधिकारों को प्रदान करने या सुरक्षित करने की चिंता नहीं है तो उन्हें अपराध गंभीर मानते हुए जमानत से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह आरोपित की जमानत मंजूर कर रही है लेकिन वह मुंबई शहर छोड़कर नहीं जा सकेगा। उसे हर 15 दिन में संबंधित एनआइए कार्यालय या पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उल्लेखनीय है कि इस आरोपित को 9 फरवरी, 2020 में मुंबई के अंधेरी इलाके में दो हजार के 1193 नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि नकली नोट पाकिस्तान से तस्करी करके मुंबई लाए गए थे। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि इसी मामले में दो अन्य आरोपित जमानत पर बाहर हैं।

सूरजपाल के खिलाफ अनुयायियों में गुस्सा, बताया धोखेबाज व ढोंगी

अलीगढ़ : अनुयायियों के बीच सूरजपाल सिंह (नारायण साकार विश्व हरि) स्वयं को 'परमात्मा' बताता है। सत्संग में हर पल साथ रहने की बात कहता है। लेकिन जब अनुयायियों पर मुसीबत आई तो खुद सारी मानवता और इंसानियत भूल गया। भगदड़ में उसे ईश्वर मानने वाले अनुयायी मर रहे थे, लेकिन उसने किसी की चिंता नहीं की। एक बार पलट कर नहीं देखा। (पेज-6)

भारतीय विमान हाईजैक करने वाले आतंकी की पाक में मौत

अमृतसर : आतंकी जरनैल सिंह भिंडरांवाला की गिरफ्तारी के विरोध में 29 सितंबर, 1981 को दिल्ली से एयर इंडिया के विमान को हाइजैक कर लाहौर ले जाने वाले आतंकी गजिंदर सिंह की गत तीन जुलाई को पाकिस्तान में हार्ट अटैक से मौत हो गई। चार जुलाई को पाकिस्तान में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। शव को मुखाग्नि उसकी बेटी विक्रमजीत कौर ने दी। (पेज-11)

'विस अध्यक्ष ने तृकां विधायकों को शपथ दिलाकर संविधान का उल्लंघन किया'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पत्र लिख अध्यक्ष की शिकायत की

उपाध्यक्ष के बदले अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाए जाने से राज्यपाल खफा

बंगाल में तृकां के दो निर्वाचित विधायकों के शुक्रवार को शपथ लेने के बावजूद विधानसभा व राजभवन के बीच टकराव थमता नजर नहीं आ रहा है। राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने अब विधानसभा उपाध्यक्ष के बदले अध्यक्ष बिमान बनर्जी द्वारा विधायकों को शपथ दिलाने पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान का उल्लंघन बताया है। शुक्रवार शाम उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर विस अध्यक्ष की शिकायत की। ज्ञात हो, बोस ने शपथ दिलाने के लिए उपाध्यक्ष को अधिकृत किया था।

राज्यपाल ने राष्ट्रपति को यह पत्र दोपहर में बुलाए गए विस के विशेष सत्र के दौरान अध्यक्ष द्वारा कोलकाता के बरानगर से विधायक सायंतिका बनर्जी व मुर्शिदाबाद जिले के भगवानगोला सीट के विधायक रेयात हुसैन सरकार को शपथ दिलाने के कुछ घंटे बाद लिखा है। पत्र में राज्यपाल ने विस अध्यक्ष के संवैधानिक रूप से अनुचित कदम का उल्लेख किया है। वहीं, विस अध्यक्ष ने कहा, हमने सब काम संविधान के अनुरूप किया है। उन्होंने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे पत्र पर टिप्पणी करने से इन्कार किया।

एक महीने के बाद तृणमूल कांग्रेस के दोनों विधायकों ने ली शपथ पेज>>5

****

180 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा निदेशालय ने खजूरी खास स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय व सर्वोदय कन्या विद्यालय में में की है। इसमें 106 सर्वोदय कन्या और 74 सर्वोदय बाल विद्यालय में तैनात किए गए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 6 जुलाई, 2024

आज का मौसम

शनिवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे। गरज व बिजली चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
6 जुलाई	33.0	26.0
7 जुलाई	34.0	26.0
नोएडा		
6 जुलाई	33.0	26.0
7 जुलाई	34.0	26.0
गुरुग्राम		
6 जुलाई	32.0	28.0
7 जुलाई	31.0	27.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने युवक की हत्या

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने बृहस्पतिवार देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह पुलिस को घटना की जानकारी मिली। मरने वाले की पहचान गौरव ठाकुर के रूप में हुई है। उसका शव एक चारपाई पर पड़ा मिला। चारपाई पर खाने का सामान और एक कुर्सी रखी थी। चारपाई के पास खून बिखरा था। उसकी गर्दन पर पीछे चाकू से वार करने के निशान मिले हैं। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। इस बाबत पुलिस ने उसके स्वजन को घटना के बारे में जानकारी दे दी है। पुलिस का कहना है कि किसी भारी चीज से गौरव का सिर पर वार कर हत्या की गई है। पुलिस को शक है कि किसी परिचित ने ही वारदात को अंजाम दिया है। (जासं)

सराय रोहिल्ला में हत्या के मामले में बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली: सराय रोहिल्ला में रवि यादव नाम के शख्स की हत्या करने के मामले में वांछित अजय कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल आठ अन्य को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपित हत्या और लूटपाट के पहले के दो मामलों में शामिल रहा है। डीसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक अजय कुमार उर्फ छोटू, राखी मार्केट, जखीरा का रहने वाला है। मई माह में सराय रोहिल्ला की रहने वाली सावित्री यादव ने सराय रोहिल्ला थाने में शिकायत पर पति रवि यादव की हत्या के लिए नौ लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। बयान में महिला ने आरोप लगाया था कि उनके पति की हत्या जखीरा के रहने वाले कृष्ण ने साथियों के साथ मिलकर की है। कृष्ण पर आनंद पर्वत में राजन नाम के शख्स की भी हत्या करने का आरोप है। (जासं)

ट्रायल कोर्ट के बजाय सीधे हाई कोर्ट जाने पर सीबीआइ ने जताई आपत्ति

आबकारी नीति घोटाला ▶ दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सीबीआइ द्वारा गिरफ्तारी और जारी रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 17 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई
- कहा, ट्रायल कोर्ट के फैसले से भी लाभ होगा

अरविंद केजरीवाल।

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत के बजाय सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जमानत याचिका दायर करने पर सीबीआइ ने आपत्ति जताई। जांच एजेंसी ने सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है और यह मुद्दा पहले से ही एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है।

जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। सीबीआइ की आपत्ति को दर्ज करते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि इस पर जिरह के दौरान विचार किया जाएगा। साथ ही याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इसी दिन सीबीआइ द्वारा गिरफ्तारी और इसके बाद जारी रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होती है।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि कितने मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा है कि कृपया वापस जाएं। कानून पर कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जब वैकल्पिक उपाय हो तो हाई कोर्ट को बाधित न करें। कोई कारण होना चाहिए कि हाई कोर्ट बेहतर है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के फैसले से भी लाभ होगा। पीठ ने कहा कि पक्षकारों को सत्र अदालत के समक्ष पहली सुनवाई का भी लाभ मिलता है और वे वहां सफल हो सकते हैं।

केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि ऐसे में जबकि निचली अदालत ने केजरीवाल को रिमांड पर देते हुए पाया था कि सीआरपीसी की धारा- 41ए का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाना व्यर्थ होगा। सीबीआइ की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत को सूचित किया कि जमानत याचिका और केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए आधार समान हैं और मुख्यमंत्री के पास जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

वहीं, केजरीवाल की तरफ से जिरह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है और केजरीवाल को दो साल बाद गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई है और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं। केजरीवाल सिर्फ कुछ अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से तर्क दिया गया कि उन्हें हिरासत में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। सीबीआइ ने 26 जून को केजरीवाल से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआइ व ईडी दोनों ही मामले में केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार पर 15 मई को दर्ज किया गया था केस

प्रथम पृष्ठ से आगे

गत 15 मई को सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव (हाइड्रोलिक्स और जल निकाय) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी व साजिश रचने आदि धाराओं में केस दर्ज किया था। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों व निजी व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए एसआइटी का गठन किया गया था।

एसीबी को प्रारंभिक जांच में विभिन्न परियोजनाओं के टेंडर और फर्जी बिल लगाने से संबंधित घोटाले का पता लग गया था, क्योंकि कई मामलों में बिना काम किए करोड़ों रुपये के चालान प्रस्तुत किए गए थे। फर्जी चालान से पता चला था कि काम किए बिना ही भुगतान ले लिया गया। एसीबी ने जांच में यह भी पाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में अंकित श्रीवास्तव की नियुक्ति भी नियम कानून को ताक पर रखकर की गई।

ससुर की कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया: जलबोर्ड के पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव ने ससुर अमरीश भाटिया की कंपनी को रोहिणी एसटीपी में जल निकाय के निर्माण से संबंधित टेंडर में अनुचित लाभ पहुंचाया था। साइट पर हैवी मशीनरी के शिपमेंट में जो नंबर चालान में दिया गया था, वह असल में कार का पंजीकरण नंबर पाया गया, जिससे हैवी मशीनरी ढोना व्यावहारिक रूप से असंभव है। अमरीश के स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स एडी हाइड्रो न्यूमेक इंजीनियर्स की ओर से वाटर बाडी वाली साइट पर मशीनरी नहीं लगाई गई थी। कंपनी ने नकली चालान तैयार किए गए थे। इसकी वजह से सरकार को 2.16 करोड़ राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा।

आइजीआइ से सवा सौ उड़ानों के प्रस्थान में विलंब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : शुक्रवार को सवा सौ उड़ानों में विलंब की स्थिति आइजीआइ एयरपोर्ट पर देखने को मिली। विलंबन की सर्वाधिक मार स्पाइसजेट के यात्रियों को उठानी पड़ी। स्पाइसजेट की गुवाहाटी जाने वाली उड़ान 11 घंटे विलंब से गंतव्य के लिए प्रस्थान की गई। इसी तरह अहमदाबाद की उड़ान में सात घंटे विलंब की स्थिति रही। श्रीनगर की उड़ान में पांच घंटे, मुंबई की उड़ान चार घंटे विलंब से रवाना हुई। कई दिनों दरभंगा की उड़ान में विलंब दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को भी दरभंगा की उड़ान चार घंटे की देरी से रवाना हुई।

सीएम आवास में नवीनीकरण पर चल रही जांच में नया मोड़

वी के शुक्ला ● जागरण

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच में नया मोड़ आ गया है। इस परियोजना में उस समय शामिल रहे लोक निर्माण विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता ए के आहुजा ने मिले नोटिस पर दिल्ली सरकार को भेजे लिखित जवाब में कहा है कि वह विभाग में प्रमुख अभियंता नहीं थे, मगर प्रमुख अभियंता की हैसियत से उन्हें नोटिस भेजा गया है। जबकि इस मामले में वह नहीं बल्कि उस समय विभाग के प्रमुख अभियंता शशिकांत थे।

इस मामले में यह पहली बार है कि विभाग प्रमुख रहे किसी अधिकारी का नाम सामने आया है। फिलहाल सरकार का सतर्कता निदेशालय मामले की जांच कर रहा है। उधर शशिकांत ने कहा है कि यह मामला कभी उन तक नही आया। अगर कोई यह कहता है कि उन्होंने कोई आदेश दिए हैं तो वह पेपर सामने लाए जाएं। यह पूरा नया विवाद इसलिए सामने आया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में जांच करने के बाद जब इसमें आरोपित सात अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा था। जिसमें उनसे जवाब मांगा गया। इसमें अधिकतर अभियंताओं ने जवाब दे दिया है। इन सात अभियंताओं में दो अभियंता ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनमें उस समय अधिशासी अभियंता रहे एसएन धारा और विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता एकके आहुआ भी शामिल हैं। आहुजा ने जवाब में कहा है कि मैं सितंबर 2020 में सेवानिवृत्त हो गया था। जबकि इस मामले की निविदा अक्टूबर में जारी की गई और कंपनी को काम दिसंबर में सौंपा गया था। इस परियोजना पर काम शुरू होने पर मैं सेवानिवृत्त हो गया था। आहुजा ने कहा है कि मुझे दिए गए कारण बताओ नोटिस का पैरा 94 (ब) भी मुझसे संबंधित नहीं है।

के कविता के आरोप पत्र पर सुनवाई आज

जासं, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। शुक्रवार को कविता की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआइ ने उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश किया था। सीबीआइ ने अदालत से कविता की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। वहीं, कविता के अधिवक्ता ने सीबीआइ के इस आवेदन का विरोध किया। दो दिन पहले आबकारी नीति घोटाले में अदालत ने के. कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

इससे पहले सीबीआइ ने मामले में कविता के खिलाफ अदालत में पूरक आरोपपत्र दायर किया था। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं मामले की सुनवाई छह जुलाई को तय है। कविता को सीबीआइ ने अप्रैल में तिहाड़ में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें इससे जुड़े गिरफ्तारी के बाद रखा गया था।

यमुना में भरी है गाद पर बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी होने का दावा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

- एपेक्स कमेटी की बैठक के बाद आप सरकार ने दी तैयारियों की जानकारी
- नालों की सफाई के दावों के बाद दिल्ली ने हाल में देखा है भारी जलभराव

सौरभ भारद्वाज और आतिशी। फाइल

पिछले वर्ष आई बाढ़ के बाद भी यमुना में न गाद की सफाई हुई और न ही डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है। नदी में कई स्थानों पर टीले बने हुए हैं। विभागों के दावों के बावजूद सीवर लाइन और नालों की सफाई नहीं होने से पिछले सप्ताह वर्षा से दिल्लीवासियों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए लोगों को पिछले वर्ष की तरह बाढ़ की चिंता सता रही है।

वहीं, आप सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए सभी तैयारी पूरी होने का दावा किया है। उसका कहना है कि बाढ़ की स्थिति पैदा होने की आशंका से पहले ही सभी संबंधित एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। शुक्रवार को राजस्व मंत्री आतिशी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ नियंत्रण एपेक्स कमेटी की बैठक की।

बाढ़ नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम

- 24 घंटे निगरानी के लिए पूर्वी दिल्ली के डीएम कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यहां से अधिकारी हथनीकुंड बैराज से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर हरियाणा के सिंचाई विभाग के साथ संपर्क में हैं।
- यमुना के बहाव क्षेत्र के आसपास के मौसम की निगरानी भी की जा रही है
- हथनीकुंड से एक लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर सभी विभाग सक्रिय होंगे। अभी 352 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। डूब क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी की जाएगी। लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जाएगा।
- पिछले वर्ष हथनीकुंड से ज्यादा पानी छोड़ने और आइटीओ बैराज के गेट नहीं खुलने से बाढ़ की स्थिति बनी थी। इस बार आइटीओ बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। नदी में बने टीले पर पायलट कट बनाए गए हैं, जिससे पानी का बहाव बाधित नहीं होगा।

दुर्भावनापूर्ण तरीके से विवाद को जिंदा रखना अन्य के लिए हानिकारक

विनीत त्रिपाठी ● जागरण

- हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामलों को रद करने का दिया आदेश
- शिकायतकर्ता को याची को 50 हजार हर्जाना अदा करने का आदेश दिया

नई दिल्ली: जानबूझकर अदालतों में मामलों को लंबित रखने वाले वादियों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वादियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण कारणों से विवाद को जिंदा रखने से अदालत पर बोझ बढ़ता है और यह उन वादियों के लिए हानिकारक होता है, जिनके मामले वर्षों से लंबित हैं। अदालत ने यह टिप्पणी 80 लाख रुपये के एक चेक बाउंस मामले पर सुनवाई करते हुए की। इसमें शिकायत 2015 में की गई थी और पक्षकारों ने बाद में समझौता कर लिया था। समझौते के बावजूद कार्यवाही जारी रहने से व्यथित होकर आरोपित ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि समझौता दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए मसौदों में से केवल एक था और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज नहीं करने के कारण यह बाध्यकारी नहीं था। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों ने वर्ष 2016 में ही अपने विवादों का निपटारा कर लिया था।

शिकायतकर्ता ने पक्षकारों के बीच सहमति के अनुसार राशि भी स्वीकार कर ली है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान करने के बावजूद शिकायतकर्ता के बेईमान रवैये के कारण पिछले आठ वर्षों से अधिक समय से परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके कारण अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामलों को रद करते हुए शिकायतकर्ता को याची को 50 हजार का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया।

मकान का छज्जा गिरने से एक परिवार के तीन बच्चों की मौत

जासं, फरीदाबाद: सेक्टर-58 थाने के अंतर्गत सीकरी गांव में एक मकान का छज्जा गिरने से नीचे खेल रहे एक परिवार के तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। छज्जे की हालत ठीक नहीं थी। वर्षा के बाद इसकी हालत और खराब हो रही थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह गिर जाएगा। हादसा शुक्रवार देर शाम हुआ। यह मकान गांव में राकेश का है। उसने किराये के लिए कमरे बनाए हुए हैं। इन्हीं कमरों में कुछ प्रवासी लोग किराये पर रहते हैं। एक कमरे में धर्मेंद्र अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था।

देर शाम इस मकान का छज्जा एकाएक गिर गया, जिसके चलते छज्जे के नीचे बैठे धर्मेंद्र का पुत्र आदिक (10), आकाश (9) व पुत्री मुस्कान (11) उसकी चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई। थाना सेक्टर-58 व सीकरी चौकी पुलिस तीनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिए हैं। पोस्टमार्टम शनिवार सुबह होगा।

लोको पायलट की समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे राहुल गांधी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी। सौजन्यः रेलवे कर्मचारी

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को जीटीबी नगर में जहां दैनिक श्रमिकों से मुलाकात की थी, वहीं शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मिले। रेलवे अधिकारियों को उनके स्टेशन आने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। इस दौरान उन्होंने लोको पायलट ने उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और समाधान के लिए इन्हें सरकार के सामने उठाने का आश्वासन दिया।

राहुल गांधी ने लोको पायलट से उनके काम और उसमें आने वाली परेशानियों के बारे में जाना। सिग्नल प्रणाली के साथ ही हाल में हुए ट्रेन दुर्घटनाओं के संभावित कारणों के बारे में भी जानकारी ली। शुक्रवार की दोपहर करीब 12:30 बजे राहुल गांधी अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लोको पायलट रनिंग रूम में पहुंचे। उस समय वहां पर देश के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से पहुंचे लगभग 50 लोको पायलट उपस्थित थे। लोको पायलट समेत अन्य रेलवे कर्मियों ने राहुल के साथ सेल्फी ली। उन्हें समस्याएं बता हल कराने की मांग की।

लोको पायलटों ने कहा- भर्ती नहीं होने से काम का बोझ बढ़ रहा है: लोको पायलटों ने राहुल गांधी को बताया कि उन्हें काम अत्यधिक दबाव की वजह से पर्याप्त आराम नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेन लेकर आते हैं। अक्सर उन्हें पर्याप्त आराम लिए बगैर ही ड्यूटी पर आना पड़ता है। इससे तनावग्रस्त रहते हैं और उनकी एकाग्रता में कमी आती है। ट्रेन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण यह भी है।

सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में प्रवेश के लिए होगी सामान्य परीक्षा

जासं, नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में नान प्लान दाखिले के तहत आवेदन की तिथियां जारी कर दी हैं। निदेशालय ने कहा कि बहुत से उम्मीदवार निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं और बार-बार स्कूलों में संपर्क कर रहे थे। ऐसे में उम्मीदवारों को एक और मौका दिया जा रहा है। निदेशालय ने कहा कि दाखिले के लिए आवेदन आठ जुलाई से शुरू होंगे और 20 जुलाई तक चलेंगे। वहीं, 25 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 29 जुलाई को सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी।

निदेशालय ने कहा कि परीक्षा कुल दो घंटे की होगी, जो कि सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड या स्कूल आइडी लेकर आना होगा। दो अगस्त को परिणाम जारी होगा। वहीं, उम्मीदवार को परीक्षा में तभी पास घोषित किया जाएगा, जब वह प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

सुविधा

एलएचएमसी में मशान लगाने और उसका ट्रायल पूरा करने में अभी लगेंगे तीन माह, कैंसर मरीजों को रेडिएशन थेरेपी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी

एक्सीलेरेटर मशीन से होगा कैंसर का इलाज

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

- कैंसर मरीजों को रेडिएशन थेरेपी देने की सुविधा शुरू हो जाएगी
- सर्विकल कैंसर के इलाज में होता है इस तकनीक का इस्तेमाल अधिक

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज। फाइल

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (एलएचएमसी) के अस्पताल में लंबे समय के इंतजार के बाद रेडियोथेरेपी की अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेरेटर मशीन आ गई है। अगले करीब तीन माह में यह मशीन लगाने और उसके ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद इस मशीन से कैंसर मरीजों को रेडिएशन थेरेपी देने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे कैंसर के मरीजों को राहत मिलेगी और सरकारी क्षेत्र के अस्पताल में इलाज का एक नया विकल्प भी मिलेगा।

एलएचएमसी में वर्ष 1999 से रेडियोथेरेपी विभाग है, लेकिन रेडियोथेरेपी के लिए मशीन उपलब्ध नहीं होने से कैंसर के मरीजों को रेडिएशन थेरेपी की सुविधा नहीं मिल पाती थी। एलएचएमसी में करीब पांच वर्ष पहले कैंसर ब्लाक बना था। फिर भी रडियोथेरेपी की मशीन नहीं लग पाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति ने भी इस पर सवाल उठाया था। पिछले वर्ष एलएचएमसी प्रशासन ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएलएल के साथ एक समझौता कर 78 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाने की पहल की गई। इसके तहत कैंसर ब्लाक के भूतल पर ब्रेकीथेरेपी मशीन लगाई गई। अप्रैल में भी इस अस्पताल में ब्रेकीथेरेपी से कैंसर मरीजों के इलाज की सुविधा शुरू हुई है। ब्रेकीथेरेपी से शरीर के अंदरूनी हिस्से में एक एप्लीकेटर लगाकर आंतरिक रूप से कैंसर ट्यूमर को रेडिएशन दिया जाता है। सर्विकल कैंसर के इलाज में इस तकनीक का इस्तेमाल अधिक होता है। इसके अलावा स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ओरल कैंसर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है।

दूसरी ओर, लीनियर एक्सीलेरेटर मशीन से बाहर से ही शरीर के किसी हिस्से में मौजूद ट्यूमर को रेडिएशन दिया जा सकता है। कैंसर को रेडिएशन देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल अधिक होता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इस अत्याधुनिक सुविधा का अभाव है। दिल्ली में अभी तक तीन सरकारी अस्पतालों में ही लीनियर एक्सीलेरेटर मशीन पहले से उपलब्ध है, जिसमें एम्स, दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान व लोकनायक अस्पताल शामिल है। अब एलएचएमसी में भी रेडियोथेरेपी की लीनियर एक्सीलेरेटर मशीन उपलब्ध हो गई है। इस मशीन को लगाने का काम चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल में रेडियोथेरेपी की एक कोबाल्ट मशीन है। इस अस्पताल में भी लीनियर एक्सीलेरेटर मशीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस अस्पताल में अभी मशीन लगने में लंबा समय लगेगा।

****

एनएसयूआइ ने डूसू अध्यक्ष पर जाली मार्कशीट के प्रयोग से प्रवेश लेने का आरोप लगाया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कुलपति को ज्ञापन सौंप तुषार डेढ़ा का डूसू अध्यक्ष पद पर चुनाव अमान्य घोषित करने की मांग की
- तुषार ने कहा, एनएसयूआइ मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआइ) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) अध्यक्ष तुषार डेढ़ा पर जाली मार्कशीट के जरिये डीयू में प्रवेश लेने और अध्यक्ष बनने का आरोप लगाया है। डूसू के उपाध्यक्ष और एनएसयूआइ के पदाधिकारी अभि दहिया ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह को ज्ञापन देकर तुषार डेढ़ा का अध्यक्ष पद पर चुनाव अमान्य घोषित कर मुकदमा चलाने की मांग की है। पूरे मामले पर तुषार डेढ़ा ने कहा कि एनएसयूआइ मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का दो जगह से डिग्री करने को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। उसी के तहत मैंने पढ़ाई की है। इसमें एक मार्कशीट का उपयोग किया जा सकता है और मैंने यूपी बोर्ड की मार्कशीट का उपयोग किया।

अभि दहिया ने कुलपति को सौंपे मांग पत्र में कहा है कि डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा ने सत्यवती कालेज से बीए प्रोग्राम में स्नातक किया है। वर्तमान में वह बौद्ध स्टडी में स्नातकोत्तर कर रहे हैं। उनके पास 12वीं की दो मार्कशीट हैं। इसमें कला संकाय की मार्कशीट सीबीएसई की है, जबकि उत्तर प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट विज्ञान संकाय से है। दोनों परीक्षाएं 2016 में नियमित विद्यार्थी के तौर पर उत्तीर्ण की हैं। दोनों ही बोर्ड के नियमों के अनुसार नियमित छात्र को 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही उसे किसी अन्य बोर्ड से उसी समय समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन तुषार डेढ़ा के मामले में ऐसा नहीं है। यह सीबीएसई और यूपी बोर्ड के परीक्षा उपनियमों का पूरी तरह से उल्लंघन है। इसलिए दोनों अंकपत्र शून्य हैं।अभि ने कहा कि तुषार ने जानबूझकर अवैध तरीकों का इस्तेमाल किया और प्रवेश पाने के लिए अपनी योग्यता के बारे में गलत तथ्य दिए। उन्होंने डूसू अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए अपनी योग्यता के बारे में गलत बयान और हलफनामा भी दायर किया है। इसलिए डूसू के अध्यक्ष पद पर तुषार डेढ़ा के चुनाव परिणाम को नियमानुसार अमान्य घोषित करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

एक सत्र में दो जगह पढ़ाई नहीं कर सकते

मामले में सीबीएसई के आला अधिकारियों का कहना है कि एक सत्र में नियमित तौर पर दो जगह पढ़ना संभव नहीं है, सिर्फ साइड कोर्स ही किए जा सकते हैं। नियमित तौर पर पढ़ाई नहीं की जा सकती।

2021 में भारत और रूस ने द्विपक्षीय कारोबार को 25 अरब डालर का करने का जो लक्ष्य तय किया था, जो पूरा हो चुका है।

रक्षा उत्पादन में 'मेक इन इंडिया' का नया कीर्तिमान

देश में वर्ष 2023–24 में 1.27 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन

▸ भारत को वैश्विक रक्षा उत्पादन का केंद्र बनाने को प्रतिबद्ध : राजनाथ

▸ कहा, इससे हमारे हथियार बढ़ेंगे और हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे

2023-24 में कुल रक्षा उत्पादन में डीपीएसयूपीएसयू ने 79.2 प्रतिशत और निजी क्षेत्र ने 20.8 प्रतिशत उत्पादन किया है

16.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस बार रक्षा उत्पादन क्षेत्र के विकास में

राजनाथ सिंह। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के वार्षिक रक्षा उत्पादन ने 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में वर्ष 2023–24 में 1.27 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन हुआ। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार इस क्षेत्र के विकास में 16.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सिंह ने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता से विकासशील भारत के लिए एक अनुकूल शासन स्थापित कर रही है ताकि वह वैश्विक रक्षा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बने।

रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट में कहा कि इस साल रक्षा उत्पादन की कुल कीमत 1,26,887 करोड़ रुपये है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022–23 में 1,08,684 करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन हुआ था। उन्होंने रक्षा समेत भारतीय उद्योग जगत को बधाई देते हुए कहा कि इससे हमारे सुरक्षा औजार और हथियार बढ़ेंगे और हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सभी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र (डीपीएसयू) और अन्य रक्षा सामग्री के पीएसयू निर्माता और निजी कंपनियों ने देश के रक्षा उत्पादन में रिकार्ड 1,26,887 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। रक्षा उत्पादन के विकास की यह दर 16.8 प्रतिशत है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023–24 में कुल रक्षा उत्पादन में डीपीएसयूपीएसयू ने 79.2 प्रतिशत और निजी क्षेत्र ने 20.8 प्रतिशत उत्पादन किया है। उल्लेखनीय है कि रक्षा निर्यात ने वित्त वर्ष 2023–24 में रिकार्ड 21,083 करोड़ रुपये की बुलंदी हासिल कर ली। इसमें पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 32.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले पांच वर्षों (2019–20 से) रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता गया है और अब इसमें कुल 60 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हो चुका है।

भारतीय सेना को मिलीं 35 हजार एके–203 राइफलें

एके–203 असाल्ट राइफल। फाइल

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रूस यात्रा से पहले इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (आइआरपीएल) ने भारतीय सेना को 35 हजार एके–202 असाल्ट राइफलें सौंपने की जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि आइआरपीएल भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए भारत में राइफलों का निर्माण शुरू किया गया है। इस परियोजना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है।

इंडिया रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एके–203 क्लाश्निकोव असाल्ट राइफलें तैयार करने वाली परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है। ये राइफलें उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनी हैं। सभी आवश्यक उपकरण उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित कोरवा आयुध कारखाने को भेजे गए हैं।

रूस के साथ सैन्य सहयोग के मुकाबले कारोबार संतुलन पर होगी ज्यादा वार्ता

जयप्रकाश रंजन, जागरण

▸ रूस को फार्मा, कृषि व प्रौद्योगिकी का निर्यात बढ़ाना प्राथमिकता : क्वात्रा

▸ आठ और नौ जुलाई को रूस की यात्रा पर होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

विनय क्वात्रा। फाइल

नई दिल्ली : पिछले तीन वर्षों में भारत और रूस का द्विपक्षीय कारोबार चार अरब डालर से बढ़कर 65 अरब डालर का हो गया। 55 अरब डालर का व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में। इन्हीं तीन वर्षों में दोनों देशों के बीच हर वर्ष होने वाली न तो टू प्लस टू (विदेश व रक्षा मंत्रियों की) बैठक हुई है और न ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए गठित आयोग (आइआरआइजीसी–एमएंडएमटीसी) की बैठक हुई है। ये दोनों तथ्य बताते हैं कि पिछले तीन–चार वर्षों में भारत और रूस के बीच व्यापार में रक्षा की बजाय कच्चा तेल बढ़ा। आज भारत लगभग 55 अरब डालर का कच्चा तेल रूस से लेता है।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया, 'भारत–रूस के बीच होने वाली 22वीं शिखर बैठक में कारोबार संतुलन को बेहतर करना एक अहम प्राथमिकता होगी। पिछले वर्ष भारत ने रूस से 60 अरब डालर का आयात किया है, जबकि निर्यात सिर्फ पांच अरब डालर का रहा है। भारत की कोशिश रूस को फार्मा, खाद्य उत्पाद, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में निर्यात बढ़ाकर इस संतुलन को अपनी तरफ झुकाने पर होगी।' वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय कारोबार को 25 अरब डालर का करने का जो लक्ष्य वर्ष 2021 में तय हुआ था, वह पूरा हो चुका है। अब नया लक्ष्य तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 8–9 जुलाई को मास्को दौरे पर होंगे। दूसरे अधिकारी बताते हैं कि दोनों देश बदलते वैश्विक परिदृश्य को समझ रहे हैं, तभी इनके बीच सैन्य सहयोग को मजबूत बनाने को लेकर गठित समितियों की बैठकें भले ही नहीं हुई हों, लेकिन अप्रैल, 2023 में आर्थिक सहयोग पर गठित अंतर–सरकारी आयोग की बैठक जरूर हुई है। साथ ही अप्रैल, 2024 में मास्को में पहली बार भारत–रूस निवेश फोरम की बैठक हुई। रूबल–रुपये में कारोबार करने पर भी बात हुई, लेकिन अभी तक इसमें प्रगति नहीं दिखी है। क्वात्रा ने बताया कि भारत से ईरान व मध्य एशिया–रूस होते हुए यूरोप को कारोबारी मार्ग से जोड़ने की योजना भी काफी महत्वपूर्ण है जिस पर पुतिन–मोदी शिखर वार्ता में बात होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आगामी शिखर सम्मेलन में रक्षा सहयोग पर बात नहीं होगी। भारत को समय पर एस–400 की आपूर्ति, रूस से खरीदे गए रक्षा उपकरणों व युद्धक जहाजों के लिए कल–पुर्जों की आपूर्ति और भारत में हथियारों का सह–उत्पादन ऐसे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वात्रा का कहना है, 'भारत–रूस संबंधों में रक्षा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे और मजबूत बनाया जाएगा।' इसी तरह से शिखर सम्मेलन में रूस की सेना में गलत सूचना देकर भारतीयों की भर्ती करने का मुद्दा भी अहम होगा। क्वात्रा ने बताया कि तकरीबन 30–40 भारतीयों के रूस की सेना में यूक्रेन युद्ध के लिए भर्ती किए जाने की सूचना है। सरकार की कोशिश से 10 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है, जबकि इनकी भर्ती करने वाली भारतीय एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। दोनों नेताओं के बीच वार्ता में क्षेत्रीय एवं वैश्विक हित के मुद्दे भी एजेंडे में होंगे।

मान सरकार का नए कानूनों को पंजाबी में अनुवाद कराने के लिए केंद्र से आग्रह

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▸ कहा, लीगल रिमेबेरंस विभाग ने अनुवाद से खड़े किए हाथ

▸ तर्क दिया कि अनुवाद सही नहीं हुआ तो केसों को लेकर दिक्कतें आएंगीं

केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पंजाबी भाषा में नहीं है। पंजाब सरकार ने तीनों कानूनों को पंजाबी में अनुवाद कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

विभागीय अधिकारी ने कहा कि तीनों कानून संवेदनशील हैं, इसलिए जिस भी मंत्रालय की ओर से ये बनाए गए हैं, वही अनुवाद करे तो ही सही रहेगा। हमने केंद्र सरकार को लिखा है कि तीनों कानूनों का पंजाबी में अनुवाद करवाकर भेजा जाए। इससे पहले गृह मंत्रालय ने उन राज्यों जिनकी भाषाओं को मान्यता मिली हुई, से कहा था कि वे अपने स्तर पर तीनों ने कानूनों का अनुवाद करवा लें। पंजाब सरकार ने भी लीगल रिमेबेरंस विभाग को इसे भेजा था, लेकिन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। इसका कारण उन्होंने तकनीकी शब्द बताया और कहा कि चूंकि ये आपराधिक मामलों से जुड़े कानून हैं, इसलिए अगर इनका अनुवाद सही नहीं हुआ तो केसों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं।

काबिले गौर है कि इन कानूनों का सभी मान्यता प्राप्त 18 प्रांतीय भाषाओं में अनुवाद होना है। पंजाबी इनमें से एक है। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इसका अनुवाद कर लिया है और इसको पास करवाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा हुआ है। जिन राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी ज्यादा बोली या पढ़ी लिखी नहीं जाती है, वहां इन्हें लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में तैनात स्टाफ को केस दर्ज करने के लिए बार–बार अपने अधिकारियों से बात करनी पड़ रही है। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अगर तीनों कानून का पंजाबी में अनुवाद हो जाएगा तो इन्हें सही ढंग से लागू किया जा सकेगा।

केशव राव ने राज्य सभा से दिया इस्तीफा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस में शामिल होने के बाद के केशव राव ने राज्य सभा से इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राव 2020 से तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के राज्यसभा सदस्य थे। वह बुधवार को कांग्रेस में शामिल हुए और गुरुवार को संसद के उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ की ओर से शुक्रवार को उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बाद राज्यसभा में उनकी सीट खाली हो गई है। राव के इस्तीफे के बाद सदन में 16 सीटें खाली हो गई हैं। इससे पहले, राज्यसभा में 15 सीटें खाली थीं। इनमें जम्मू–कश्मीर से चार, महाराष्ट्र से तीन, असम और बिहार से दो–दो और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से एक–एक सीट खाली हैं।

सीतारमण से मिले चंद्रबाबू, आंध्र के लिए मांगी वित्तीय मदद

▸ पोलावरम परियोजना के लिए फंड, नई राजधानी के विकास के लिए भी मांगी मदद

▸ वित मंत्री सीतारमण ने आंध्र प्रदेश की मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान नायडू ने कर्ज के बोझ से दबे आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्रीय बजट पेश होने से कुछ ही सप्ताह पहले हुई है। नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देसम पार्टी राजग की महत्वपूर्ण सहयोगी है। लोकसभा में तेदेपा के 16 सांसद हैं।

सूत्रों ने बताया कि नार्थ ब्लाक में बैठक के दौरान नायडू ने राज्य के लिए और अधिक वित्तीय सहायता की मांग के कारणों को बताते हुए विस्तृत ज्ञापन सौंपा। आंध्र प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में बताया जिनके लिए केंद्रीय सहायता की तत्काल जरूरत है। राज्य सरकार के अनुसार, आंध्र प्रदेश का सार्वजनिक ऋण 2019–20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 31.02 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 33.32 प्रतिशत हो गया है।

नायडू की पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए फंड, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता और नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए मदद मांगी। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विभाजन से उत्पन्न लंबित मुद्दों के समाधान की भी मांग की।

सूत्रों के अनुसार सीतारमण ने नायडू की चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि वह आंध्र प्रदेश की मांगों पर विचार करेंगी। नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की।

इससे पहले नायडू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान नायडू ने आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी। उन्होंने अल्पकालिक वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए समर्थन, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और विशेष सहायता योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन की मांग भी की। नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी।

आंध्र को वैश्विक मानचित्र पर लाने का लिया संकल्पः चंद्रबाबू ने आंध्र को अगले पांच वर्षों में विश्व मानचित्र पर लाने के लिए शुक्रवार को रोडमैप पेश किया। राष्ट्रीय राजधानी के अपने दो दिवसीय दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेदेपा प्रमुख ने कहा, हम केंद्र से राज्य के पुनर्निर्माण में मदद मांग रहे हैं। हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा। उन्होंने जो भी पेशकश की, हमने खुशी से स्वीकार कर लिया।

नायडू ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। नायडू ने कहा कि नया सचिवालय, विधानसभा और हाई कोर्ट सहित प्रमुख सरकारी इमारतों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। सीएम ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल ने कौशल जनगणना को मंजूरी दे दी है। उद्योग की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम हर परिवार से उद्यमी बनाएंगे। नायडू ने कहा, गोदावरी नदी का लगभग 3,000 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है। यदि हम उस पानी का उपयोग कर सकें तो चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने कृष्णा और गोदावरी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। राजग के साथ तेदेपा के संबंधों को लेकर नायडू ने कहा, हमने केंद्र से कोई मंत्री पद नहीं मांगा, यहां तक कि वाजपेयी के समय में भी नहीं। जो भी पेशकश की गई, हमने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने का वादा किया।

कर्नाटक के राज्यपाल की युवाओं से धर्म–संस्कृति संरक्षित करने की अपील

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को जैन दर्शन में अहिंसा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से धर्म एवं संस्कृति को अपनाने और उसे संरक्षित करने की अपील की।

राज्यपाल ने बेंगलुरु में अखिल भारतीय जैन मंच की ओर से आयोजित समारोह में 'जैन पुराण भाग–3 आचार्य चरित्र' पुस्तक का विमोचन करने के बाद लोगों को संबोधित किया। राज्यपाल ने पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म, संस्कृति, रीति–रिवाजों और परंपराओं को आगे बढ़ाने में धार्मिक साहित्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समाज को संगठित रखने में धर्म के महत्व और धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रुझान रखने वाले व्यक्तियों पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया।

राज्यपाल थावरचंद ने 'जैन पुराण भाग–3' पुस्तक को सभी के लिए उपयोगी बताया एवं अखिल भारतीय जैन मंच, बेंगलुरु के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं परोपकारी कार्यों की सराहना भी की।

'सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने के लिए शासनादेश की जरूरत नहीं'

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज

▸ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुच्छेद 141 के तहत पूरे देश में लागू

▸ 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर इंक्रीमेंट के अधिकार का मामला

▸ अधिकारी इन्कार करने का आदेश वापस लें या अपनी सफाई दें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुच्छेद 141 के तहत पूरे देश में लागू है। यह जब तक कायम है, सभी पर बाध्यकारी है। किसी सरकार या विभाग को विपरीत रुख अपनाने का अवसर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने अथवा लागू करने के लिए किसी शासनादेश की जरूरत नहीं होती, आदेश स्वतः लागू होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 30 जून को सेवानिवृत्त होने वालों को एक काल्पनिक वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) देने संबंधी आदेश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा शासनादेश जारी करने की सराहना नहीं की जा सकती। विभाग को 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट देने से इन्कार करने का अधिकार नहीं है।

इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को अपना प्रश्नगत आदेश एक सप्ताह में वापस लेने अथवा जवाबी हलफनामा दायर कर कारण बताने को कहा है कि क्यों न भारी हर्जाने के साथ उनका आदेश रद करते हुए काल्पनिक इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया जाए। साथ ही हर्जाना राशि की वसूली उस अधिकारी के वेतन से क्यों न की जाए। प्रकरण में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश प्रताप सिंह व 12 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव पर्यावरण व वन, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, विभागाध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज व डायरेक्टर वित्त एवं पेंशन को भेजने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने याची की तरफ से बहस की।

अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद ने ली सांसद पद की शपथ

नई दिल्ली, प्रेट्र: खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद शेख अब्दुल रशीद ने शुक्रवार को सांसद के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के लिए दोनों को पैरोल दी गई थी। ब्दुल रशीद को इंजीनियर रशीद के रूप में भी जाना जाता है। वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है।

निर्वाचित सांसदों ने लोस अध्यक्ष के कक्ष में शपथ ली। अमृत पाल व रशीद ने जेल में रहते हुए क्रमशः पंजाब के खडूर साहिब व जम्मू–कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता है। शपथ लेने के लिए रशीद को तिहाड़ से संसद तक की यात्रा के समय को छोड़कर दो घंटे की हिरासत पैरोल दी गई थी, और अमृतपाल को असम से दिल्ली और वापस यात्रा के मद्देनजर पांच जुलाई से चार दिन की हिरासत पैरोल दी गई थी।

राष्ट्रपति ने प्रदान किए 10 कीर्ति व 26 शौर्य चक्र

▸ सात कीर्ति चक्र और सात शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए

▸ राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में किए प्रदान, पीएम भी रहे मौजूद

नई दिल्ली में शुक्रवार को रक्षा अलंकरण समारोह–2024 (चरण–1) में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सेना चिकित्सा कोर, 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन अंशुमान सिंह को (मरणोपरांत) कीर्ति चक्र स्वजन को प्रदान किया। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए, इनमें सात मरणोपरांत हैं। राष्ट्रपति ने 26 शौर्य चक्र भी प्रदान किए और इनमें भी सात मरणोपरांत हैं। अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र देश में शांतिकाल का दूसरा और शौर्य चक्र तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिसकर्मियों को ये अलंकरण प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं की सूची के अनुसार, भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की 55वीं बटालियन में ग्रेनेडियर्स के सिपाही पवन कुमार; पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह; पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) की 9वीं बटालियन के हवलदार अब्दुल मजीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। सीआरपीएफ की 210 कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राज कुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा और कांस्टेबल शंभू राय को भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इनके अलावा मेजर रैंक के दो अधिकारियों एवं एक नायब सूबेदार को भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं, छह सैन्यकर्मियों के अलावा जम्मू–कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही सेना, वायुसेना, नौसेना और गृह मंत्रालय के अधीन सेवाएं देने वाले कर्मियों के एक समूह को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रपति भवन ने बाद में अपने एक्स हैंडल पर समारोह की तस्वीरें साझा कीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह–2024 (चरण–1) में शामिल हुआ, जहां राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार प्रदान किए।

हमारे राष्ट्र को अपने बहादुर सैनिकों की वीरता और समर्पण पर गर्व है। वे सेवा और बलिदान के उच्चतम आदर्शों के उदाहरण हैं। उनका साहस हमेशा लोगों को प्रेरित करेगा।" प्रधानमंत्री ने भी समारोह की तस्वीरें साझा कीं।

भागीदारी बढ़ाने का प्रयास

नई लोकसभा में बढ़ी संख्या का विपक्ष को मिलेगा फायदा, बढ़ेगी भागीदारी, पीएसी की कमान कांग्रेस को मिलना तय, सपा, तृकां व द्रमुक को एक–एक समिति की मिलेगी कमान

विदेश, वित्त, रक्षा संबंधी संसदीय समितियों की कमान पर जोर लगाएगा विपक्ष

संजय मिश्र ● जागरण

24 स्थायी समितियों के गठन पर विपक्षी खेमे में सरगर्मी शुरू

नई दिल्ली: 18वीं लोकसभा में संख्या बल में वृद्धि का विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए को संसदीय स्थायी समितियों में फायदा मिलेगा। परंपरानुसार सबसे महत्वपूर्ण लोकलेखा समिति (पीएसी) की अध्यक्षता मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मिलनी तय है। वहीं विपक्षी दलों की रणनीति इस बार विदेश, रक्षा व वित्त मंत्रालय से संबंधित अहम संसदीय समितियों की कमान भी अपने हाथ में लेने की है। पिछली लोकसभा में सत्तारूढ़ भाजपा ने इन तीनों समितियों की अध्यक्षता अपने पास रखी थी। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक जैसे विपक्षी दलों को भी इसका फायदा मिलेगा और इन दलों को कम से कम एक–एक स्थायी समिति की अध्यक्षता मिलनी तय है।

संसदीय समितियों के गठन को लेकर लोकसभा स्पीकर की ओर से अलग–अलग समितियों के लिए जल्द ही नाम मांगे जाएंगे। इसके मद्देनजर आइएनडीआइए में शामिल सभी दलों के नेताओं के बीच अनौपचारिक मंत्रणाओं का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी सूत्रों ने कहा, जहां तक विपक्षी सदस्यों की समितियों में भागीदारी की बात है तो आनुपातिक भागीदारी का फार्मूला है जिसकी वजह से इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सत्तापक्ष व विपक्ष में रस्साकसी की आशंका सिर्फ वित्त, रक्षा, विदेश व सार्वजनिक विभागों से संबंधित समितियों की अध्यक्षता को लेकर ही है। भाजपा सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में वित्त व विदेश मंत्रालय की स्थायी समितियों की अध्यक्षता विपक्ष को नहीं मिली थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, इन दोनों समितियों को अध्यक्षता मुख्य विपक्षी दल को देने की परंपरा रही थी जिसे पिछली बार तोड़ा गया। इस बार हम इसे बहाल करने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार, मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार के दोनों कार्यकाल में विभागों संबंधी समिति की अध्यक्षता विपक्ष को दी गई थी। इसलिए इस बार विपक्ष की सदन में संख्या को देखते हुए सत्तापक्ष पिछली लोकसभा की तरह अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा।

मंत्रालयों–विभागों से संबंधित संसद की 24 स्थायी समितियां हैं जिनमें 16 लोकसभा तथा आठ राज्यसभा की हैं। संख्या बल के आधार पर सत्तापक्ष को 14 तो विपक्ष को 10 समितियों की कमान मिलने की संभावना है। वित्त, विदेश, रक्षा के साथ पीएसी लोकसभा की है जिनमें इस सदन के 15 और राज्यसभा के सात सदस्य होते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति (एस्टिमेट कमेटी) के सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसकी अध्यक्षता सत्तारूढ़ दल के पास होती है।

संसद में 1968 में इंदिरा गांधी के पीएम के पहले कार्यकाल में पीएसी बनी और तभी से इसकी अध्यक्षता विपक्ष को देने की परंपरा रही है। पिछली लोकसभा में कांग्रेस को आधिकारिक विपक्ष का दर्जा हासिल नहीं था पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता के रूप में उसके नेता अधीर रंजन चौधरी ने पांच वर्ष तक लोकलेखा समिति की अध्यक्षता की। पीवी नरसिंह राव की सरकार के दौरान भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी भी पांच वर्ष तक पीएसी के अध्यक्ष रहे थे। गृह मंत्रालय, शिक्षा, कानून व न्याय, सड़क परिवहन, पर्यटन,संस्कृति व स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित स्थायी समितियां राज्यसभा की हैं, मगर इनमें भी दोनों सदनों की संख्या के हिसाब से आनुपातिक भागादारी होती है जिनमें लोस के 15 व रास के सात सदस्य शामिल हैं। 17वीं लोकसभा में गृह मंत्रालय की समिति की अध्यक्षता राज्यसभा में कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा को मिली थी।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

****

भाजपा ने बनाए 24 राज्यों के प्रभारी, तावड़े को बिहार तो पूनिया को हरियाणा का जिम्मा

पंजाब के प्रभारी होंगे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, झारखंड में बने रहेंगे बाजपेयी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विनोद तावड़े।

सतीश पूनिया।

विजय रूपाणी।

लक्ष्मीकांत बाजपेयी।

राधा मोहन दास।

प्रकाश जावड़ेकर।

लोकसभा चुनाव में तीसरी बार विजय प्राप्त करने के साथ ही भाजपा ने संगठन को नए सिरे से चुस्त-दुरुस्त करने की प्रक्रिया पर काम तेज कर दिया है। जगत प्रकाश नड्डा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रही अटकलों के बीच पार्टी ने 24 राज्यों में प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इनमें कुछ राज्यों में वरिष्ठ नेताओं का प्रभार बरकरार रखा है तो बाकी राज्यों में चेहरे बदले गए हैं। संगठनात्मक अनुभव और दूसरे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हरियाणा की कमान राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपी गई है। बिहार में जहां अगले वर्ष चुनाव होने हैं, वहां पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को जिम्मेदारी सौंपी है।

भाजपा ने 24 राज्यों में प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति का आदेश शुक्रवार को जारी किया। दिल्ली के निकटवर्ती हरियाणा में कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव हैं। वहां चुनौतियां भी हैं, जिनसे निपटने के लिए पार्टी ने पिछले दिनों वहां का चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया और अब प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया को बनाया है। उनके साथ सह-प्रभारी की जिम्मेदारी गुर्जर समुदाय से आने वाले सांसद सुरेंद्र सिंह नागर संभालेंगे। इसी वर्ष झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। अभी महाराष्ट्र को लेकर तो कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड में हाईकमान ने संगठन के अनुभवी सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी को प्रभारी बनाए रखा है। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को फिर प्रभारी बनाया गया है तो सह-प्रभारी आशीष सूद होंगे। बिहार में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हैं। उत्तर भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य के लिए पार्टी ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता व राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर विश्वास जताया है। उनके साथ सह-प्रभारी के रूप में दीपक प्रकाश काम करेंगे। मध्य प्रदेश में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में वहां भी बदलाव न करते हुए उत्तर प्रदेश के तेजतर्रार नेता डा. महेंद्र सिंह को प्रभारी पद पर बनाए रखा है और सह-प्रभारी सतीश उपाध्याय को बनाया गया है। पंजाब भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण राज्य है। यहां गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी प्रभारी का दायित्व संभालेंगे, जबकि डा. नरिंदर सिंह सह-प्रभारी के रूप में सहयोग करेंगे।

दक्षिण में विस्तार पर भाजपा की नजरें हैं। ऐसे में कर्नाटक में फिर से राष्ट्रीय महासचिव डा. राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है तो सुधाकर रेड्डी सह-प्रभारी होंगे। केरल की कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दी गई है। उनके साथ अपराजिता सारंगी सह-प्रभारी होंगी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को फिर प्रभारी बनाया गया है तो चंडीगढ़ के दिग्गज नेता संजय टंडन को सह-प्रभारी बनाया गया है। ओडिशा में सरकार बना चुकी भाजपा ने वहां बतौर प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर और सह-प्रभारी के रूप में लता उसेंडी को जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम बनाए गए हैं। सह-प्रभारी रेखा वर्मा बनी हैं। ओडिशा से लोकसभा चुनाव जीतने वाले डा. संबित पात्रा को पार्टी ने उत्तर-पूर्व प्रदेश का संयोजक तो वी. मुरलीधरन को सह-संयोजक बनाया है। इसके अलावा अंडमान-निकोबार में रघुनाथ कुलकर्णी, अरुणाचल प्रदेश में अशोक सिंघल, छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन, दादरा एवं नगर हवेली और दमन-द्वीव में दुष्यंत पटेल, को प्रभारी बनाया गया है।

तेलंगाना में बीआरएस के छह एमएलसी कांग्रेस में शामिल

हैदराबाद, प्रेट्र : तेलंगाना में के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) की भारत राष्ट्र समिति को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गुरुवार की रात बीआरएस के छह एमएलसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीआरएस के एमएलसी के पार्टी छोड़ने का क्रम जारी है। राजधानी दिल्ली से दो दिवसीय यात्रा से गुरुवार की रात लौटने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निवास पर ही बीआरएस के इन एमएलसी को कांग्रेस में शामिल कराया गया। कांग्रेस में शामिल होने वाले छह एमएलसी में दांडे विट्ठल, भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, बोग्गरापु दयानंद, येग्गे मल्लेशम और बसवाराजू सरैया शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेड्डी, तेलंगाना में एआइसीसी प्रभारी दीपा दासमुंशी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में बीआरएस के एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए।

बीआरएस एमएलसी के दलबदल के बाद केटी रामाराव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, बीआरएस सांसद केशव राव ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनके फैसले का स्वागत है। लेकिन उन बीआरएस विधायकों का क्या जिन्होंने हारने के बावजूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन आधे दर्जन बीआरएस विधायकों का क्या जो दलबदल कर कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी क्या आप ऐसे ही संविधान को कायम रखेंगे।...ये कैसा न्यायपत्र है।

19 अगस्त के बाद किसी भी समय हो सकता है विस चुनाव का एलान

जम्मू-कश्मीर

राज्य ब्यूरो, जागरण● श्रीनगर

- चुनाव आयोग ने 10 को निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारियों की बुलाई बैठक
- गैर पंजीकृत दलों से चुनाव चिह्न के आवंटन के लिए आमंत्रित किए गए हैं आवेदन
- मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी, 20 अगस्त को होना है सूचियों का अंतिम प्रकाशन

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी जिला चुनाव अधिकारियों की एक बैठक 10 जुलाई को बुलाई है। बैठक में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग 19 अगस्त के बाद किसी भी समय चुनाव का ऐलान कर सकता है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में जारी श्री अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी।

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव संबंधी तैयारियों को गति देते हुए गैर पंजीकृत दलों से चुनाव चिह्न के आबंटन के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा प्रदेश में मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेश में अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 20 अगस्त को होना है। बता दें कि वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये होने वाली इस बैठक में प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) की भूमिकाओं व तैनाती की मौजूदा स्थिति और घर-घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन की प्रगति की व्यापक समीक्षा

की जाएगी।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में इससे पहले विधानसभा चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे। जून 2018 में तत्कालीन भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार गिर जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहले राज्यपाल और 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित होने के बाद से यहां उपराज्यपाल का शासन लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर, 2024 से पहले विधानसभा के गठन के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीते माह कहा था कि जम्मू-कश्मीर में लोग जल्द अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

केरल में एसएफआइ को लेकर एलडीएफ में टकराव

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल में छात्र संगठन एसएफआइ को लेकर सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाकपा पर पलटवार करते हुए माकपा नेता एके बालन ने शुक्रवार को कहा कि एलडीएफ के अंदर या बाहर किसी को भी छात्र संगठन एसएफआइ को नष्ट नहीं करने देंगे। इससे पहले गुरुवार को भाकपा के राज्य सचिव बिनाय विश्वम ने कहा था कि स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) ने अपने तौर-तरीके नहीं बदलता तो यह राज्य में वाम मोर्चे के लिए बोझ बन जाएगा। एसएफआइ कार्यकर्ताओं को छात्र आंदोलन के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। वे अपनी राजनीतिक विचारधारा नहीं जानते। वे वाम मोर्चे के दायित्वों के बारे में भी नहीं जानते। इस बीच बिनाय विश्वम ने शुक्रवार को फिर कहा कि छात्र संगठन को अपना व्यवहार सुधारना चाहिए।

विस उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री के इस्तीफे से बच रही भाजपा

नरेंद्र शर्मा● जागरण

- राजस्थान में पांच सीटों पर होने वाले हैं विधानसभा उपचुनाव, तीन सीटों पर मीणा का प्रभाव

जयपुर : राजस्थान में कृषि मंत्री डा. किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार करने से भाजपा बच रही है। मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद डा. किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दस दिन बाद फिर बुलाया है। कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व संगठन से कोई नाराजगी नहीं है। विश्वस्त नेताओं का कहना है कि मीणा ने राष्ट्रीय नेतृत्व को सत्ता व संगठन में कम महत्व मिलने पर नाराजगी के बारे में बताया है।

दरअसल, मंत्रिमंडल गठन के समय कम महत्व के विभाग मिलने और लोकसभा चुनाव में छोटे भाई को टिकट नहीं दिए जाने से मीणा प्रदेश नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि यदि पूर्वी राजस्थान की एक सीट पर भी भाजपा की हार हुई तो वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे।

किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए। एएनआइ

सूत्रों के अनुसार पांच विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगा। पांच में से तीन सीटों पर मीणा का प्रभाव है। यदि मीणा का इस्तीफा स्वीकार हो गया तो इसका असर उपचुनाव पर भी दिखेगा।

कर्नाटक कांग्रेस में कलह बढ़ने की आशंका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा भ्रष्टाचार पर सीधे मुख्यमंत्री को बना रही निशाना, उपमुख्यमंत्री खेमे में चुप्पी
- कर्नाटक में तीन उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव कथित रूप से उपमुख्यमंत्री के खिलाफ
- मुख्यमंत्री सिद्दरमैया का खेमा अहिंदा की रैली कर शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है

कर्नाटक में पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। तब वरिष्ठ नेता सिद्दरमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सामने आई खींचतान को बेशक हाईकमान ने दबाते हुए सिद्दरमैया को सीएम और शिवकुमार डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन उन छिपी दरारों से असंतोष लावा का रह-रहकर बाहर आ रहा है। अभी सरकार बने एक वर्ष ही हुआ है कि अंदरूनी कलह तेज होने लगी है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को कमजोर बताकर प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार को घेरने की कोशिश हो रही है और इसी क्रम में तीन अन्य उपमुख्यमंत्री बनाने की बात हुई। वहीं शिवकुमार खेमा मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर चुप्पी साधे हुए है। जबकि भाजपा ने अभियान तेज कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र मुख्यमंत्री के आवास तक का घेराव करने लगे हैं।

यह किसी से नहीं छिपा है कि राज्य में बड़ी जीत के बावजूद मुख्यमंत्री तय करने में कांग्रेस को नाकों चने चबाना पड़ा था। सिद्दरमैया इसलिए भारी पड़े थे क्योंकि उनकी छवि भी अच्छी थी और अहिंदा (अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित) के बीच उनकी पकड़ ज्यादा मानी जाती है। अब जबकि प्रदेश में भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को लेकर भाजपा ने अभियान तेज कर दिया है और निशाने पर सीधे सिद्दरमैया हैं तो कांग्रेस के अंदर की हलचलें भी तेज हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की पत्नी के नाम से मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन का मामला तूल पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री भले ही इस आवंटन को भाजपा कार्यकाल के दौरान हुई वैध प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस सरकार की घेरेबंदी शुरू कर दी है। आरोप है कि मुख्यमंत्री इस घोटाले के आरोपित अधिकारियों को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर.अशोक के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी अब इस आंदोलन को राज्यभर में लगातार करने का मन बना चुकी है। सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस के अंदर सिद्दरमैया के विरोधियों की भी नजर भाजपा के अभियान पर है। इस बीच, सिद्दरमैया खेमा शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। सिद्दरमैया के 75वें जन्मदिन पर 12 अगस्त को बड़ी रैली करेंगे जिसमें अहिंदा का समर्थन दिखाया जाएगा।

बंगाल में माकपा को जनमत संग्रह अभियान में मिले हजारों ईमेल

राज्य ब्यूरो, जागरण● कोलकाता : बंगाल में माकपा को अपने जनमत संग्रह अभियान में अब तक हजारों ईमेल मिले हैं, जिनमें पिछले लोकसभा (लोस) चुनाव में पार्टी की बुरी हार के कारण गिनाए गए हैं। कुछ ने हार के पीछे पार्टी की सांगठनिक दुर्बलता बताई है तो कुछ ने पार्टी नेताओं का जनता से संपर्क नहीं होना। वहीं कुछ ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।

मालूम हो कि बंगाल में हाशिए पर आ चुकी माकपा अपने पुनरुत्थान के लिए जनमत संग्रह कर रही है। माकपा नेता लोगों से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पार्टी पर पहले जैसा भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वे पार्टी में क्या खामियां देख रहे हैं और आने वाले समय में उनकी पार्टी से क्या अपेक्षाएं हैं। माकपा आम लोगों के साथ-साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों का मत भी संग्रह कर रही है। मालूम हो कि 2019 की तरह 2024 के लोस चुनाव में भी बंगाल में पार्टी का खाता नहीं खुल पाया।

अगस्त के बाद गिर जाएगी नरेन्द्र मोदी सरकार : लालू

बिहार की हलचल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

- सबसे कमजोर कार्यकाल साबित होगा इस सरकार का : तेजस्वी
- विधायकों को चेतावनी- कमजोर विधायक होंगे बेटिकट

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। लालू के अनुसार मोदी की सरकार इसी साल अगस्त के बाद गिर जाएगी। जबकि तेजस्वी ने कहा कि मोदी अपना यह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। दोनों शुक्रवार को राजद के 28 वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्रसाद ने कहा कि राजद को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी ने कहा कि वह इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। पार्टी अपनी विचारधारा पर चलेगी। अगर लोकसभा चुनाव में बिहार से महागठबंधन के सांसदों की संख्या आठ-दस और बढ़ जाती तो मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। प्रचारित किया गया था कि मोदी को कोई परास्त नहीं कर सकता है। मोदी का तीसरा कार्यकाल उनके पूर्व के दो कार्यकाल की तुलना में काफी कमजोर है। संसद में मोदी का मजबूत विपक्ष से मुकाबला हो रहा है। वैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर अफसोस करने की जरूरत नहीं है।

पटना में शुक्रवार को राजद के 28वें स्थापना दिवस समारोह में पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद को चांदी का मुकुट पहनाया गया। प्रेट्र

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हमें अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी। कहा कि विधानसभा चुनाव में दल बदलुओं और राजद के प्रति संदिग्ध आस्था वाले लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। टिकट देते समय जीत और पार्टी के प्रति निष्ठा का ध्यान रखा जाएगा। यह भी देखेंगे कि उम्मीदवार की अपनी ताकत है या नहीं। इस दौरान वर्तमान विधायकों का टिकट काटने से भी हम परहेज नहीं करेंगे। बड़े से बड़े नेता भी इसके दायरे में आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को 16 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 78-80 है। तेजस्वी ने नौकरियां दी हैं। हमें भरोसा है कि बिहार का नौजवान किसी भी जाति और धर्म का हो, हमारे दल को वोट देगा।

नायडू-नीतीश की कृपा पर चल रही केंद्र की मोदी सरकार : रामगोपाल

जासं, इटावा : सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा पर चल रही है। दोनों जिस दिन खिलाफ हो जाएंगे उस दिन सरकार गिर जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो केंद्र सरकार नहीं चल पाएगी। ये दोनों नेता अपने-अपने राज्यों में विशेष पैकेज की मांग करने में लगे हैं। यह मुद्दा केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आइएनडीआइ गठबंधन को बड़ी कामयाबी मिल सकती है।

मछली टेबल पर रख बिहार में वीआइपी प्रमुख ने की बैठक

जासं, भागलपुर : बिहार के भागलपुर में वीआइपी (विकासशील इंसान पार्टी) प्रमुख मुकेश सहनी ने शुक्रवार को गंगा की लहरों के बीच क्रूज पर 43 किलो की कतला मछली टेबल पर रखकर बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी से ही जुट जाएं। मेरा कर्म और धर्म मछली मारना, बेचना और खाना है। मेरे साथ मछली देखकर कई लोग परेशान हो जाते हैं। मैं मछुआरा का बेटा हूं। इस लोकसभा चुनाव में भले पार्टी ने सीट नहीं जीती हो, लेकिन वीआइपी का ही नहीं बल्कि महागठबंधन का वोट शेयर बढ़ा है, जो आने वाले चुनाव के लिए शुभ संकेत है।

उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अभी भी निषाद आरक्षण की है। जब तक बिहार, झारखंड और यूपी में निषादों को आरक्षण नहीं मिल जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज देश और बिहार की वर्तमान सरकार से जनता ऊब गई है।

तीर्थ यात्रा के सहारे दिल्ली में एससी से जुड़ाव बढ़ाएगी भाजपा

संतोष कुमार सिंह● जागरण

- विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी ने बनाई रणनीति
- लोकसभा में इस वर्ग का समर्थन मिलने से उत्साहित है पार्टी

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में सभी सातों सीटें जीतने के बाद भाजपा अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के लिए भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन चाहिए। परंतु, अनुसूचित जाति (एससी) के बीच कमजोर पकड़ पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इसे ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की जा रही है। इनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए इस वर्ग की महिलाओं के लिए निश्शुल्क तीर्थ यात्रा कराने का निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस वर्ग का समर्थन मिल जाता है, परंतु विधानसभा और नगर निगम चुनावों में निराशा हाथ लगती है। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 विधानसभा क्षेत्रों में से नौ में बढ़त बनाई थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस वर्ग का इन क्षेत्रों में अच्छा समर्थन मिला था, परंतु उसके बाद वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव व उसके बाद वर्ष 2022 में हुए निगम चुनाव में पार्टी को निराशा हाथ लगी थी।

पिछले दो विधानसभा चुनाव से पार्टी एक भी आरक्षित सीट नहीं जीत सकी है। पहले की तुलना में निगम में भी इसके अनुसूचित जाति से संबंधित पार्षदों की संख्या बहुत कम हो गई है। 2017 के निगम चुनाव में इसे आरक्षित 46 वार्डों में से 21 में जीत मिली थी। 2022 में यह कम होकर छह (अब 42 आरक्षित वार्ड हैं।) तक सिमट गई।

जीत का 'जायका' तैयार कर गए शिवराज

झारखंड

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं संग बैठक कर चुनाव पर की चर्चा, हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी को अवसर की तरह ले रही भाजपा, अब भ्रष्टाचार पर और मुखर होगा विरोध

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने तीन महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में अंतिम रूप दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को एक साथ बिठाकर शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी की एकजुटता का संदेश भी दिया। बाद में इस बैठक में प्रदेश के अन्य नेता भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने को भाजपा एक अवसर की तरह देख रही है। चुनाव प्रभारी ने भी सोरेन सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को मुखरता से उठाने का निर्देश दिया। दो दिनों के प्रवास में शिवराज सिंह चौहान ने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं के घर भोजन और जलपान किया। उन्होंने झारखंड के स्थानीय भोजन को सुस्वादु बताते हुए स्पष्ट किया कि अब विधानसभा जीतने के लिए जायका तैयार कर लिया गया है।

इधर, शनिवार से प्रारंभ होने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान और विजय संकल्प सभा में पूरा जोर लगाने का निर्देश प्रदेश चुनाव प्रभारी ने दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर से यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय सांसद, लोकसभा में हारे हुए प्रत्याशी और मंडल स्तर तक के नेताओं की उपस्थिति को अनिवार्य बनाया गया है। छह से 15 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन हजारीबाग में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे और विधानसभा चुनाव जीतने का संकल्प दिलाएंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का रामगढ़ के सुगिया गांव में ग्रामीणों ने शुक्रवार को पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। एएनआइ

हेमंत सोरेन के पास विधायकों का पर्याप्त आंकड़ा, सोमवार को बहुमत परीक्षण

राज्य ब्यूरो, जागरण● रांची

- 44 विधायकों का समर्थन है सरकार के साथ, 39 विधायक चाहिए सामान्य बहुमत के लिए
- आठ जुलाई को सदन में बहुमत साबित करेंगे हेमंत सोरेन, बुलाया गया है विशेष सत्र

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को विधानसभा में बहुमत साबित करने वाले हैं। जेल से जमानत पर बाहर निकलने के बाद एक दिन पहले ही उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र आठ जुलाई को बुलाने की घोषणा की गई। इस दिन सदन में हेमंत सोरेन विश्वास मत हासिल करेंगे। हालांकि हेमंत के समक्ष विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन्हें पहले से ही पर्याप्त संख्या में विधायकों का समर्थन और बहुमत हासिल है।

झारखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 81 है। चार विधायकों ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव जीतक सांसद बनने के बाद विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी और नलिन सोरेन एवं भाजपा के मनीष जायसवाल और ढुलु महतो शामिल हैं। इसके अलावा जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक रहीं सीता सोरेन ने भाजपा में शामिल होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अभी विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 76 है। इसमें सामान्य बहुमत के लिए 39 विधायकों का समर्थन सरकार को चाहिए। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को 44 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। यह भी उल्लेखनीय है कि झामुमो के दो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा अनुशासनहीनता की कार्रवाई के कारण निलंबित हैं। इसके बावजूद बहुमत से अधिक का आंकड़ा सरकार के पक्ष में है। दोनों गठबंधन के विधायकों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। मांडू से भाजपा के विधायक जेपी पटेल भी गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक में सम्मिलत हुए थे। उनका साथ भी सरकार को मिलेगा। हेमंत बहुमत परीक्षण के बाद मंत्रिमंडल गठित करेंगे। मंत्रिमंडल में ज्यादा फेरबदल की संभावना नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन सभी विधायकों को शामिल किया जाएगा, जो चम्पाई कैबिनेट में थे। लातेहार के विधायक बैद्यनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चम्पाई सोरेन मंत्रिमंडल में वह मंत्री बनने से चूक गए थे।

हेमंत सोरेन। फाइल

****

23 जून को आयोजित होने वाली नीट-पीजी की परीक्षा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 जून को स्थगित कर दी थी। उसके बाद से ही मेडिकल के छात्र परीक्षा जल्द आयोजित करने के लिए गुहार लगा रहे थे।

बिहार में पुल गिरने के मामलों में 11 और इंजीनियर निलंबित

कार्रवाई ▸ नीतीश सरकार ने संबंधित निर्माण एजेंसी को आगे काम न देने का निर्णय लिया

तीन गिरे पुल किस विभाग के, जिलों से जुटाई जा रही है जानकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

बिहार के सारण और सिवान में जल संसाधन विभाग के छह पुल गिरने के बाद एक्शन में आई नीतीश कुमार की सरकार ने 11 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही निर्माण में लगी एजेंसी को आगे कोई काम न देने का निर्णय भी लिया है। यह जानकारी शुक्रवार को विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने एक प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान दी। बता दें कि बीते एक पखवाड़े में कुल 12 पुल गिरे या ध्वस्त हो चुके हैं।

विकास आयुक्त के अनुसार इस मामले में दो कार्यपालक अभियंता चार सहायक अभियंता और पांच कनीय अभियंता निलंबित किए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग चार इंजीनियरों को पहले ही निलंबित कर चुका है। यह कार्रवाई उड़नदस्ता की जांच के बाद की गई है। उन्होंने बताया कि तीन और चार जुलाई के बीच एक ही योजना गंडक-छाड़ी नदी जोड़ योजना से जुड़े छह पुल गिरे थे। ये योजना गंडक-अकाली नाला (छाड़ी)-गंडकी-माही-गंगा नदी जोड़ योजना का हिस्सा है। गिरे पुलों के स्थान पर नए पुलों के निर्माण के लिए पुल निर्माण निगम से मदद मांगी गई है। उन्होंने कहा कि ध्वस्त पुलों के स्थान पर नए पुलों के निर्माण की राशि संबंधित एजेंसी से वसूली जाएगी।

उन्होंने कहा कि बीते एक पखवाड़े में छह पुल जल संसाधन विभाग के और तीन ग्रामीण कार्य विभाग के गिरे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तीन पुल किसके हैं, इसकी जानकारी जिलों से ली जा रही है। फिर आगे की कार्रवाई होगी। इन नौ पुलों में छह पुल पुराने और तीन निर्माणाधीन थे। ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि उनके विभाग के तीन पुल ध्वस्त हुए हैं। अररिया में बकरा नदी पर 18 जून को पुल गिरने के मामले में चार अभियंता को निलंबित किया गया, जबकि दो पहले से निलंबित थे।

उन्होंने कहा कि 23 जून को पूर्वी चंपारण में घोड़ासहन में गिरे पुल पर मानसून अवधि में काम कराए जाने की जानकारी सामने आई है। जिसके बाद एजेंसी से जवाब मांगा गया है। पूछा गया है कि 15 जून से काम पर रोक के बावजूद ढिलाई क्यों की गई। इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। इसी तरह 26 जून को मधुबनी में निर्माणाधीन पुल पर भी मानसून अवधि में काम करने का आरोप है।

पश्चिम चंपारण में रेलिंग समेत पुलिया का आधा हिस्सा ध्वस्त

जासं, शनिचरी (पश्चिम चंपारण)

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुअरवा मे रेलिंग समेत ध्वस्त पुलिया को देखते ग्रामीण। जागरण

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बहुअरवा गांव के समीप गुरुवार की देर रात रेलिंग समेत पुलिया का आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया। पुलिया का निर्माण लगभग 50 वर्ष पूर्व कराया गया था। यह सड़क बहुअरवा से मठिया रसूलपुर होते हुए बासोपट्टी हाई स्कूल तक जाती है। अब हाई स्कूल मे पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

मुखिया नजमा खातून ने बताया कि इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दी गई है। इसे दुरुस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। योगापट्टी के अंचलाधिकारी प्रज्ञा नयनम ने बताया कि पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है। तिरहुत नहर से निकली उपवितरणी पर यह पुलिया बनी थी। जांच कर वरीय अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

मालूम हो कि पिछले एक माह से बिहार में पुल-पुलियों का गिराना लगातार जारी है। पहले इसका कारण मानसूनी बारिश के कारण पानी का तेज बहाव बताया जाता रहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है।

पीएचईडी की 4436 करोड़ रुपये की निविदाएं रद, फिर होगी प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

- विभागीय मंत्री नीरज बोले, महागठबंधन सरकार के दौरान निविदा आवंटन में हुई थी गड़बड़ी
- जांच लगभग पूरी, दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों-इंजीनियरों के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा जलापूर्ति योजनाओं से जुड़ी 4436 करोड़ की निविदाएं रद कर दी गई हैं। शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए विभागीय मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि प्रक्रिया में संशोधन के बाद एक माह के भीतर दोबारा से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। महागठबंधन सरकार के दौरान निविदा आवंटन में कुछ गड़बड़ी हुई थी। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों-इंजीनियरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तय है।

सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय के अंतर्गत नल-जल योजना के क्रियान्वयन का दायित्व पीएचईडी के पास है। पूर्ववर्ती महागठबंधन सरकार में नल-जल योजना के तहत 4706 करोड़ की निविदाएं हुई थीं। वे निविदाएं ललित यादव के पीएचईडी मंत्री रहते हुए स्वीकृत हुई थीं। ललित राजद कोटे से मंत्री थे। अब गड़बड़ी वाली अधिसंख्य निविदाओं को रद कर पारदर्शी तरीके से नई निविदाओं के लिए निर्णय लिया गया है। नीरज ने कहा कि अगले छह माह में नल-जल योजना की गड़बड़ियों को पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा। पंचायती राज विभाग से हस्तांरित 50 प्रतिशत से अधिक योजनाएं ठीक नहीं चल रही हैं। उन सभी का स्थल निरीक्षण कराया जा रहा है। योजना से छूटे वार्ड-टोले में जल्द नल-जल का काम किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राजग सरकार के गठन के तत्काल बाद निर्णय लिया गया था कि राजद कोटे के मंत्रियों के कार्यों और निर्णयों की समीक्षा होगी तथा खामी पाए जाने पर निविदाएं निरस्त की जाएंगी। सात मार्च को ही उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इसकी घोषणा कर चुके हैं। तब उनके पास पीएचईडी का दायित्व भी था। नीरज उसी निर्णय पर आगे बढ़ रहे हैं। ये निविदाएं दो चरणों में रद हुई हैं। पहले चरण में निविदाओं के रद करने की घोषणा सिन्हा ही कर चुके थे, जिस पर बाद में नीरज ने भी अपनी मुहर लगाई थी।

श्रद्धालु बनकर राजस्थान पुलिस ने पेपर लीक की आरोपित को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा: राजस्थान में एसआइ भर्ती-2021 समेत छह से ज्यादा परीक्षाओं में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामलों में आरोपित सरकारी शिक्षिका शम्मी बिश्नोई को वहां की पुलिस ने शुक्रवार को बरसाना की एक गोशाला के पास से गिरफ्तार कर लिया। वह यहां गाय की आरती कर रही थी। राजस्थान की पुलिस सर्विलांस के माध्यम से मिले इनपुट के आधार पर यहां कृष्ण भक्त बनकर मंदिर और आश्रमों में उसकी खोजबीन कर रही थी।

राजस्थान पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। पुलिस को उसके बरसाना में होने का इनपुट मिला। इस पर जोधपुर से पुलिस की एक टीम बरसाना पहुंची। जोधपुर रेंज के आइजी विकास कुमार के निर्देशन में पहुंची टीम ने शम्मी को पकड़ने के आपरेशन को राजवृक्ष नाम दिया।

एसआइ परमीत चौहान, सरोज और कांस्टेबल झूमरराम ने बरसाना में शम्मी की खोज में कई दिन तक आश्रम और मंदिर खंगाले। सर्विलांस के माध्यम से एक दिन उसकी श्रीमाता जी गोशाला के पास मोबाइल की लोकेशन मिली। तीन दिन पहले शाम को गायों की निकलने वाली यात्रा में शम्मी उनकी आरती कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। शम्मी ने पुलिस को बताया कि वह यहां छह हजार रुपये प्रतिमाह में किराये का कमरा लेकर दो माह से रह रही थी।

बंगाल के बारे में पीएम के बयान का खंडन नहीं कर सकती तृकां : केंद्रीय मंत्री

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री व बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (तृकां) चोपड़ा और संदेशखाली के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान का खंडन नहीं कर सकती। क्या तृणमूल यह कह सकती है कि चोपड़ा और संदेशखाली के बारे में पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा वह झूठ है?

उनकी टिप्पणी तृकां द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे गए पत्र के जवाब में आई है, जिसमें उनसे बंगाल में चोपड़ा और संदेशखाली की घटनाओं पर सदन में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को हटाने का आग्रह किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को संदेशखाली में स्थानीय लोगों पर तृकां नेताओं के अत्याचार की घटनाओं और हाल में चोपड़ा में एक जोड़े की पिटाई को लेकर बंगाल सरकार की चुप्पी को लेकर आलोचना की थी।

डबल इंजन सरकार में एक भ्रष्टाचार में तो दूसरा अपराध में लगा : तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

- बोले, 18 वर्ष जदयू के पास रहा ग्रामीण कार्य विभाग, मेरे पास सिर्फ कुछ महीने

तेजस्वी यादव। एएनआइ

बिहार में पुल-पुलिया के गिरने, बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार आक्रामक हैं। उनका सरकार पर आक्रामक तेवर शुक्रवार को भी दिखा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है तो दूसरा अपराध में। कहा कि 15 दिन में 12 पुल गिरना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है।

बिहार में अपराध की घटनाओं के साथ पुल-पुलिया गिरने की घटनाओं पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लगाए आरोप पर तेजस्वी ने कहा कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जदयू के पास रहा। वह 18 महीने की गठबंधन सरकार में कुछ महीनों के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री रहे। उस दौरान विभाग में पैसा ही नहीं था। सात-आठ महीने तो पैसे लाने में लग गए। उनके कार्यकाल में कुछ पुल-पुलिया की योजना स्वीकृत हुई थी वह योजनाएं तो अभी टेंडर में होंगी या प्रक्रियाधीन होंगी। ज्यादा समय यह मंत्रालय जदयू के पास रहा। 17 साल तक जिसके पास मंत्रालय रहा उसे जवाब देना चाहिए पुल-पुलिया क्यों गिर रहे। उन्होंने पेपर लीक पर भी सवाल उठाए और कहा कि कौन सी परीक्षा है जिसके पेपर लीक नहीं हो रहे। बिहार की जनता देख रही है जिनकी सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, पुल-पुलिया गिरे उनकी सरकार को जनता वापस सत्ता में लौटने नहीं देगी।

नीट पीजी 11 अगस्त को, दो पालियों में होगी परीक्षा

नई दिल्ली, प्रेट्र : मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट-पीजी 11 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने शुक्रवार को कहा कि 11 अगस्त को दो पालियों में नीट-पीजी 2024 का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 जून को नीट-स्नातकोत्तर परीक्षा स्थगित कर दी थी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 23 जून को होनी थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता पर लगे आरोपों के मद्देनजर ऐहतियाती कदम उठाते हुए यह परीक्षा स्थगित की थी।

बोर्ड ने कहा, नीट-पीजी 2024 परीक्षा का आयोजन पुनर्निर्धारित किया गया है। अब यह 11 अगस्त को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। नीट-पीजी 2024 में उपस्थित होने की पात्रता के लिए कट-आफ तिथि 15 अगस्त, 2024 ही रहेगी। नीट-पीजी का आयोजन एनबीईएमएस द्वारा तकनीकी साझेदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ मिलकर किया जाता है।

सिर्फ एनटीए को ही नहीं, राज्यों को भी परीक्षाएं फूलप्रूफ बनाने में दी जाएगी मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एनटीए के सामने भले ही इस बार सामने आई गड़बड़ी, राज्यों में सालों से है
- उच्च स्तरीय कमेटी राज्यों से भी लेगी राय, परीक्षाओं में राज्यों की अहम भूमिका

प्रतीकात्मक

परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने की पहल सिर्फ केंद्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि राज्यों को भी अपनी परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने में मदद दी जाएगी। यही वजह है कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी अब इस मुद्दे पर राज्यों से भी रायशुमारी की तैयारी में है। वैसे भी केंद्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी की यह गूंज पहली बार इस स्तर पर हुई है जबकि राज्यों में यह समस्या पिछले कई सालों से पांव पसारे हुए है।

परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को लेकर काम कर रही कमेटी और उससे जुड़े विशेषज्ञों ने इस मुहिम से राज्यों को जोड़ने की पहल इसलिए भी की, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पेपरलीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के जो भी मामले सामने आए हैं, वह राज्यों से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों से जुड़े हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सात सालों में देशभर में करीब 70 मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक 14 मामले अकेले राजस्थान के हैं, जो 2015 से 2023 के हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी पिछले सालों में पेपरलीक और गड़बड़ियों के बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। ऐसे में राज्यों को इस मुहिम से अलग नहीं रखा जा सकता। कमेटी से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक राज्यों में पिछले कई सालों से सामने आ रही परीक्षाओं की इन गड़बड़ियों व पेपरलीक की घटनाओं से यदि उसी समय सख्ती से निपटा गया होता तो स्थिति आज इस स्तर तक नहीं पहुंचती।

विशेषज्ञों की मानना है कि जब तक राज्यों में परीक्षाओं की गड़बड़ी को रोकने को मजबूत तंत्र नहीं खड़ा किया जाता है, तब तक मुकम्मल तौर पर इस तरह की गड़बड़ियों को रोक पाना मुश्किल होगा। विशेषज्ञ कमेटी ने उन राज्यों पर अधिक फोकस किया है, जहां पिछले कुछ सालों में गड़बड़ियों के अधिक मामले हुए हैं। परीक्षाओं को फूलप्रूफ बनाने को राधाकृष्णन कमेटी अगले दो महीनों में इसे लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।

जमीन पर कब्जा न मिलने पर बिहार में डीएम के जनता दरबार में बुजुर्ग ने खुद को लगाई आग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर में आत्मदाह के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती मरीज के स्वजन की भीड़। जागरण

बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन पर वर्षों से कब्जा नहीं मिलने से क्षुब्ध बुजुर्ग ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इसके बाद बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वहां मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। डीएम के अंगरक्षक और कर्मचारियों ने किसी तरह उनके शरीर में लगी आग बुझाई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में डीएम सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि पीड़ित को पर्चे पर जितनी जमीन मिली थी। उतनी पर कब्जा करा दिया गया था। एक डिसमिल जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद की बात सामने आई है। मामले की जांच करने को कहा गया है।

प्रत्येक शुक्रवार की तरह डीएम सुब्रत कुमार सेन जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। एसएसपी राकेश कुमार भी मौजूद थे। अपनी फरियाद लेकर बिंदा लाल गुप्ता भी आए थे। उनकी शिकायत थी कि जमीन पर एक दबंग वार्ड पार्षद कब्जा नहीं होने दे रहे। फरियाद लेकर डीएम कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने दोपहर 12 बजे प्लास्टिक के छोटे डिब्बे में लाया पेट्रोल अपने शरीर पर उड़ेल लिया। इसके बाद माचिस की तीली जला आग लगा ली, आग की जलन से बिंदा लाल बाहर की ओर भागे। शोर सुनकर डीएम भी बाहर निकले। वहां मौजूद डीएम के बाडीगार्ड एवं कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद उसे कब्जे में शरीर पर कपड़ा डाल आग बुझाई। बिंदा गुप्ता को घर से कुछ ही दूरी पर स्थित महादलित टोला में 1760 स्क्वायर फीट (चार डिसमिल) जमीन मिली है। इस पर नगर परिषद के एक दबंग वार्ड पार्षद ने कई वर्षों से कब्जा किया हुआ है।

परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को महाराष्ट्र में पेश किया गया विधेयक

राज्य ब्यूरो, मुंबई : प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में पांच साल तक की सजा का प्रविधान है। मंत्री शंभूराज देसाई ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में विधेयक 'महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' को पेश किया। विधेयक के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

विधेयक में कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों और अपराधों में लिप्त पाए जाने वालों को कम से कम तीन साल कैद की सजा होगी, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है। 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त सेवा प्रदाता को गड़बड़ी होने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही परीक्षा की लागत प्रदाता से ही वसूली जाएगी। उसे चार साल की अवधि के लिए बैन किया जाएगा।

नीट मामले में बिहार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

प्रथम पृष्ठ से आगे

नीट-यूजी, 2024 में गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओयू) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मामले में हुई जांच का ब्योरा दिया। हालांकि ईओयू ने पेपर लीक और अनियमितताओं की जांच का सिर्फ 23 जून तक का ब्योरा दिया है और कहा कि 23 जून को मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी इसलिए वह उसके आगे की जांच का अपडेट नहीं दे रही है।

हलफनामे में कहा गया है कि पांच मई, 2024 को पटना पुलिस को नीट में कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायत मिली थी जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। संदिग्धों के मोबाइल फोन और कुछ संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए। राज्य पुलिस ने गहराई से मामले की जांच की तो पाया कि कुछ अभियुक्त पूर्व में भी ऐसे ही अपराधों में शामिल रहे हैं। चार और लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने नीट धांधली में शामिल होने की बात स्वीकारी। 17 मई को यह मामला आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आठ सदस्यीय एसआइटी गठित की गई। जांच में ईओयू ने पाया कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। झारखंड के भी लोग इसमें शामिल हैं। 20 जून को बिहार सरकार ने मामले की जांच रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी। बिहार ने कहा कि 23 जून को केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी और इसके बाद प्रदेश सरकार ने मामले से जुड़ी सारी सामग्री सीबीआइ को दे दी। बिहार की ओर से यह हलफनामा वकील मनीष कुमार ने दाखिल किया। इसमें यह भी कहा गया है कि जांच सीबीआइ के पास है इसलिए मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती।

नीट पेपर लीक में झारखंड से एक अन्य आरोपित गिरफ्तार

राब्यू, जागरण • पटना: नीट पेपर लीक मामले में सीबीआइ ने एक अन्य आरोपित को झारखंड के झरिया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अमित सिंह उर्फ बंटी बताया जा रहा है। सीबीआइ की ओर से अब तक गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

जानकारी के अनुसार सीबीआइ ने दो दिन पहले अमन सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसके साथ काम करने वाला एक अन्य आरोपी अमित सिंह उर्फ बंटी उस दिन फरार हो गया था। अमन सिंह से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसी को शुक्रवार को अमित को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। अमित सिंह के घर की तलाशी लेने की जानकारी भी आई है। कहा जा रहा है कि तालाशी में रुपये, तीन बैंक खातों की पासबुक, चार मोबाइल, गांव की जमीन और गाड़ियों के कागजात बरामद हुए हैं।

आइसक्रीम में कनखजूरा मिलने की पोस्ट हटाने का कोर्ट ने दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कहा, दंपती सुनवाई में नहीं हुए शामिल, जांच के लिए आइसक्रीम टब देने से किया इन्कार
- अगले आदेश तक कोई अन्य ऐसी पोस्ट करने पर भी अदालत ने दंपती पर लगाई रोक

इंटरनेट मीडिया एक्स पर अमूल के आइसक्रीम में कनखजूरा मिलने के आरोप लगाने वाली पोस्ट को हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने प्रतिवादी नोएडा निवासी दीपा देवी को अदालत के अगले आदेश तक एक्स पर कोई अन्य ऐसी सामग्री पोस्ट करने और अपलोड करने से रोक दिया। दीपा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में तस्वीर साझा कर लिखा था कि डिलीवरी एप से मंगाई अमूल आइसक्रीम में एक कनखजूरा मिला है।

अमूल ब्रांड के तहत उत्पादों को बेचने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने याचिका में तर्क दिया कि प्रतिवादी का दावा झूठा और गलत था क्योंकि उसकी आइसक्रीम में किसी कीड़े का मौजूद होना बिल्कुल असंभव है। अदालत ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही में प्रतिवादी की अनुपस्थिति ने कंपनी के मामले को मजबूत किया है। दीपा देवी व उनके पति को अदालती कार्यवाही में भाग लेने और अपने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में किए गए दावे को पूरा करने का अवसर दिया गया था, लेकिन वह पेश भी नहीं हुईं और जांच के लिए कंपनी को आइसक्रीम टब सौंपने से भी इन्कार कर दिया। दीपा देवी ने 15 जून 2024 को साझा किए पोस्ट में मृत कीड़े के उनके दावों की फोरेंसिक जांच और सत्यापन में भाग लेने से भी इन्कार किया।

एक माह बाद तृकां के दो विधायकों ने ली शपथ

प्रथम पृष्ठ से आगे

राजभवन और विधानसभा के बीच करीब एक महीने तक चले गतिरोध के बाद दोनों तृणमूल विधायकों को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अध्यक्ष ने शपथ दिलाई गई। गुरुवार देर शाम राज्यपाल ने विधानसभा उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया था। हालांकि विशेष सत्र के दौरान उपाध्यक्ष ने खुद को कार्यक्रम से अलग कर लिया और कहा कि जब अध्यक्ष आसान पर मौजूद हों तो उपाध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाना मानदंडों के विरुद्ध है। उपाध्यक्ष की अपील के बाद अध्यक्ष ने दोनों विधायकों को सदन में बुलाया और शपथ दिलाई।

मालूम हो कि राज्यपाल ने 26 जून को दोनों विधायकों को शपथ के लिए राजभवन में आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि परंपरा के अनुसार उपचुनाव जीतने वालों के मामले में राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को शपथ दिलाने का दायित्व सौंपते हैं। दोनों विधायक राजभवन की बजाय विधानसभा में शपथ दिलाने की मांग पर अडिग थे। मांग को लेकर दोनों विधायक पिछले कुछ दिनों से विधानसभा परिसर में धरने पर भी बैठे।

कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस कि विधायक रेयात हुसैन और सायंतिका बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में शपथ ली। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करीब एक महीने से गतिरोध के कारण अटका था। अंततः विधानसभा के विशेष सत्र में उन्हें शपथ दिलाई गई। शपथ के बाद खुशी प्रदर्शित करते दोनों विधायक। प्रेट्र

खींचतान का एक और दौर शुरू होने की आशंका

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इससे राजभवन और सत्तारूढ़ दल के बीच खींचतान का एक और दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ संवैधानिक प्रविधान राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 188 राज्यपाल को इस मामले में अंतिम अधिकार देते हैं। इसके मुताबिक विस या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा।

2500 करोड़ के घोटाले में संलिप्त 19 अफसर अब भी अहम पदों पर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला

विकास सोनी • नईदुनिया प्रतिनिधि

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए 2,500 करोड़ के शराब घोटाले के सिंडिकेट में शामिल रहे अधिकारी अब भी अहम पदों पर बने हुए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जनवरी 2024 में की गई एफआइआर व आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की ओर से एक जुलाई, 2024 को विशेष कोर्ट में पेश किए 10 हजार पन्नों के आरोपपत्र में इन्हीं अधिकारियों पर घोटाले में संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं। इनमें से एक अधिकारी की पिछले माह मृत्यु हो चुकी है, बाकी के 19 अधिकारी अब भी आबकारी विभाग में अहम पदों पर बने हुए हैं। इसमें उड़नदस्ता, जिला आबकारी अधिकारी और उपायुक्त के पद शामिल हैं। एफआइआर और जांच में नाम आने के बावजूद अब तक इन अधिकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

ईओडब्ल्यू के आरोपपत्र के अनुसार, शराब घोटाले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लि. के तत्कालीन प्रबंध संचालक एपी त्रिपाठी ने शराब सिंडीकेट बनाया।

- शराब घोटाले की एफआइआर में हैं इन अफसरों के नाम

शराब घोटाले मामले में जांच एजेंसियां लगातार पड़ताल कर रही हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। जिन अधिकारियों के नाम सामने आए थे वह बयान के आधार पर थे और एजेंसियां प्रमाण के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं। जिन अधिकारियों के खिलाफ प्रमाण मिलते जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है।

– विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री, छत्तीसगढ़

****

35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यह अभियान रक्षाबंधन से प्रारंभ होगा। इसमें 25 करोड़ पौधे 20 जुलाई को लगाए जाएंगे। शेष 10 करोड़ पौधे 15 अगस्त तक लगेंगे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 6 जुलाई, 2024

सूरजपाल के खिलाफ अनुयायियों में गुस्सा, बताया धोखेबाज व ढोंगी

हाथरस हादसा ▸ इंसानियत भी भूल गया खुद को 'परमात्मा' कहने वाला सूरजपाल

बोले-जनता मर रही थी, पर उसने पलट कर भी नहीं देखा

सुरजीत पुंढीर ● जागरण

अलीगढ़ : अनुयायियों के बीच सूरजपाल सिंह (नारायण साकार विश्व हरि) स्वयं को 'परमात्मा' बताता है। सत्संग में हर पल साथ रहने की बात कहता है। दुख की घड़ी में एक-दूसरे का साथ निभाने की सीख देता है, लेकिन जब अनुयायियों पर मुसीबत आई तो खुद सारी मानवता और इंसानियत भूल गया। भगदड़ में उसे ईश्वर मानने वाले अनुयायी मर रहे थे, लेकिन उसने किसी की चिंता नहीं की। एक बार पलट कर नहीं देखा। चार दिन बाद भी किसी मृतक के स्वजन या घायल का हाल नहीं जाना। ऐसा व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता? यह तो धोखेबाजी है। ढोंग है। अब परिवार से किसी को भी उनके सत्संग में नहीं जाने देंगे। यह कहते हुए पिलखना के छोटेलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने सत्संग के बाद मची भगदड़ में अपनी पत्नी मंजू देवी और इकलौते छह वर्षीय पुत्र पंकज को खोया है।

दो जुलाई को मची भगदड़ में जिन 121 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनमें चार पिलखना नगर पंचायत के फरहान मोहल्ले के थे। अनुसूचित जाति वर्ग बहुल मोहल्ले में 50 से अधिक परिवार सूरजपाल के अनुयायी हैं। देश के अलग-अलग शहरों में होने वाले सत्संगों में यहां से लोग शामिल हुए हैं, लेकिन घटना के चार दिन बीत जाने के बाद भी सूरजपाल द्वारा कोई प्रतिक्रिया न देने पर अनुयायियों का गुस्सा फूटने लगा है। शुक्रवार को पिलखना कस्बे में लोगों ने जमकर भड़ास निकाली। हादसे में अपनी मां को खोने वाले अमित, विनोद व मुकेश कहते हैं कि उन्होंने कई बार मां को कार्यक्रम में जाने से रोका था, मगर मां भगवान की तरह सूरजपाल को मानती थीं। वह कहती थीं कि वह कुछ नहीं होने देंगे।

▸ **पीड़ितों का हाल भी जानने के लिए नहीं आने पर है नाराजगी**

शुक्रवार को पिलखना स्थित घर में मृतक प्रेमवती के बेटे अरविंद, बिजेंद्र और सुनील। जागरण

मुख्य आरोपित ने किया समर्पण

जागरण संवाददाता, आगरा : हाथरस हादसे के मुख्य आरोपित सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने शुक्रवार रात को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वह कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। मधुकर पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। गौरतलब है कि हाथरस जिले के फुलरई गांव में दो जुलाई को सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार विश्व हरि के सत्संग में भगदड़ से 121 अनुयायियों की मृत्यु हो गई थी। मामले में पुलिस ने मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, अन्य आयोजकों व सेवादारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने दोषियों को चिह्नित कर दो महिलाओं सहित छह लोगों की गिरफ्तारियां की थीं।

किसी घटना को 'गिद्ध दृष्टि' से नहीं देखना चाहिए : भाजपा

नई दिल्ली, एएनआइ : हाथरस के भगदड़कांड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि किसी को भी राजनीतिक लाभ के लिए किसी घटना को 'गिद्ध दृष्टि' से नहीं देखना चाहिए। पार्टी ने यह भी पूछा है कि वह हाथरस तो गए लेकिन तमिलनाडु के कल्लाकुरुचि जहरीली शराबकांड में मारे गए निर्दोष लोगों के स्वजनों से मिलने क्यों नहीं गए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शुक्रवार को हाथरस की भगदड़ में मारे गए लोगों के घरवालों से मिलने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वह इन परिवारों को उचित मुआवजा दें और उसे राशि को बढ़ाएं। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी एलओपी बनने के बाद से भय और संशय की राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है कि वह हाथरस जैसी हृदयविदारक घटना पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जबकि ऐसी घटनाओं को पूरी संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए। त्रिवेदी ने राहुल गांधी से यह भी पूछा कि तमिलनाडु के अनुसूचित जाति के 50 से अधिक लोगों के जहरीली शराब से मरने पर उनका क्या कहना है। इस संबंध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है।

राहुल बोले-हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार, संसद में उठाएंगे मुद्दा

जागरण टीम, अलीगढ़

▸ **कांग्रेस नेता ने अलीगढ़ व हाथरस में हादसे के पीड़ितों से की मुलाकात**

▸ **मरने वालों के स्वजन से बांटा दर्द, सीएम से दिल खोलकर मुआवजा देने की अपील**

सूरजपाल सिंह के सत्संग के बाद मची भगदड़ के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। हादसे के चौथे दिन शुक्रवार को उन्होंने अलीगढ़ के गांव पिलखना और हाथरस के नवीपुर में जाकर मरने वालों के स्वजन से बात कर दर्द बांटा। इस दौरान कहा कि वह हादसे पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण हादसा हुआ। घोषित किए गए मुआवजे को कम बताया। कहा कि इस मामले को वह संसद में उठाएंगे। साथ ही अपील की कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल खोलकर मुआवजा दें। हादसे में 121 लोगों की मृत्यु हुई है।

तय समय से 30 मिनट की देरी से पिलखना पहुंचे राहुल ने मृतक मंजू के पति व छह वर्षीय पंकज के पिता छोटेलाल से बात की। इसके बाद वह मृतक प्रेमा देवी के घर पहुंचे। फिर हाथरस पहुंचे। यहां पर नवीपुर खुर्द में मृतक मुन्नी देवी, आशा देवी, ओमवती और किशोरी लतामणि के स्वजन से मुलाकात की। करीब आधा घंटे उनके बीच रहे। मुन्नी देवी के बेटे सुभाष ने बताया कि राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताया है और इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने की बात कही है। लतामणि के पिता उमेश कुमार और बड़ी बहन वैष्णवी ने भी रोते हुए दुख को साझा किया। इसके बाद राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हादसे के बाद से परिवार टूटे हुए हैं। वह यहां राजनीति करने नहीं आए हैं। घटना में हाथरस प्रशासन से गलती तो हुई है। पीड़ित परिवारों ने उन्हें बताया कि लाखों की भीड़ वाले कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की थी।

अलीगढ़ के पिलखना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से गले मिलकर रो पड़ी हादसे में मृत मंजू की सास सुन्हरी देवी। सौजन्य : कांग्रेस

बंगाल में महिला व चार साल के बेटे को जिंदा जलाया

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के बीरभूम जिले में शुक्रवार को कुछ अज्ञात लोगों ने एक महिला और उसके चार साल के बेटे को जलाकर मार डाला। इस घटना में मृतकों की पहचान 30 वर्षीय रुम्पा बीबी और उनके चार साल के बेटे अयान शेख के रूप में हुई है। महिला के पति शेख टुटा को गंभीर रूप से झुलसने के कारण स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इस घटना में शेख टुटा का बड़ा बेटा बच गया है। घटना के समय वह दूसरे कमरे में सो रहा था। उसने मीडियाकर्मियों को बताया कि शुक्रवार की सुबह वह अपनी मां की चीख सुनकर उठा। जिस कमरे में उनके माता-पिता और छोटा भाई सो रहे थे, उस कमरे की खिड़कियां सड़क किनारे खुली थीं। वह आग में फंस गए और कमरे से केरोसिन की तेज गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर से आए कुछ बदमाशों ने खुली खिड़की से कमरे में केरोसिन छिड़का और फिर आग लगा दी।

महुआ की अभद्र टिप्पणी पर दर्ज हो एफआइआर : एनसीडब्ल्यू

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर बेहद अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने पर आयोग ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआइआर दर्ज करने को कहा है। वहीं, भाजपा ने भी 'पायजामा टिप्पणी' पर तृणमूल सांसद मोइत्रा की कड़ी आलोचना करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से महुआ को बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मोइत्रा ने अपनी यह पोस्ट अब डिलीट कर दी है।

हाथरस भगदड़ को लेकर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा के घटनास्थल पर पहुंचने पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो पर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा, 'वह अपने बास का पायजामा पकड़ने में व्यस्त हैं।' वास्तविक पोस्ट में एनसीडब्ल्यू की प्रमुख के पीछे एक आदमी को छाता लेकर चलते देखा जा सकता था। जिस पर मोइत्रा ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एनसीडब्ल्यू ने तत्काल इस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'यह अभद्र टिप्पणी एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करती है। आयोग इस टिप्पणी को अपमानजनक मानता है।' आयोग का कहना है कि मानहानि के इस बयान की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील करता है। इसलिए महुआ के खिलाफ एक एफआइआर दर्ज की जानी चाहिए और उस पर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट को तीन दिनों के अंदर तलब किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया के बाद मोइत्रा ने उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, 'दिल्ली पुलिस आओ, तत्काल मेरे खिलाफ दिए आदेश का पालन कर कार्रवाई करो।

▸ **'पायजामा टिप्पणी' पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत केस का निर्देश**

▸ **रेखा शर्मा के अपमान पर भाजपा की तृणमूल सांसद को पार्टी से निकालने की मांग**

पोर्श दुर्घटना के आरोपित नाबालिग ने लिखा सड़क सुरक्षा पर निबंध

पुणे, प्रेट्र : पुणे कार दुर्घटना मामले में आरोपित नाबालिग ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की जमानत शर्तों का पालन करते हुए सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखा है। नाबालिग आरोपित ने बुधवार को जेजेबी को निबंध सौंपा।

नाबालिग को पिछले महीने बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि बांबे हाईकोर्ट ने उसे सुधार गृह में भेजने के आदेश को अवैध करार दिया था। शराब के नशे में नाबालिग ने 19 मई को तेज रफ्तार पोर्श कार से मोटरसाइकिल सवार दो इंजीनियरों को कुचल दिया था। दोनों इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दुर्घटना के कुछ घंटों बाद जेजेबी ने आदेश दिया था कि नाबालिग आरोपित को उसके माता-पिता और दादा की देखरेख में रखा जाए। जेजेबी ने नाबालिग को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया था। जेजेबी के आदेश का देशभर में विरोध होने पर पुलिस ने जमानत आदेश में संशोधन की मांग करते हुए किशोर न्याय बोर्ड का दरवाजा खटखटाया।

कोलकाता में इस्कान की रथयात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

▸ **हाथरस की घटना को देखते हुए बरती जा रही विशेष सतर्कता**

▸ **मुख्यमंत्री ममता सात जुलाई को करेंगी 53वीं रथयात्रा का उद्घाटन**

उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले दिनों हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत की वीभत्स घटना को देखते हुए इस्कान की कोलकाता रथयात्रा को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मालूम हो कि यह जगन्नाथ पुरी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रथयात्रा मानी जाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सात जुलाई को 53वीं कोलकाता रथयात्रा का उद्घाटन करेंगी। वह वहीं से कोलकाता में इस्कान के संस्थापक भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम पर एक पार्क व अलीपुरद्वार जिले में निर्मित आद्यापीठ मंदिर का भी उद्घाटन करेंगी। दीघा में बंगाल सरकार की ओर से निर्मित कराए जा रहे जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा अगले साल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी।

कोलकाता इस्कान के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने बताया-'हाथरस में जो हुआ, वह बहुत दुखदायी है। हम भीड़ प्रबंधन को लेकर काफी सतर्क हैं। रथयात्रा के दिन कोलकाता पुलिस के 600-700 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस बार 24 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। इसके साथ बड़ी संख्या में निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मी भी मुस्तैद रहेंगे। हमारे अपने 1,000 वालंटियर भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।

प्रतीकात्मक

तृणमूल नेता के भाई ने कान पकड़ कर उठक-बैठक करवाई

जागरण संवाददाता, इस्लामपुर : बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में तृणमूल नेता द्वारा भरी पंचायत में एक युवक और युवती के साथ मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि इसी जिले में एक और वीडियो प्रसारित हो गया है। इस वीडियो में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष अब्दुल हक का भाई किसी से कान पकड़कर उठक-बैठक करवा रहा है। वह व्यक्ति बीच-बीच में तृणमूल नेता के भाई का पैर पकड़ रहा है और मिन्नतें करता नजर आ रहा है। दैनिक जागरण इस प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम मोहम्मद खालेक है। शुक्रवार को उसे इस्लामपुर के एसीजेएम अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पहले प्रसारित वीडियो के मुख्य आरोपित ताजीमुल उर्फ जेसीबी की तरह इसके खिलाफ भी इस्लामपुर थाने में दबंगई और आतंक मचाने के कई आरोप हैं।

अनंत-राधिका के संगीत में जस्टिन बीबर ने बांधा समा

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

▸ **समारोह में गाने के लिए बीबर ने 83 करोड़ तो बादशाह ने चार करोड़ लिए**

▸ **मुंबई में अंबानी कल्चरल सेंटर के द ग्रैंड थिएटर में हुआ भव्य संगीत समारोह**

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अरबपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति विरेन मर्चेंट की बेटी राधिका के शादी से पूर्व भव्य समारोहों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार की रात आयोजित 'शुभ संगीत' को देश-विदेश के सुपरहिट गायकों के सुरों से सजाया गया। दो बार के ग्रैमी विजेता जस्टिन बीबर भारत इस भव्य संगीत समारोह में मेहमानों का मनोरंजन करने पहुंचे। उन्होंने परफार्म करने के लिए 83 करोड़ रुपये लिए हैं। इसके अलावा, देश के सबसे बड़े रैपर बादशाह ने भी अपने गानों पर सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया।

मामेरू समारोह और गरबा नाइट्स के बाद शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के द ग्रैंड थिएटर में अनंत और राधिका की शादी का संगीत समारोह हुआ। इससे पहले, दिन में 30 वर्षीय जस्टिन बीबर लास एंजिलिस से मुंबई पहुंच गए। गुलाबी टीशर्ट, स्वेटपैंट और लाल रंग की बकेट हैट पहने बीबर अपने दल-बल के साथ सीधे होटल गए। 'बेबी', 'सारी', 'लव यौरसेल्फ' और 'ब्वायफ्रेंड' जैसे चार्टबस्टर गानों के लिए विख्यात कैनेडियन गायक बीबर को इस संगीत समारोह में गाने के लिए एक करोड़ डालर (करीब 83.51 करोड़ रुपये) रकम दी गई है। बताया जाता है कि 'डीजेवाले बाबू' फेम रैपर बादशाह को चार करोड़ रुपये परफार्म करने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पाप सेंसेशन में एडेल, ड्रेक और लाना डेल रे भी संगीत समारोह की जान रहे। अनंत के दोस्त और अभिनेता मीजान जाफरी ने भी पांच गानों पर परफार्म किया। पूर्व क्रिकेटर एमएस धौनी अपनी पत्नी, फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा, अमीषा पटेल समेत अलग-अलग क्षेत्र की प्रख्यात हस्तियां भी समारोह में पहुंचीं।

शादी से पहले आठ जुलाई को गृह पूजा होनी है, जिसमें अनंत और राधिका के करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल होंगे। दस जुलाई को शिव पूजा होगी। 12 जुलाई को राधिका और अनंत शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मुख्य विवाह समारोह में मेहमानों को पारंपरिक भारतीय पोशाक पहननी होगी। वहीं शादी के मेन्यू में चाट की वेरायटी होगी। नीता अंबानी ने खुद वाराणसी के काशी चाट भंडार से विभिन्न तरह की चाट का चयन किया और इसके मालिक राकेश केसरी को शादी में एक स्टाल लगाने के लिए आमंत्रित किया है। मेन्यू में टिक्की, टमाटर चाट, पालक चाट, चना कचौरी और कुल्फी शामिल हैं। 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद समारोह होगा। इस समारोह के लिए भारतीय औपचारिक ड्रेस कोड होगा। वहीं 14 जुलाई को शादी का रिसेप्शन किया जाएगा, जिसमें भारतीय पोशाक ही थीम होगी। इससे पहले गत जून के अंत में हुए अनंत-राधिका के क्रूज पार्टी समारोह में पाप गायिका केटी पेरी भी परफार्म किया था, जिसके लिए उन्होंने लगभग 45 करोड़ रुपये लिए थे। उससे पहले जामनगर में हुए तीन दिवसीय प्रीवेडिंग समारोह में अंतरराष्ट्रीय गायिका रिहाना ने परफार्म करने के लिए 74 करोड़ रुपये फीस ली थी।

अपने विवाह से पहले शुक्रवार को मुंबई में संगीत समारोह के दौरान अनंत अंबानी तथा राधिका मर्चेंट। प्रेट्र

राजस्थान में मतांतरण कार्यक्रम में मारपीट, 28 हिरासत में

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान के भरतपुर में शुक्रवार को मतांतरण के मुद्दे पर विवाद हो गया, दो पक्षों में मारपीट हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 28 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार भरतपुर के मथुरा गेट क्षेत्र में स्थित एक घर में चर्चा फाउंडेशन के बैनर तले मतांतरण का कार्यक्रम चल रहा था। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। विहिप कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि करीब एक सौ लोग मतांतरण कार्यक्रम में मौजूद थे। विहिप के जिला अध्यक्ष लाखन सिंह ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों को 500-500 रुपये के नोट देकर बुलाया गया था।

18 वर्ष बाद फर्जी एनकाउंटर के आरोपित पुलिसकर्मी को जमानत

जम्मू, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 18 वर्ष पुराने फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपित पुलिसकर्मी को जमानत दे दी है। आरोपित को 2006 में गिरफ्तार किया गया था और तब से न्यायिक हिरासत में है। बीच में कुछ माह के लिए अंतरिम जमानत मिली थी।

पुलिसमकर्मी बंसीलाल पर आरोप है कि उसने 2006 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और बाद में उसे आतंकी साबित करने का प्रयास किया। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए कहा कि यह विलंबित मुकदमे के कारण अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। फिलहाल वह जम्मू के कोट भलवाल जेल में बंद है और उन्होंने जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।

वकील ने बताया कि आरोपित लगभग 18 वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें कोर्ट ने कभी राहत नहीं दी, सिवाय कुछ माह की अंतरिम जमानत दी गई थी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में कुल 72 गवाह हैं, जिनमें से पिछले 17 वर्षों में केवल 28 से पूछताछ की जा सकी है। अदालत इस मामले के तथ्यों से आश्चर्यचकित है।

आदेश में कहा गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के स्तर पर मुकदमे में देरी हो रही है। इसके साथ ही राज्य यह दिखाने में असमर्थ है कि देरी के लिए आवेदक को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अदालत ने आरोपित को 50 हजार रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि प्रस्तुत करने पर तुरंत जमानत करने का आदेश दिया।

▸ **2006 में हुई थी गिरफ्तारी, दो दशक में 72 में से मात्र 28 गवाहों से हो पाई पूछताछ**

पीड़ितों को मुआवजे के विरुद्ध मद्रास हाई कोर्ट में याचिका

कल्लाकुरिची शराब त्रासदी

चेन्नई, प्रेट्र : कल्लाकुरिची शराब त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में शराब त्रासदी के पीड़ितों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को रद करने की मांग की गई है। दलील दी गई कि पीड़ित स्वतंत्रता सेनानी या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, जिन्होंने आम जनता या समाज के लिए अपनी जान गंवाई हो।

मोहम्मद गौस द्वारा दायर जनहित याचिका जब शुक्रवार को सुनवाई के लिए आई तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर. महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मुआवजे की राशि अधिक है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

याचिका में कहा गया कि अवैध शराब पीना गैरकानूनी कृत्य है। राज्य को उन लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अवैध शराब पीकर गैरकानूनी काम किया। मुआवजा केवल दुर्घटना के पीड़ितों को दी जानी चाहिए, न कि उन लोगों को जिन्होंने कोई अवैध कार्य किया हो। याचिका में कहा गया कि शराब त्रासदी के सभी पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश अनुचित और मनमाना है।

बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शराब से लोगों को मरने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए एनसीडब्ल्यू सदस्य खुशबू सुंदर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।

▸ **दी दलील, स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ित**

▸ **शराब त्रासदी के पीड़ितों को दिया गया है 10 लाख रुपये मुआवजा**

एक दिन पहले युवाओं से आधुनिक शिक्षा से देश सेवा का आह्वान किया गया था

प्रथम पृष्ठ से आगे

यह प्रस्ताव ऐसे समय में है, जब मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा पर सरकारों के साथ बुद्धिजीवी भी जोर दे रहे हैं। खुद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक दिन पहले अधिवेशन में मुस्लिम युवाओं से आधुनिक शिक्षा के माध्यम से देश की सेवा का आह्वान किया था। दूसरे दिन मदनी ने कहा कि जमीयत विशुद्ध धार्मिक संगठन है, यह आधुनिक शिक्षा के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि नई पीढ़ी को बुनियादी धार्मिक शिक्षा प्रदान किए बिना स्कूल की शिर्क (किसी को अल्लाह के बराबर दर्जा देना) वाली शिक्षाओं पर आधारित पाठ्यक्रम न पढ़ाया जाए। मदनी ने उत्तर प्रदेश के गैरमान्यता प्राप्त 4,204 मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अन्य स्कूलों में प्रवेश दिलाने के राज्य सरकार के निर्णय पर टकराव वाला रुख अपनाते हुए कहा कि हम कहना चाहते हैं कि इस्लामी मदरसे शिक्षा के अधिकार कानून से अलग हैं, और यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है, जिसे हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

भारत में बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश करने वाले 16 रोहिंग्या गिरफ्तार

अगरतला, प्रेट्र : बांग्लादेश से बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले 16 रोहिंग्याओं को त्रिपुरा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें सात महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर गुरुवार को 11 संदिग्ध को धर्मनगर इंटरस्टेट बस टर्मिनल से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि बांग्लादेश स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में रह रहे थे और अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की है। वे सभी गुवाहाटी जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। वहीं, उत्तरी त्रिपुरा के चुराइबारी इलाके में एक अलग घटना में पुलिस ने गुवाहाटी जाने वाली एक बस को रोका और यात्रियों से पहचान सत्यापित करने का अनुरोध किया। इस दौरान पांच रोहिंग्या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे।

ईडी ने सहारा के ठिकानों से बरामद किए करीब तीन करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : ईडी ने सहारा समूह के विरुद्ध एक सोसायटी में 25 हजार करोड़ रुपये जमा कराए जाने के मामले की छानबीन के दौरान कई संदिग्ध कंपनियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान 2.98 करोड़ रुपये के अलावा लगभग 700 संदिग्ध कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क कब्जे में ली है, जिसके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। ईडी ने बुधवार को कोलकाता व लखनऊ स्थित सहारा समूह के छह ठिकानों पर छापेमारी की थी। लखनऊ में कपूरथला स्थित समूह के कारपोरेट आफिस में भी छानबीन की गई थी।

****

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

फर्जी दावे के साथ नेहरू की तस्वीर प्रसारित

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को लेकर एक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें जवाहर लाल नेहरू की एक तस्वीर शेयर कर कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि स्वामी विद्यानंद विदेह ने एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री को थप्पड़ मार दिया था।

पड़ताल: प्रसारित तस्वीर को गूगल लेंस से सर्च करने पर पता चला कि यह तस्वीर पहले भी प्रसारित हो चुकी है। सर्च में हमें एक न्यूज वेबसाइट पर भी प्रसारित तस्वीर मिली। इसे छह जनवरी, 1997 को अपलोड किया गया है। इसके कैप्शन में लिखा है, जनवरी, 1962 में पटना में कांग्रेस की एक बैठक में सुरक्षाकर्मी ने प्रधानमंत्री नेहरू को उपद्रवी भीड़ में जाने से बचाने के लिए पकड़ लिया। इसमें फोटो की तारीख एक जनवरी, 1962 दी गई है। गूगल न्यूज आर्काइव में जनवरी, 1962 का पेपर सर्च करने पर आठ जनवरी, 1962 को द फ्लोरेंस टाइम्स में छपी यह तस्वीर मिली। इसके कैप्शन में भी इसे पटना में हुए कांग्रेस अधिवेशन का बताया गया। इसके बाद हमने स्वामी विद्यानंद विदेह के बारे में जानकारी के लिए सर्च किया। वेद संस्थान की वेबसाइट के अनुसार, स्वामी विद्यानंद विदेह संस्थान के संस्थापक हैं। वेबसाइट पर हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे प्रसारित दावे की पुष्टि हो सके।

निष्कर्ष: जनवरी, 1962 में पटना में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहर लाल नेहरू को उपद्रवी भीड़ में जाने से रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया था। उस तस्वीर को गलत दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा है।

क्या हो रहा है प्रसारित

फेसबुक यूजर अमरकांत त्रिपाठी ने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, 'जब नेहरू के मुंह पर झन्नाटेदार झापड़ मारा गया था स्वामी विद्यानंद विदेह के द्वारा। कारण.. नेहरू ने एक समारोह के अपने भाषण में कहा कि हिंदू आर्य समाज के लोग हिंदुस्तान में शरणार्थी हैं।'

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

18 प्रांतीय भाषाओं में तीनों नए कानूनों का अनुवाद होना है। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर इसका अनुवाद कर लिया है और इसको पास करवाने के लिए केंद्र सरकार को भेजा हुआ है।

न्यूज गैलरी

तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या

चेन्नई : बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के. आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार को छह सदस्यीय गिरोह ने हत्या कर दी। दो पहिया वाहन से आए बदमाशों ने आर्मस्ट्रांग पर उनके घर के समीप ही हमला किया जिसमें वह घायल हो गए। इसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले। पुलिस ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय आर्मस्ट्रांग की मौत हो गई। आर्मस्ट्रांग चेन्नई नगरनिगम के पूर्व पार्षद थे। पुलिस ने संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है। (प्रेट्र)

वाईएसआरसीपी का पूर्व विधायक दुष्कर्म में गिरफ्तार

कर्नूल : आंध्र प्रदेश पुलिस ने वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक जे. सुधाकर को चार वर्ष तक एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोडुमुरु से विधायक रह चुके सुधाकर को नाबालिग की शिकायत पर गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने पुलिस को वीडियो प्रमाण सौंपा है। कर्नूल सब-डिवीजन पुलिस अधिकारी विजय शेखर रेड्डी ने कहा कि सुधाकर ने 2019 से 2023 के दौरान नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। उस दौरान पीड़िता विधायक के घर में घरेलू सहायिका थी। (प्रेट्र)

सुकेश को धोखाधड़ी मामले में बांबे हाई कोर्ट से जमानत

मुंबई : ठग सुकेश चंद्रशेखर को बांबे हाई कोर्ट ने 2015 के धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी है। यह मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज किया था। अन्य कई मामलों में आरोपित होने के कारण तिहाड़ जेल में बंद चंद्रशेखर अभी बाहर नहीं आ सकेगा। चंद्रशेखर पर पोंजी स्कीम के माध्यम से 19 करोड़ रुपये जुटाने का आरोप है। (प्रेट्र)

बांबे हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज संस्थापक की जमानत बढ़ाई

मुंबई : बांबे हाई कोर्ट जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अंतरिम जमानत शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी। मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए नरेश गोयल को हाई कोर्ट ने छह मई को मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। कैंसर से पीड़ित नरेश गोयल ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें प्रारंभिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी होगी। हाई कोर्ट अब दो अगस्त को नरेश गोयल की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगा। (प्रेट्र)

ईडी की चार्जशीट में 11 साल बाद पी चिदंबरम की पत्नी पर आरोप

सारधा घोटाले में इतनी देरी से चार्जशीट पेश करने पर ईडी को फटकार

न्यायाधीश ने मामले से संबंधित दस्तावेज नहीं किए स्वीकार, 1.5 करोड़ रुपये लेने का मामला

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल के बहुचर्चित सारधा चिटफंड घोटाले में शुक्रवार को कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में 11 साल बाद तीसरी चार्जशीट दाखिल करने पर न्यायाधीश ने ईडी को फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि आखिर 11 साल बाद चार्जशीट क्यों दाखिल की गई? ईडी ने मामले से संबंधित दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सूत्रों के मुताबिक 65 पन्नों की चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की वकील पत्नी नलिनी चिदंबरम पर आरोप लगाए गए हैं। 1,100 पन्ने के विभिन्न साक्ष्य भी संलग्न किए गए हैं। इसी को लेकर ईडी को कोर्ट में सवालों का सामना करना पड़ा।

नलिनी चिदंबरम। फाइल

यह है सारधा चिटफंड घोटाला

वर्ष 2013 में सारधा चिटफंड घोटाला सामने आया था। यह राज्य का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। समूह ने बंगाल, असम और ओडिशा में हजारों निवेशकों से आकर्षक रिटर्न का प्रस्ताव देकर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये जुटाए थे। जिसमें से अधिकांश रकम का भुगतान नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ व ईडी इस घोटाले की जांच कर रही है।

प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिए थे 1.5 करोड़ : ईडी का दावा है कि नलिनी ने सारधा समूह के मालिक व मुख्य आरोपित सुदीप्त सेन से 1.5 करोड़ रुपये लिए थे। इस संबंध में नलिनी ने कहा था कि उन्होंने वकील के तौर पर सलाह देने के बदले में ये पैसे लिए। ईडी का कहना है कि नलिनी को उस वक्त प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसे दिए गए थे। उस समय उनके पति पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। इस पर न्यायाधीश ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे समझाएं कि अगर कोई कर सलाहकार पैसे लेता है तो यह भ्रष्टाचार कैसे है? अगर कोई अपराधी अपने अपराध का पैसा किसी वकील को देता है, तो क्या वह वकील भी मनी लांड्रिंग का अपराधी बन जाता है?

न्यायाधीश यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस तरह अराजकता पैदा की जा रही है। आपके कार्य सत्य नहीं हैं। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की लेकिन कोर्ट में इसे स्वीकार नहीं किया गया। बाद में ईडी के वकील ने एक और तारीख का अनुरोध किया। कहा कि उस दिन सभी सवालों के जवाब दिये जाएंगे। इससे पहले सारधा मामले में 34 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया गया था। कई को तलब कर पूछताछ की गई है। नलिनी से पूछताछ नहीं की गई। नलिनी से ईडी को पूछताछ को लेकर कोर्ट से स्थगन मिल गया है।

कांवड़ यात्रियों के गोमुख जाने पर रोक

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में चार दिन से रुक-रुक कर हो रही वर्षा ने पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। नदी-नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसे देखते हुए उत्तरकाशी में जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रियों और ट्रेकिंग के लिए गोमुख जाने पर रोक लगा दी है। गोमुख क्षेत्र में गदेरे पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल बहने से 36 कांवड़ यात्री 24 घंटे तक फंसे रहे। इन्हें शुक्रवार शाम एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। जबकि, गुरुवार को चीड़बासा के पास गदेरे के उफान में बहे दिल्ली निवासी दो कांवड़ यात्रियों का पता नहीं चल पाया है। वहीं, पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा को जोड़ने वाला धारचूला-तवाघाट मार्ग अब तक नहीं खुल पाया है। इस कारण आदि कैलास से लौटे 35 यात्री तवाघाट के पास फंसे हुए हैं।

80 प्रतिशत तक घट गई चारों धाम में दर्शनार्थियों की संख्या : उत्तराखंड में वर्षा के जोर पकड़ने के साथ ही चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग गया है। यात्रा के शुरुआती दौर से आकलन करें तो चारों धाम में दर्शनार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत तक घट गई है। इस वर्ष गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट एक ही दिन 10 मई को खुले थे, जबकि बदरीनाथ धाम के कपाट दो दिन बाद 12 मई को खोले गए। इस कारण यात्रा ने शुरुआती दिनों में ही गति पकड़ ली थी।

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, हिमंत ने लिया हालात का जायजा

- डिब्रूगढ़ जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों से की बात
- 29 जिलों में लगभग 21.13 लाख लोग प्रभावित

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बाढ़ के पानी में हिमंता बिस्व सरमा। प्रेट्र

गुवाहाटी, एएनआइ : असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ जिले के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। डिब्रूगढ़ में पिछले छह दिनों से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से सहायता का आश्वासन दिया। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए हिमंत ने लिखा, डिब्रूगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की। डिब्रूगढ़ में विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर हम बाढ़ की समस्या का समाधान खोजेंगे। बिजली आपूर्ति बहाल होने पर सरमा ने कहा कि बिजली का झटका लगने से कोई दुर्घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे बंद कर दिया गया है। इससे पहले सरमा ने गुरुवार को सरमा ने नदी द्वीप माजुली का दौरा किया था और द्वीप के निवासियों से बातचीत की थी।

असम में बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। 29 जिलों में लगभग 21.13 लाख लोग प्रभावित हैं। 24 बाढ़ प्रभावित जिलों में 515 राहत शिविरों में 3.86 लाख से अधिक लोग शरण ले रहे हैं।

महिला ने नाव पर बच्ची को दिया जन्म : असम में बाढ़ के बीच एक महिला ने नाव पर बच्ची को जन्म दिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, जहांआरा बेगम को बुधवार को मेडिकल टीम नाव से मोरीगांव जिले के झारगांव स्वास्थ्य केंद्र ले जा रही थी, तभी उसे प्रसव पीड़ा हुई और भीषण बाढ़ के बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका पति भी उसके साथ था। मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 77 जंगली जानवरों की मौत : प्रेट्र के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में शुक्रवार तक कुल 77 जंगली जानवरों की डूबने या उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि 94 अन्य जानवरों को बचाया गया है। इस बीच, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत एनएच-37 (नया एनएच-715) पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू है।

गुवाहाटी में जलभराव, बच्चा लापता : गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश के बीच शुक्रवार को कई जगहों पर जलभराव हो गया। शहर से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। गुरुवार शाम से शहर के ज्योति नगर इलाके से बच्चा लापता है। वह कथित तौर पर खुले नाले में गिर गया था।

राहुल के अभय मुद्रा को श्री गुरु नानक देव से जोड़ने पर आपत्ति

जागरण संवाददाता, अमृतसर

- एसजीपीसी अध्यक्ष बोले-गुरु साहिब ने ऐसी किसी मुद्रा या आसन को मान्यता नहीं दी
- कहा, पावन गुरवाणी व शिक्षाओं को राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने लोकसभा में राहुल गांधी की ओर से अभय मुद्रा को पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के साथ जोड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई है।

शुक्रवार को एसजीपीसी की कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि गुरु साहिबान की पावन गुरबाणी व शिक्षाओं को राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना कि गुरु साहिब का स्वरूप अभय मुद्रा को दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। गुरु साहिब ने ऐसी किसी भी मुद्रा या आसन को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने सदैव ऐसे कर्मकांड का खंडन करते हुए मानवता को अकाल पुरख से जुड़ने का उपदेश दिया। धामी ने लोकसभा व राज्यसभा के स्पीकरों से अपील की है कि वे यह यकीनी बनाएं कि संसद की कार्यवाही के समय किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। एक अन्य पारित प्रस्ताव में भाजपा सांसद कंगना रनोट द्वारा सिख समुदाय के प्रति टिप्पणियों की निंदा की गई। धामी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कंगना के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज करने की मांग की। एसजीपीसी की ओर से दर्ज केस वापस न लेने पर श्री हरि मंदिर साहिब में योग करने वाली अर्चना की कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी पर धामी ने कहा कि यह अर्चना का संवैधानिक अधिकार है। एसजीपीसी मर्यादा के उल्लंघन की किसी को भी अनुमति नहीं दे सकती।

जबलपुर के कथावाचक को बनाया बंधक, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वृंदावन (मथुरा)

- उधार लिए गए सात लाख रुपये आनलाइन गेम में हार गए थे
- उधार देने वाले युवकों ने बुलाकर गेस्ट हाउस में बनाया बंधक

जबलपुर (मध्य प्रदेश) के कथावाचक को कुछ युवकों ने उधार के विवाद में बंधक बना लिया। बहन की शिकायत पर पुलिस ने कुछ ही देर में युवकों को गिरफ्तार कर कथावाचक को छुड़ा लिया। आरोपितों से दो कार व मोबाइल फोन व कथावाचक से लूटे 28 हजार रुपये बरामद हुए हैं। कथावाचक ने युवकों से सात लाख रुपये उधार लिए थे। यह रकम वह आनलाइन गेम में हार गए थे।

जबलपुर निवासी सिद्धार्थ पांडे कथावाचक हैं। उनका वृंदावन आना-जाना रहता था। यहां उनकी पहचान ओडिशा के युवक मुकुंद से हुई। पैसा कमाने की ललक में उन्होंने मोबाइल पर आनलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया। पहले पैसे कमाए तो लोभ जाग गया। अधिक कमाने को मुकुंद से सात लाख रुपये उधार ले लिए। शुरुआत में लाभ होने पर वह मुकुंद को रकम देते रहे, लेकिन बाद में सात लाख रुपये गेम में हार गए। मुकुंद ने रुपये मांगे तो देने से इन्कार कर दिया। मुकुंद ने रुपये वापस पाने को अपने साथियों के साथ सिद्धार्थ के अपहरण की योजना बनाई। उसने गुरुवार को कथावाचक को बुलाया। यहां एक गेस्ट हाउस में रखकर उनके साथ मारपीट की और एक लाख रुपये मंगाने का दबाव बनाया। सिद्धार्थ के कहने पर स्वजन ने मुकुंद के मोबाइल पर एक लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपित सिद्धार्थ को दूसरे जगह ले गए, वहां सिद्धार्थ व उसके दो साथी अमित व दीपक को बंधक बना लिया।

यह चित्र बिहार के सरकारी स्कूल की दुर्दशा का है। पटना स्थित इस सरकारी स्कूल में शुक्रवार को वर्षा से छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं, तो इस तरह छाते के साथ पढ़ना-पढ़ाना हुआ। एएनआइ

'ओएमआर डाटा रिकवरी को विशेष एजेंसी की मदद ले सीबीआइ'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा- प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित भ्रष्टाचार की जड़ें यहीं छिपी हुई हैं कलकत्ता
- पूरा खर्च बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से उठाया जाएगा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआइ को आदेश दिया कि वह बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में इस्तेमाल की गई ओएमआर (आप्टिकल मार्क रिकाग्निशन) शीट से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष एजेंसी की मदद ले। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल न्यायाधीश पीठ वर्ष 2014 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने कहा कि सीबीआइ संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली निजी संस्थाओं समेत दुनिया में कहीं से भी सलाह और मदद ले सकती है। न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद का पूरा खर्च बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) की ओर से उठाया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि ओएमआर शीट पर मौजूद डेटा को दोबारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित भ्रष्टाचार की जड़ें यहीं छिपी हुई हैं। दो जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने सीबीआइ को मूल हार्ड डिस्क पेश करने का आदेश दिया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ के वकील ने शुक्रवार को बताया कि उनके एजेंसी के अधिकारी इसे अदालत में पेश करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद पीठ ने एजेंसी को विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद लेने का आदेश दिया।

लुधियाना में गनमैन के सामने शिवसेना नेता पर निहंगों ने तलवारों से किया हमला

जागरण संवाददाता, लुधियाना

- दिनदहाड़े हुई घटना सीसीटीवी में कैद, 53 सेकेंड में तलवारों से सिर पर किए 12 वार
- दो आरोपित श्री फतेहगढ़ साहिब से किया गिरफ्तार, तीसरे की तलाश में छापेमारी

शिवसेना पंजाब के नेता और बलिदानी सुखदेव थापर के वंशज 58 वर्षीय संदीप थापर पर शुक्रवार सुबह तीन निहंगों ने तलवारों से हमला कर दिया। संदीप एक्टिवा पर अपने गनमैन के साथ सिविल अस्पताल में कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे। हमलावरों ने पीछे बैठे गनमैन को उतार कर किनारे कर दिया और संदीप पर हमला बोल दिया। आरोपितों ने 53 सेकेंड में तलवार से करीब 12 वार किए। इसके बाद उनकी ही एक्टिवा से फरार हो गए। घायल को पहले सिविल अस्पताल और वहां से डीएमसी ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर है। पुलिस ने देर शाम दो हमलावरों को श्री फतेहगढ़ साहिब से गिरफ्तार कर लिया। तीसरे साथी की तलाश जारी थी। पुलिस कमिश्नर ने हमलावरों का विरोध न करने पर संदीप के गनमैन को निलंबित कर दिया है।

शिवसेना नेता संदीप थापर शुक्रवार सुबह सिविल अस्पताल में एक धार्मिक समागम में भाग लेने पहुंचे थे और वहां से एक्टिवा पर गनमैन के साथ लौट रहे थे। दोनों जैसे ही अस्पताल से थोड़ा आगे पहुंचे दो निहंगों ने उन्हें वहां घेर लिया। इतने में पीछे से तीसरा निहंग भी आ गया और उनके गनमैन को धक्का मार एक तरफ ले गया। शेष दो निहंगों ने संदीप थापर के सिर पर तलवार से वार करना शुरू कर दिया। संदीप के एक्टिवा स्कूटर से नीचे गिरने के बावजूद निहंग हमला करते रहे।

अलगाववादियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं संदीप : संदीप थापर पंजाब में हो रही आतंकी गतिविधियों और अलगाववादियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर भी विभिन्न टीवी चैनल पर विरोध जताया था। पुलिस, इस एंगल पर भी जांच कर रही है। चिंता की बात यह रही कि निहंग के धक्का मारने के बाद गनमैन ने एक तरह से सरेंडर कर दिया। उसने संदीप को बचाने का प्रयास नहीं किया। मौके पर भारी संख्या में राहगीर भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने उनको बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई।

घटना की सूचना मिलते ही शिवसेना और हिंदूवादी नेता डीएमसी पहुंचे और वहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सीपी और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि हमला पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है।

पुलिस का दावा, गिरफ्तार नौसेना अधिकारी वीजा रैकेट के सरगना

- लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन डागर और सब लेफ्टिनेंट ब्रह्म ज्योति की पुलिस हिरासत नौ जुलाई तक बढ़ी
- दक्षिण कोरिया में अवैध रूप से काम करने के इच्छुक भारतीयों को वीजा दिलाने में मदद करता

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में दावा किया कि गिरफ्तार किए गए दो नौसेना अधिकारी कथित वीजा रैकेट मामले के सरगना हैं। सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने लेफ्टिनेंट कमांडर विपिन डागर और सब लेफ्टिनेंट ब्रह्म ज्योति की पुलिस हिरासत नौ जुलाई तक बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने दावा किया है कि वे कथित तौर पर उस सिंडिकेट का हिस्सा थे, जो दक्षिण कोरिया में अवैध रूप से काम करने के इच्छुक भारतीयों को वीजा दिलाने में मदद करता था।

इस मामले में दो नौसेना अधिकारियों के अलावा, सिमरन तेजी, रवि कुमार और दीपक मेहरा उर्फ डोगरा अन्य आरोपित हैं। उनकी हिरासत समाप्त होने के बाद पांचों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद पाटिल के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब डागर और ज्योति विशाखापत्तनम में तैनात थे तो उन्होंने वहां से स्टांप बनाने की मशीन खरीदी और इसका इस्तेमाल जाली दस्तावेज बनाने में किया।

गिरफ्तार आरोपितों ने इन जाली दस्तावेज की मदद से लोगों को दक्षिण कोरिया के अलावा अन्य देशों में भी भेजा। पुलिस ने उनका एक-दूसरे से आमना-सामना कराने के लिए रिमांड बढ़ाने की अपील की थी। पुलिस के अनुसार, ये गिरोह पिछले एक साल में कम से कम समय में आठ लोगों को दक्षिण कोरिया भेजने में कामयाब रहा, लेकिन उनमें से दो को वापस भारत भेज दिया गया है।

तितलियों के अद्भुत संसार में लीजिए प्रकृति के सान्निध्य का अविस्मरणीय अनुभव

यात्रा

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित कवर्धा जिले को प्रकृति का आशीर्वाद, तितलियों की 130 प्रजातियां मोह लेंगी मन

रामकृष्ण डोंगरे ● नईदुनिया

रायपुर : अगर आपको रंग-बिरंगी तितलियां भाती हैं तो चले आइए भोरमदेव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित इस अभयारण्य में 130 से अधिक प्रजाति की तितलियों को देखा जा सकता है। इनमें राष्ट्रीय तितली आरेंज ओकलीफ (केलिमा इनेकस), दुर्लभ प्रजाति की 'स्पाटेड एंगल' आदि शामिल है। तितलियों के स्वर्ग कहे जाने वाले इस अभयारण्य में 200 से अधिक पक्षियों का भी बसेरा है। राजधानी रायपुर से 120 किमी दूर स्थित मैकल पर्वत श्रृंखला से घिरे कवर्धा जिले में चिल्फी घाटी, भोरमदेव मंदिर, सरोधा दादर जलाशय, रानीदहरा जल प्रपात, पीठाघाट वाचटावर और पुरातात्विक स्थल पचराही मुख्य आकर्षण हैं।

सरोधा दादर ग्राम में 11 एकड़ में पहाड़ पर स्थित बैगा एथनिक रिसार्ट ● पर्यटन मंडल

अभयारण्य क्षेत्र को कोर और बफर जोन में बांटा गया है। बफर जोन में चिल्फी घाटी क्षेत्र आता है। जहां बैगा आदिवासियों के कई गांव है। अभयारण्य में अगस्त अंत तक बटरफ्लाई कैंप का आयोजन होगा। वहीं, जंगल सफारी संभवत नवंबर से शुरू हो जाएगा।

-शशि कुमार, वन मंडल अधिकारी, कवर्धा

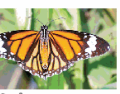

टाइगर तितली

आरेंज ओकलीफ तितली के पंख जब बंद रहते हैं तो यह सूखी पत्ती के समान दिखती है। वहीं, पंख खुलने पर इसके सुंदर रंग बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं ● पर्यटन मंडल

इस तरह पहुंचे, यहां रुके

रायपुर एयरपोर्ट, रायपुर और जगदलपुर रेलवे स्टेशन से आप आसानी से कवर्धा पहुंच सकते हैं। रायपुर से 120 किमी दूर स्थित कवर्धा के लिए नान स्टाप एसी बसें उपलब्ध है। जिले में रुकने के लिए सरोधा दादर के रिसार्ट सहित अभयारण्य के पास और शहर में सस्ते होटल उपलब्ध है। सरोधा रिसार्ट में बुकिंग के लिए आप पर्यटन बोर्ड के नंबर 7714224999 व 9111007964 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

352 वर्ग किमी में फैला भोरमदेव वन्य प्राणी अभयारण्य मोर, किंगफिशर, बायसन, चीतल, नीलगाय जैसे वन्यजीवों, पक्षियों और दुर्लभ वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास है। मगर यहां एक बड़ा आकर्षण केंद्र सात एकड़ में फैला तितलियों का संसार है। वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को यहां तितलियों का संसार देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि आरेंज ओकलीफ तितली जब पंख बंद रखती है तो सूखी पत्ती के समान दिखती है और पंख खुलने पर काला, नारंगी, गहरे नीले रंग वाले पंख सभी को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अभयारण्य क्षेत्र के जामुनपानी और प्रतापगढ़ में जंगल सफारी कर पर्यटक वन्यप्राणियों को देखने जा सकते हैं।

18 किमी दूर भोरमदेव मंदिर परिसर: कवर्धा से 18 किमी दूर स्थित भोरमदेव मंदिर परिसर भगवान शिव को समर्पित चार हिंदू मंदिरों का एक समूह है। हजारों वर्ष पुराने इन मंदिरों को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। यहां मंडवा महल, छेरकी महल सहित अन्य मंदिरों की नक्काशी देखने लायक है। वर्ष 1349 में नागवंशी राजा रामचंद्र देव और राजकुमारी अंबिका देवी की शादी की याद में मड़वा महल यानी दुल्हादेव बनवाया गया था। इस परिसर की बाहरी दीवारों पर कामासूत्र में दर्शाई गई 54 मुद्राएं बनी हुई हैं। एक मंदिर में अधगढ़ा शिवलिंग स्थित है। मंदिर की छत पर कमल के आकार में शिल्पकारी की हुई है।

प्रकृति को निहारने आइए सरोधा दादर: जिला मुख्यालय से 50 किमी की दूरी पर मध्यप्रदेश की सीमा पर चिल्फी घाटी स्थित है। यहां से दाहिने दिशा में पांच किमी ऊपर सरोधा दादर ग्राम में पहाड़ पर 11 एकड़ की भूमि पर एक बैगा एथनिक रिसार्ट बनाया गया है। इस पर्यटन ग्राम में वुडन व डीलक्स हाउस बने है। चिल्फीघाटी और सरोधा-दादर में प्रकृति का आनंद लेने के लिए सालभर देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही रहती है। सरोधा-दादर और पीड़ाघाट के पास एक वाच-टावर भी बनाया गया है, जहां से लोग पर्वत और घाटी के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। जिले में मुख्य रूप से बैगा आदिवासी निवास करते हैं, इनकी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति आकर्षित करती है। ट्रेकिंग व कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं।

लुभाता है जलाशयों का दृश्य: हरी-भरी पहाड़ियों के घिरे सरोधा जलाशय में पर्यटक स्पीड बोट, वाटर स्कूटर और कैंपिंग कर सकते हैं। यहां से मैकल पर्वत श्रृंखला की खूबसूरती देखते ही बनती है। छीरपानी जलाशय का नयनाभिराम दृश्य भी पर्यटकों को लुभाता है। यहां घने जंगल के बीच स्थित रानीदहरा जल प्रपात, दुरदुरी जलप्रपात, मांदाघाट जलप्रपात भी है। रानीदहरा बोड़ला से चिल्फी मार्ग पर कवर्धा से लगभग 35 किमी की दूर है। अभयारण्य के घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित रानीदहरा जल प्रपात का सौंदर्य सावन में पूरे उत्कर्ष पर होता है। यहां करीब 40 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। पहाड़ी रास्तों के बीच ठंडी हवाएं पर्यटकों को सुकून देती है।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

प्रांत प्रचारक बैठक में शताब्दी वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा

जासं, रांची: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय प्रांत प्रचारक बैठक 12 जुलाई से रांची में होगी। सरसंघचालक मोहन भागवत व सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में अगले वर्ष होने वाले संघ के शताब्दी वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा होगी। संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में बड़े कार्यक्रम नहीं कर छोटे-छोटे कार्यक्रम करने की योजना बनाई है, परंतु इसका स्वरूप क्या होगा, यह अभी तय नहीं है। इस बार की बैठक में इस विषय को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक में भाग लेने के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत सहित छोटी टोली के सभी सदस्य आठ जुलाई को रांची पहुंच जाएंगे। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, सभी 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सहयोगी, सभी क्षेत्र प्रचारक व प्रचारक प्रमुख शामिल होंगे।

****

दैनिक जागरण
आत्मा स्वयं को परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ी है

ढहता आधारभूत ढांचा

यह अच्छा हुआ कि बिहार सरकार ने एक के बाद एक पुल गिरने की घटनाओं को देखते हुए अनेक इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। इस तरह की कार्रवाई इसलिए आवश्यक थी, क्योंकि पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। यह सामान्य बात नहीं कि महज 15 दिनों के अंदर एक दर्जन पुल गिर जाएं। बिहार में इसके पहले भी कई पुल गिर चुके हैं। एक-दो पुल तो ऐसे रहे, जो निर्माणाधीन स्थिति में ही ध्वस्त हो गए। इसे देखते हुए यह आवश्यक था कि बिहार सरकार कोई ठोस कदम उठाती। उसने कई विभागों के इंजीनियरों को निलंबित करने के साथ ही पुलों का निर्माण करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनका भुगतान रोकने की पहल की है। उसने कंपनियों से यह भी पूछा है कि क्यों न उन्हें काली सूची में डाल दिया जाए? यदि ऐसी कंपनियों की गलती पाई जाती है तो उन्हें न केवल काली सूची में डाला जाना चाहिए, बल्कि उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि वे नाम बदलकर फिर से सक्रिय न होने पाएं। यह तो किसी जांच से ही सामने आएगा कि नए-पुराने पुल इतनी जल्दी-जल्दी क्यों गिरते रहते हैं, लेकिन इसकी भरी-पूरी आशंका है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण दोयम दर्जे का निर्माण है। यह समस्या केवल बिहार की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की है। पिछले ही दिनों झारखंड से यह खबर आई कि वहां सुंदर नदी पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही धंसने लगा। इस तरह के मामले देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आते रहते हैं।

एक आंकड़े के अनुसार 2012 से 2021 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे-बड़े दो सौ से अधिक पुल गिर चुके हैं। बात केवल पुलों की ही नहीं, सड़कों, एक्सप्रेसवे और आधारभूत ढांचे से जुड़े अन्य निर्माण कार्यों की भी है। आखिर यह एक तथ्य है कि पिछले दिनों दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की एक छत गिर गई। इसी तरह की घटना जबलपुर और राजकोट हवाईअड्डे पर भी हुई। वास्तव में अपने देश में बरसात का मौसम आधारभूत ढांचे की पोल खोलने का काम करता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, क्योंकि पुलों के गिरने और सड़कों के धंसने के मामले रह-रहकर सामने आते ही रहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आधारभूत ढांचे के निर्माण में लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। यह लापरवाही कमीशनखोरी की ओर ही साफ संकेत कर रही है। यह ध्यान रहे तो अच्छा कि आधारभूत ढांचे का तेज गति से निर्माण होने के साथ ही खराब गुणवत्ता के कारण उसके नष्ट होते रहने का सिलसिला प्रगति को थामने के साथ ही संसाधनों की बर्बादी और देश की बदनामी का भी कारण बनता है।

भ्रष्टाचार का परिणाम

बिहार और झारखंड में मानसून के शुरू होते ही लगातार पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार में अब तक दस से अधिक पुल ध्वस्त हो गए हैं। वहीं, झारखंड में मानसून की पहली बारिश के साथ ही निर्माणाधीन पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी है। गिरिडीह के अरगा नदी में बारिश के पानी के बहाव में फतेहपुर-भेलवाघाटी के बीच पांच करोड़ रुपये की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। इस प्रकार गोड्डा के सुंदर नदी पर पांच करोड़ रुपये की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही धंसने लगा। इस तीन साल पहले खूंटी जिले में कांची नदी पर 13 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल का पिलर अचानक आई तेज बरसात में धंस गया। इसी क्षेत्र में पहले भी दो पुल धंस चुके थे। उन पुलों का निर्माण भी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, जिसने यह पुल बनाया था। बरसात के मौसम में बिहार की तरह झारखंड में भी पुलों के धंसने व टूटने की घटना हर साल होती है। यह कुछ घटनाएं एक बानगी है, जो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की कहानी को बयां कर जा रही हैं। नदियों से हो रहे बालू के अवैध खनन भी इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। खूंटी के पास पुल धंसने की घटना की एक वजह पुल के पिलर के पास से बालू का अवैध खनन माना जा रहा था। जिससे पिलर को मजबूती नहीं मिली और धंस गया। झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो पाने से अवैध तरीके से नदियों से बेतहाशा का बालू का उत्खनन किया जाता है। अवैध खनन करने वाले लोग सारे नियम-कायदे को तोड़ कहीं से भी खनन करना शुरू कर देते हैं। जो इस तरह के हादसों का मुख्य कारण बनते हैं। इससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। ऐसे में जरूरत है, इस पर कड़ी कार्रवाई की।

झारखंड में भी मानसून की पहली बारिश के साथ ही निर्माणाधीन पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी है

संविधान बदलने का फर्जी विमर्श

उमेश चतुर्वेदी

इसकी जानबूझकर अनदेखी की जा रही है कि मोदी सरकार के विगत दस वर्षों के शासन में आठ संविधान संशोधन हुए और इन सभी का समर्थन विपक्ष ने किया

बीते दिनों लोकसभा सदस्यों की शपथ के दौरान कुछ सदस्यों ने संविधान की प्रतियां भी लहराईं। संसद के भीतर और बाहर लहराई जाने वाली संविधान की इन प्रतियों का रंग भले ही अलग हो, लेकिन उद्देश्य एक था। वह यह कि संविधान बदलने के नैरेटिव को बनाए रखना। इसी नैरेटिव ने विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव में सफलता दिलाई और वे भाजपा को सीमित रखने में सफल रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव या फिर उनके अन्य साथी, वे अभी भी इसी नैरेटिव पर अटके हैं। भाजपा के चार सौ पार के नारे और कुछ नेताओं की संविधान बदलने के लिए बहुमत की जरूरत वाली टिप्पणियों के सहारे विपक्ष ने सत्ता विरोधी नैरेटिव का कोलाज रच दिया। इसका उसे फायदा भी मिला। इसलिए विपक्ष चाहता है कि यह नैरेटिव जिंदा रहे और भाजपा सवालों के घेरे में रहे। वोटरों के मन में संदेह बना रहे, ताकि विपक्षी दल आगामी विधानसभा चुनावों में वोटों की अपनी फसल काट सकें। जल्द ही महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके कुछ ही समय बाद झारखंड में भी चुनाव होंगे। इसलिए विपक्ष इस माहौल को भुनाए रखना चाहता है।

सवाल उठता है कि क्या भाजपा सचमुच संविधान विरोधी है? अगर वह संविधान विरोधी है तो विपक्ष ने उसके द्वारा लाए गए संविधान संशोधन प्रस्तावों का साथ क्यों दिया? लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की काट नहीं कर पाई। पता नहीं कैसे वह भूल गई कि मोदी सरकार के दस साल के कार्यकाल में हुए ज्यादातर संविधान संशोधनों को विपक्ष ने ही सहयोग-समर्थन देकर पारित कराया। मोदी सरकार के विगत दस वर्षों के शासन में आठ संविधान संशोधन हुए। दिलचस्प यह है कि इन सभी संशोधनों का समर्थन विपक्ष ने किया। मोदी सरकार ने शुरुआत में ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने को लेकर संविधान संशोधन किया, जिसे समूचे विपक्ष ने समर्थन दिया था। यह बात और है कि पारित होने के तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जीएसटी लागू करने लिए भी संविधान संशोधन किया गया। इसका भी कांग्रेस समेत तकरीबन पूरे विपक्ष ने समर्थन किया था। चूंकि यह संघीय ढांचे से जुड़ा संविधान संशोधन था, इसलिए संविधान के अनुच्छेद-368 के प्रविधानों के तहत इसे कम से कम आधे या उससे ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं का भी समर्थन मिलना जरूरी था। जीएसटी लागू करने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों की ओर से भी मिली।

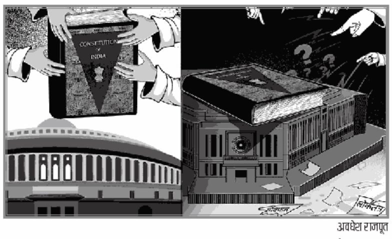

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार का तीसरा संविधान संशोधन प्रस्ताव 'पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। इसे भी विपक्ष का साथ मिला। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला कानून भी संविधान संशोधन के ही दायरे में आता है। इसे भी विपक्षी दलों के सहयोग से ही सरकार पारित करा पाई। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और एससी-एसटी आरक्षण की समयसीमा बढ़ाने वाले संविधान संशोधन को भी संसदीय मंजूरी में विपक्ष की ओर से कोई बाधा नहीं खड़ी की गई। इसी तरह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में जातियों को जोड़ने का जो अधिकार दिया गया, वह भी संविधान संशोधन ही था। इस पर भी मोदी सरकार को विपक्षी दलों का सहयोग मिला। मोदी सरकार ने वित्त आयोग के अधिकारों में परिवर्तन को लेकर भी संविधान संशोधन प्रस्तुत किया। विपक्ष को इसे भी पारित कराने में कोई आपत्ति नहीं रही।

हालांकि सवाल यह भी है कि जब पिछड़ा वर्ग को अधिकार देने की बात हो, वित्त आयोग को और अधिकार देने की बात हो, कमजोर आय वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, तब भला कौन राजनीतिक दल इससे इन्कार कर सकता है? हमने जिस राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया है, उसमें विरोधी दल को सत्ता पक्ष को कठघरे में खड़ा करने और वोटों की राजनीति में मात देने के लिए हर वक्त मुद्दों की तलाश रहती है। चूंकि राजनीतिक व्यवस्था में गिरावट आ गई है और दलीय वैचारिक एवं सैद्धांतिक आधार लगातार कमजोर हुए हैं, इसलिए राजनीति के लिए अधिकांश मुद्दे ऐसे तलाशे जाते हैं, जिनका हकीकत से कोई खास लेनादेना न हो। संविधान को बदलने या हटाने का नैरेटिव या मुद्दा इसी तरह का मामला है। विवादित 42वें संविधान संशोधन को छोड़ दें तो ज्यादातर मौकों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष ने मिलकर ही संविधान संशोधन किए हैं। संविधान संशोधन का मुद्दा भी बहुत पेचीदा है। किसी भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लिए संविधान में बदलाव विपक्ष को साथ लिए बिना बहुत आसान नहीं है।

आरक्षण का नैरेटिव जिस बिंदु पर पहुंच गया है और भारत की जो जटिल जातीय संरचना है, उसमें शायद ही कोई दल होगा, जो बिना राष्ट्रीय सहमति के इस सिलसिले में कोई संवैधानिक बदलाव कर सके। केशवानंद भारती केस हो या फिर मिनर्वा मिल्स मामला, जब सर्वोच्च न्यायालय संविधान के मूल ढांचे में बदलाव न किए जाने का फैसला दे चुका है, तब ऐसी स्थिति में क्या कोई दल किसी एक सदन में बहुमत हासिल करने के बाद संविधान में आमूलचूल परिवर्तन कर पाएगा? निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब 'नहीं' में ही आएगा। अतीत के अनुभव भी इसी ओर इशारा करते हैं। मामले को देखते हुए सरकार ने भी इस नैरेटिव के संदर्भ में विपक्ष को आक्रामक अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है।

स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपातकाल ऐसा काला धब्बा है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। बेशक इसके लिए इंदिरा गांधी दो बार माफी मांग चुकी हैं, लेकिन यह माफी कुछ वैसी ही है, जैसे किसी की हत्या कर दी जाए और फिर माफी मांगकर अपराधबोध से मुक्ति का प्रयास हो। संविधान की प्रतियां दिखाकर सरकार पर सवाल उठाने की विपक्ष की कोशिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए जिस तरह केंद्र सरकार ने आपातकाल का मसला उठाया है, उससे कांग्रेस असहज है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उसके साथ खड़े ज्यादातर सहयोगी दल आपातकाल के पीड़ित रहे हैं और उस दौर में वे भाजपा के पूर्व अवतार जनसंघ के साथ खड़े रहे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

उचित नहीं नीट के खात्मे की मांग

प्रो. निरंजन कुमार

यह ध्यान रहे तो बेहतर कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश की पुरानी व्यवस्था में परेशानी का कोई ठिकाना न था

उपयोगी है नीट जैसी केंद्रीकृत परीक्षा। एएनआइ

फ्रेडरिक नीत्शे का कथन है कि मूल्यांकन करना ही हमारे द्वारा मूल्यवान समझी जाने वाली सबसे मूल्यवान चीज है... मूल्यांकन के बिना अस्तित्व का सार खोखला होगा। व्यावहारिक संदर्भों में इसे समझें तो परीक्षा वह महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों-परीक्षार्थियों का सम्यक मूल्यांकन होता है। परीक्षा का मूल्य तब और बढ़ जाता है जब इसके माध्यम से उच्चतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अथवा रोजगार का मार्ग खुलता है। परीक्षा प्रणाली की शुचिता किसी भी उन्नत समाज या देश के लिए बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से विभिन्न राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं हों, लोक सेवा आयोग अथवा अन्य संस्थाओं की परीक्षाएं हों, इनकी शुचिता पर सवाल उठते रहे हैं। इस कड़ी में ताजातरीन घटनाक्रम है नीट (मेडिकल प्रवेश परीक्षा), यूजीसी-नेट या सीएसआइआर परीक्षाओं को लेकर उठा विवाद, जिसने परीक्षा व्यवस्था से लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों के हित में समस्या का उचित हल निकालने की जगह इस मुद्दे पर राजनीतिक दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। विपक्षी दल इसे रद करने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में नवीनतम पेच है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, जिसमें नीट परीक्षा को ही समाप्त करने की मांग की गई है। ऐसी मांग कुछ और दल भी कर रहे हैं। इस मुद्दे के प्रशासनिक, तकनीकी और राजनीतिक पक्ष हैं और इसका समाधान राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर छात्रहित में ही होना चाहिए।

इसमें संदेह नहीं कि नीट में खासी चूक हुई है। परीक्षा एजेंसी 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' (एनटीए) मुख्य रूप से कठघरे में है। हालांकि सरकार ने उचित कार्रवाई करते हुए एनटीए प्रमुख को हटाकर एक नए सक्षम अधिकारी को एनटीए का दायित्व तो दिया ही, सीबीआइ जांच भी बैठा दी है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सरकार की गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि स्वयं राष्ट्रपति के संसदीय अभिभाषण में नीट मुद्दे का उल्लेख हुआ। वहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए पूर्व इसरो चेयरमैन के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डाटा सुरक्षा प्रोटोकाल और एनटीए की संरचना पर अनुशंसा देगी। केंद्र ने पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 जैसे सख्त कानून को भी अधिसूचित कर दिया है। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। इस मामले में सीबीआइ को यह जांच भी करनी चाहिए कि क्या इस मामले में कोई अंतरराष्ट्रीय कड़ी भी जुड़ी है? ध्यातव्य है कि नीट परीक्षा 12 अन्य देशों में भी आयोजित की गई थी। पेपर लीक में डार्कनेट की भूमिका भी देखी जा रही है। रही बात नीट को रद करने की तो अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उसका निर्णय जो भी हो, लेकिन ममता बनर्जी और एमके स्टालिन द्वारा नीट परीक्षा की व्यवस्था को ही समाप्त कर देने की मांग कहीं से भी उचित नहीं। तमिलनाडु के अन्य नेता भी नीट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

ममता बनर्जी ने लिखा है कि गड़बड़ियों के मद्देनजर नीट परीक्षा को समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के मेडिकल कालेजों में एडमिशन के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती थीं। उनके अनुसार इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं थी, लेकिन ममता का यह तर्क दमदार नहीं। पुरानी व्यवस्था में छात्रों की परेशानी का तो कोई ठिकाना नहीं था। एक ही मेडिकल पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश के लिए दर्जनों अलग-अलग परीक्षाएं होती थीं। एम्स, बीएचयू, एएमयू, पुडुचेरी, सीबीएसई, एएफएमसी के अतिरिक्त सभी राज्यों की अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं होती थीं। फिर विभिन्न प्राइवेट कालेजों की अपनी अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं भी होती थीं। निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सभी परीक्षाओं में बैठना असंभव था। उच्च मध्यम वर्ग का छात्र भी इतनी ज्यादा परीक्षाओं को देते-देते पस्त हो जाता था। समय, धन, ऊर्जा की बर्बादी अलग होती थी। इन्हीं जटिलताओं के कारण 2017 से एकीकृत मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट शुरू हुई। नीट की विसंगतियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, न कि इस नई व्यवस्था को खत्म करने की।

ममता बनर्जी के अनुसार वर्तमान प्रणाली ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। यहां जानना जरूरी है कि केंद्र या राज्य सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो, प्रवेश परीक्षाओं या रोजगार परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। उनका यह कथन भी तर्कसम्मत नहीं कि एकात्मक-केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली देश के संघीय ढांचे की भावना का उल्लंघन करती है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। अतः जनहित में केंद्र ऐसे निर्णय ले सकता है। राज्यों में आइएएस और आइपीएस की नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्तर पर यूपीएससी द्वारा एक केंद्रीकृत परीक्षा दशकों से आयोजित की जा रही है। अगर ममता की बात मान ली जाए तो फिर इंजीनियरिंग, कानून या अन्य प्रवेश परीक्षाओं में भी ऐसी मांगें उठेंगी, जो नई समस्याओं को जन्म देगा। यहां समझना जरूरी है कि अलग-अलग परीक्षाओं वाली व्यवस्था का ज्यादा लाभ अमीर छात्रों को ही मिलेगा। नीट का विरोध और उसे समाप्त करने की मांग कहीं से जायज नहीं। नीट और इस जैसी अखिल भारतीय केंद्रीकृत परीक्षाएं देश हित में हैं। यह जरूर है कि इनकी शुचिता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि ईमानदार-प्रतिभावान अभ्यर्थियों के साथ भविष्य में छलावा न हो।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर और डीन आफ प्लानिंग हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य की महत्ता

जीवन में सत्य की भूख तो सभी को होती है, लेकिन जब कभी भी सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। सत्य के संबंध में जानना और सत्य का मर्म समझ लेना दोनों में बड़ा अंतर है। तैरने के संबंध में पढ़ा गया महाशास्त्र भी तैरने की कला में पारंगत नहीं बना सकता। तैरना सीखने के लिए तो जलराशि में ही उतरना पड़ेगा। इसी प्रकार हम सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म और आत्मा-परमात्मा आदि के विषय में अत्यधिक जानकारियां संग्रहित किए हुए हैं। हालांकि, ये जानकारियां सिर्फ सुनने का साधन और बोलने की परंपरा बनकर रह गई हैं और हमारे आचरण में नहीं उतर पाईं। जैसे कागज की नाव से समुद्र पार नहीं किया जा सकता वैसे ही इन सभी बातों को मात्र पढ़-सुन कर ही हम अभीष्ट की प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञान और विचार के साथ उसे आचरण में उतारने की मनोवृत्ति भी आवश्यक होती है।

सत्य अकाट्य है। द्वेष उस पर हमला कर सकता है। अज्ञानता उसका उपहास उड़ा सकती है, किंतु अंत में सत्य का अस्तित्व ही रहता है। हमारे जीवन में समय अत्यंत मूल्यवान होता है, क्योंकि जो क्षण एक बार निकल गया वह दोबारा जीवन में लौटकर नहीं आता, लेकिन सत्य का मूल्य उससे भी अधिक होता है। केवल इसीलिए नहीं कि इसके लिए अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, बल्कि इसलिए भी यह कहीं अधिक मूल्यवान होता है। सत्य स्वयं में एक ऐसा मूल्य है जिस पर विश्वास, ईमानदारी, संवेदनशीलता, दया और अपनत्व जैसे अन्य मूल्य भी टिके हुए हैं। इन्हीं मूल्यों पर टिकी है मानवता।

सत्य मानवीय अस्तित्व का आधार है। सत्य पूरी मानव जाति को मानवतावादी बनाता है। सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, लेकिन किसी के लिए भी सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता। कितना ही भयंकर तूफान हो, उनसे सत्य की नाव डगमगा सकती है, लेकिन अपने सवार को डुबोएगी नहीं, किसी न किसी प्रकार किनारे पहुंचा ही देगी।

डा. निर्मल जैन

गतिहीन जीवनशैली का सेहत पर असर

देवेंद्रराज सुथार

देश में लगभग 50 प्रतिशत लोग पर्याप्त शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जिस कारण वे अस्वस्थ हो रहे हैं

सेहतमंद आबादी किसी भी राष्ट्र की प्रगति की रीढ़ होती है। जब नागरिक स्वस्थ होते हैं, तो वे अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देते हैं, सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। लेकिन आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के बावजूद भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में भारत में लगभग 50 प्रतिशत लोग पर्याप्त शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जो उन्हें अस्वस्थ बना रहा है। भारतीय कुल मिलाकर एक घंटे भी नियमित रूप से कसरत नहीं करते हैं।

वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने हर सप्ताह 150 मिनट मीडियम एक्सरसाइज या फिर हर हफ्ते 75 मिनट फास्ट स्पीड एक्सरसाइज करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी इस गाइडलाइन को पूरा नहीं कर रही है। अगर यही हाल रहा, तो 2030 तक भारत की करीब 60 प्रतिशत आबादी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात पर जोर देता रहा है कि शारीरिक गतिविधि की कमी से मधुमेह और हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। ये बीमारियां भारत में पहले से ही प्रचलित हैं और निष्क्रियता की बढ़ती दरें स्थिति को और भी बदतर बना सकती हैं। इन बीमारियों में संभावित वृद्धि से स्वास्थ्य सेवा की लागत बढ़ सकती है और उत्पादकता में कमी आ सकती है, जिससे देश के संसाधनों पर और भी ज्यादा दबाव पड़ सकता है।

गतिहीन जीवनशैली के लिए कई कारक योगदान करते हैं। एक प्रमुख कारक तकनीक पर बढ़ती निर्भरता है। स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा और मनोरंजन ने एक अधिक गतिहीन जीवनशैली को जन्म दिया है। लोग (विशेष रूप से युवा पीढ़ी) अपने फोन पर काफी समय बिताते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध समय कम हो जाता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र के उदय के साथ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अब ऐसी नौकरियों में लगा हुआ है, जिनमें लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, जिससे शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं।

शहरीकरण और व्यायाम के लिए सार्वजनिक स्थानों में कमी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई शहरों में पैदल चलने या कोई खेल खेलने जैसी शारीरिक गतिविधियों के लिए पार्क और खुली जगहों की उपलब्धता सीमित है। शारीरिक गतिविधि को प्राथमिकता देकर और सक्रिय जीवन का समर्थन करने वाले वातावरण का निर्माण करके भारत अपनी आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार कर सकता है और राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। **(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)**

मेलबाक्स

निराश करती संसदीय कार्यवाही

'संसद के न चलने का खतरा' शीर्षक से लिखे आलेख में राहुल वर्मा ने देश में मौजूद तमाम समस्याओं के बीच बढ़ते संसदीय गतिरोध को भी देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। लेखक का मत है कि स्वस्थ चर्चा एवं बहस को दरकिनार कर संसद का चुनावी मंच के तौर पर इस्तेमाल संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना है। संसद में संविधान की प्रतियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन क्या उन सिद्धांतों का व्यावहारिक तौर पर पालन किया जा रहा है, जो उसमें उल्लिखित हैं। हंगामा करना और आसन के निकट आकर शोरशराबा करना क्या सांसदों को शोभा देता है? क्या उनकी इस प्रवृत्ति से देश की जनता का भला होगा? कल ऐसे दृश्य देश की विधानसभाओं में देखने को मिलेंगे। फिर स्थानीय स्वशासन की विभिन्न इकाइयों में दिखेंगे तब लोग पंचायत की सबसे बड़ी इकाई का उदाहरण देंगे। तब माननीयों के लिए यह स्थिति असहज होगी। चुनाव खत्म हो गया, मगर हमेशा चुनावी मोड में रहने की अवस्था को और ऐसे आचरण से आखिर उनके प्रति लोगों की क्या धारणा बनेगी? इस दिशा में सरकार को भी सार्थक संवाद की कुछ पहल करनी चाहिए, क्योंकि सदन को सुचारु रूप से चलाना सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की साझा जिम्मेदारी है।

mukeshkr.m7542@gmail.com;

परीक्षा पर आनलाइन चर्चा

दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार परीक्षा पर आनलाइन चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी नीट-यूजी व यूजीसी-नेट की प्रवेश परीक्षाओं में हुई धांधली एवं अन्य परीक्षाओं के रद होने के विषय पर छात्रों से संवाद करें और भविष्य के प्रति उनकी चिंता एवं प्रवेश परीक्षाओं के स्वरूप को बदलने के लिए अपनी दृष्टि से अवगत कराएं। नीट और यूजीसी-नेट की परीक्षाओं में धांधली और इसके बाद लगातार चल रही जांच के बीच छात्रों का एक बड़ा वर्ग व्यथित है। कोचिंग संस्थानों की संदिग्ध भूमिका ने उन गरीब छात्रों को और भी परेशान किया है जो कोचिंग का महंगा खर्च उठाने की स्थिति में ही नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोचिंग संस्थानों के संबंध में भी छात्रों के साथ अपने विचार साझा करेंगे तो समाधान भी निकलने की संभावना है। कोचिंग संस्थानों की समस्या केवल उच्च शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, फैलोशिप, प्रबंधन की प्रवेश परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटी कक्षाओं और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी है। यह तो सरकार को भी पता है कि निजी क्षेत्र में शिक्षा बहुत महंगी है और सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की राज्य सरकारों को सुध नहीं है तो गरीब बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या स्कूल और कालेज अपने स्तर पर मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को निश्शुल्क कोचिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्या स्कूल और कालेज अपने पुस्तकालय नहीं स्थापित कर सकते, जहां प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पुस्तकें और गाइड सुलभ हो सकें। ये सभी विषय प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा के लिए सार्थक एवं महत्वपूर्ण होंगे।

विनोद जौहरी, दिल्ली

झूठ का पर्दाफाश

हाल ही में हम सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी ने कैसे झूठ का सहारा लेकर कहा कि भाजपा सरकार आई तो संविधान खत्म कर देगी और आरक्षण भी समाप्त कर देगी। इस तरह की अफवाह फैलाकर देश की जनता को बरगलाया और अपेक्षा से अधिक सीटें पाने में सफलता हासिल की। इसके बाद राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी यह रवैया नहीं बदला और एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। इस तरह छल-कपट की प्रणाली उनके और देश दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस संबंध में न केवल लोकसभा अध्यक्ष, बल्कि सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और राहुल गांधी को गैर जिम्मेदारी वाले अपने रवैये को तुरंत बंद करना चाहिए। सर्वविदित है कि कांग्रेस दस वर्ष से सत्ता से बाहर है और पार्टी के नेताओं को इस बार भी विपक्ष में बैठना पड़ा है तो प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस के नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं।

बाल गोविंद, सेक्टर 44, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

8.55 लाख सहकारी समितियां कार्यरत हैं भारत में, जिनसे लगभग 13 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं देश के करीब 91 प्रतिशत गांवों में कोई न कोई सहकारी समिति कार्य कर रही है।

आजकल

प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अंकुश

भारत जैसे देश में शिक्षा और नौकरी के लिए योग्यता मापने की किसी भी परीक्षा का आयोजन स्वयं में एक बड़ी चुनौती है। फिर नकल और पेपर लीक जैसी धांधलियां होने लगें, उनमें फर्जीवाड़े से कुछ उम्मीदवारों की नैया पार लगाने के उपक्रम सामने आने लगें और परीक्षाएं आयोजित कराने वाला तंत्र जब–तब सवाल उठने पर बगलें झांकने लगे, तो लाखों युवाओं की हताशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले दिनों आयोजित हुई कई परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है जो आजकल चिंता का विषय बन गया है

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न करवाने की चुनौती निरंतर बढ़ती जा रही है। फाइल

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से कराई गई नीट परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस परीक्षा पर पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स समेत तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगे। इस बीच परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं के एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग सीटों के आवंटन हेतु दाखिले की प्रक्रिया में काउंसलिंग शुरू होने को है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट को पेपर लीक, परीक्षा रद करने की मांग और परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित कई याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई कर कोई निर्णय देना है। पर इस बीच ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि भविष्य में आइआइटी, जेईई मेन या जेईई एडवांस्ड की तरह नीट (यूजी और संभवतः पीजी भी) के लिए भी कंप्यूटर आधारित यानी आनलाइन परीक्षा को अपनाया जा सकता है। हालांकि यहां एक बड़ा सवाल यह है कि जब दूसरी कई परीक्षाएं पहले से ही आनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जा रही हैं तो एनटीए को नीट परीक्षा पेन-पेपर वाले तरीके से कराने की क्या जरूरत थी। कहीं इसका उद्देश्य कतिपय लोगों को वह चोर रास्ता मुहैया कराना तो नहीं था जो आनलाइन परीक्षा में शायद अब मुमकिन नहीं रहा है।

धांधली और गड़बड़ी से मुक्ति : अगले साल से नीट परीक्षा आनलाइन तरीके से कराने पर गंभीरता से विचार हो सकता है। अभी पेन-पेपर तरीके से यानी आफलाइन कराई जा रही इस परीक्षा में बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं, जिनके जवाब एक शीट पर भरने होते हैं। आफलाइन परीक्षा चाहे बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली हो या उसमें विस्तृत जवाब लिखने हों, उसमें एक महत्वपूर्ण सुविधा यह है कि बिजली चले जाने, बैटरी बैठ जाने या कंप्यूटर-इंटरनेट नेटवर्क ठप हो जाने की सूरत में परीक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही, जो युवा कंप्यूटर-इंटरनेट की प्रणालियों को अच्छी तरह नहीं समझते, उन्हें भी पेन-पेपर वाली परीक्षा में सुविधा रहती है। हालांकि आज के मोबाइल-इंटरनेट के दौर में यह मानना थोड़ा कठिन है कि किसी छात्र को कंप्यूटर की कामकाजी जानकारी नहीं होगी। फिर भी हर किसी को बराबरी का अवसर देने के नजरिये से आफलाइन परीक्षा की पक्षधरता अधिक ही होगी। लेकिन यह दावा नहीं किया जा सकता कि आनलाइन परीक्षा हर किस्म की धांधली और गड़बड़ियों से मुक्त ही होगी। वैसे इन समस्याओं में से खासकर पेपर लीक की रोकथाम के लिए सुझाव यह दिया जा रहा है कि इसका अंतिम प्रश्नपत्र परीक्षा के आयोजन से दो घंटे पहले तैयार किया जाएगा। ऐसी अवस्था में यदि कोई गिरोह साइबर सेंधमारी कर पेपर उड़ा भी लेता है, तो उसे लाखों रुपये देकर हासिल करने वालों तक पहुंचाने का समय नहीं मिल पाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि पेपर लीक जैसी घटना किसी बाहरी व्यक्ति या गिरोह की कोशिशों का अंजाम नहीं होती।

परीक्षा की पवित्रता के तीन मुद्दे : इस तरह परीक्षाओं की पवित्रता कायम रखने का मुद्दा तीन अहम जरूरतों से संबद्ध होता है। पहला, क्या परीक्षा का आनलाइन आयोजन उसकी स्वच्छता और सफलता की गारंटी है। दो, क्या इसमें पेपर लीक कराने वाले तंत्र और कोई भी कीमत चुकाकर प्रश्न पत्र हासिल करने वाले समाज की नैतिकता नहीं देखी जानी चाहिए। और तीन, क्या शिक्षा और नौकरी के वास्ते योग्यता मापने के लिए तीन घंटे की परीक्षा ही इकलौता उपाय है। इस अंतिम सवाल के जवाब से शायद सारी समस्याओं का हल निकल सकता है, इसलिए सबसे पहली चर्चा इसी की करनी चाहिए। पुराने जमाने में कोई नौकरी या कामकाज पाने की दो ही शर्तें होती थीं। एक तो यह कि किसी कामकाज में व्यक्ति का हुनर या जानकारी उसे पैतृक व्यवस्था के तहत मिली हो। या फिर उसने वह कौशल किसी प्रतिष्ठित गुरु या प्रख्यात संस्थान से हासिल किया हो। इन्हीं कसौटियों के आधार व्यक्ति को संबंधित कामकाज या कौशल में निपुण मान लिया जाता था और उसे वह काम सौंप दिया जाता था। परंतु डाक्टर और इंजीनियर जैसे पेशों के लिए आला दर्जे की पढ़ाई तक के लिए परीक्षाएं जरूरी हैं। इससे लगता है कि हमारा देश ज्ञान और कौशल में पारंगत करने वाले तंत्र के स्थान पर सिर्फ परीक्षा कराने वाले तंत्र में बदल गया है, जहां ज्यादातर मामलों में तीन घंटे की परीक्षा में अव्वल आना ही सर्वोत्तम योग्यता है।

नैतिकता का सवाल : नकल व पेपर लीक में शामिल लोगों की नैतिकता का प्रश्न महत्वपूर्ण है। अपने लालच के लिए हर धांधली करने को तैयार बैठा सिस्टम ऐसे लोगों की मदद करने और उन्हें दाखिला दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। सोचना होगा कि आखिर क्या बात है कि परीक्षाओं में धांधली रोकने के सारे आश्वासन अब तक कोरे ही साबित हुए हैं। शायद ही कोई परीक्षा ऐसी बची हो, जिसमें पेपर लीक जैसे किसी फर्जीवाड़े का पता नहीं चलता हो। धांधली रोकने के चाहे कितने ही इंतजाम कर लिए जाएं, परीक्षा नेटवर्क में शामिल कोई न कोई कमजोर कड़ी हर वक्त मौजूद रहती है जो लालच के सामने घुटने टेक देती है। एक या एकाधिक लोगों की करतूत लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर तुषारापात कर देती है और परीक्षा करने वाली एजेंसियों से लेकर सरकारें तक कोरी बयानबाजी करके रह जाती हैं।

परीक्षाओं के आनलाइन का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है, जिसे एक झटके में सारी समस्याओं के हल की तरह देखा जा रहा है। करीब डेढ़ दशक पहले हमारे देश में आनलाइन परीक्षाओं के व्यापक आयोजन का सिलसिला इस नजरिए के साथ शुरू किया गया था कि उससे फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। वर्ष 2009 में आइआइएम की संयुक्त परीक्षा (कैट) का एक ही समय में सैकड़ों केंद्रों पर एक साथ कराने का जिम्मा यह कहकर लिया गया था कि इसमें पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं हो सकती। लेकिन जीमैट एवं जीआरई जैसी परीक्षाएं आयोजित करने वाले संगठन (कंपनी) प्रोमेट्रिक के इंतजामों की पोल परीक्षा के पहले ही दिन खुल गई थी। उस समय देश के नौ शहरों के 11 केंद्रों की परीक्षा रद करनी पड़ी थी, क्योंकि आनलाइन परीक्षा के आयोजन में सांगठनिक तालमेल कायम नहीं हो पाया था और तकनीकी खराबी ने उसमें अड़चन डाल दी थी। कहने को तो पेन-पेपर एग्जाम के मुकाबले आनलाइन परीक्षा आसान हो सकती है और इसमें निगरानी के पुख्ता प्रबंध हो सकते हैं। लेकिन ये प्रबंध करना असल में आसान नहीं हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर साफ्टवेयर की सुरक्षा जांचने के अलावा वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के प्रबंध, पावर बैकअप यानी बिजली जाने की सूरत में उसके वैकल्पिक इंतजाम, अतिरिक्त कंप्यूटरों की उपलब्धता, अतिरिक्त सर्वर, एयर कंडीशनिंग की सुविधा आदि तैयारियों का आकलन करते हुए सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी स्तर पर चूक और सेंधमारी की गुंजाइश न रहे।

यह भी पाया गया है कि अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण आनलाइन परीक्षाएं छात्रों की विश्लेषण की योग्यता, टीम वर्क, ईमानदारी, मूल्यपरकता, संवेदनशीलता, समाज-सापेक्षता जैसे महत्वपूर्ण गुणों का परीक्षण करने में असमर्थ रही हैं। यही नहीं, हमारे देश में कृषि, डेयरी उद्योग, बागवानी, परिवहन, सूचना क्षेत्र, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पर्यटन, मनोरंजन और मीडिया जैसे क्षेत्रों के लिए ऐसे होनहार युवाओं की जरूरत है, जो गांव और शहरों की गलियों, बस्तियों और खेतों में काम करने वाले आम आदमी की जिंदगी में बदलाव ला सकें। अमेरिका और यूरोप की आधुनिक शिक्षा की नकल करते हुए परीक्षाओं को आनलाइन आयोजित करके हम ऐसे समर्थ युवा नहीं तैयार कर सकते हैं। जाहिर है कि हर कोई यह चाहता है कि देश के शैक्षिक और परीक्षा के तंत्र में वे बुनियादी बदलाव लाए जाएं, जो उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यताओं की परख कर सकें। रट्टू तोते की तरह पाठ रटाने वाली शिक्षा और परीक्षा योग्यता का मानक नहीं हो सकती, यह समझ अब बनानी ही होगी।

जिंदगी बेहतर बनाने वाली शिक्षा की आवश्यकता

आनलाइन पढ़ाई और परीक्षा का समर्थन करने वालों का तर्क है कि कोई शिक्षा अपने उद्देश्य में तभी ज्यादा सफल हो सकती है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ सकें और जीवन को बेहतर बनाने वाले ज्ञान व जानकारियों से लैस हो सकें। इस नजरिए से देखें तो हाल के वर्षों में पढ़ाई और परीक्षा के आनलाइन प्रबंध तकनीकी तौर पर एक उपलब्धि लगते हैं। पढ़ाई के आनलाइन इंतजामों ने निस्संदेह देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को एक सहूलियत दी है, क्योंकि अब उन्हें घर बैठे भी पढ़ाई और ट्रेनिंग का ऐसा विकल्प मिल गया है, जिसमें वे आरंभिक ज्ञान से लेकर क्षमता बढ़ाने वाले कोर्स कर सकते हैं और कई मामलों में विशेषज्ञता भी हासिल कर सकते हैं। कोरोना से पैदा महामारी के दौरान तो सारी पढ़ाई-लिखाई आनलाइन प्रबंधों के तहत हुई। हालांकि वह पढ़ाई कितनी मुफीद है- इसके जवाब में इस जुमले को याद किया जा सकता है कि इन दो-तीन वर्षों में पढ़-लिखकर सामने आई एक पीढ़ी को कोविड-जेनरेशन कहकर पुकारा जाता है। इस जुमले का आशय है कि इन युवाओं के ज्ञान और जानकारी का स्तर बेहद उथला या आधा-अधूरा होगा। वजह यही कि उन्होंने पढ़ाई और परीक्षा का वह आनलाइन विकल्प अपनाया है जिसमें न तो यह जांचने की मुकम्मल व्यवस्था की छात्र कुछ पढ़ भी रहा है या नहीं। साथ ही, आनलाइन परीक्षा में कहीं उसने अपने जवाब केवल कापी-पेस्ट करते हुए तो नहीं दिए हैं। नौकरी तक की आनलाइन परीक्षाएं संदिग्ध मानी गई हैं। कुछ वर्ष पूर्व 2016 से जब कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी परीक्षाएं आनलाइन हुईं, कहा गया कि तब से उनमें पेपर लीक समेत ढेरों गड़बड़झाले सामने आने लगे। असल में, बात समाज और व्यवस्था (तंत्र) की नैतिकता का है। जब तक इनमें नेकनीयती का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक किसी भी परीक्षा को योग्यता मापन की सही कसौटी मानना मुश्किल है।

(डा. संजय वर्मा)

खरी–खरी

कभी राजा, कभी रंक

डा. हरीश कुमार सिंह

राजनीति में कितनी सुविधा है, कल राजा थे, फिर रंक हो गए। जैसे घूरे के दिन फिरते हैं, किस्मत चेती फिर राजा हो गए। कल जेल की रोटी तोड़ रहे थे, आज मुख्यमंत्री आवास में चैन की नींद सो रहे हैं।

गजब की राजनीति है अपने देश की। आज फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए। कल तक भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में थे। अब देश की जनता की अंतिम उम्मीद, न्याय के मंदिर, अदालत ने आपको जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपों से बरी तो नहीं किया है। आरोप तो अभी भी चस्पा हैं आपके ललाट पर। राजनीति में भी राजनीति है भाई। मुख्यमंत्री रहते हुए आपको, आपके ऊपर आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था केंद्र सरकार की कठपुतली कही जाने वाली एजेंसियों ने। एजेंसियां जिनसे वेतन लेती हैं उनका ही काम न करेंगी तो क्या विपक्षियों का करेंगी।

पांच माह पहले आपको मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर जेल में भेजा था तो क्या वह बदले की राजनीति थी। अगर वह राजनीति थी तो यह प्रतिशोध की राजनीति बंद होनी चाहिए। अगर आरोप सही थे तो अभी जमानत मिल जाने भर से क्या आप निर्दोष साबित हो गए।

कल वे मुख्यमंत्री थे, आज भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। कल तक जो आरोपी बनकर जेल में थे, अब फिर से मुख्यमंत्री बनकर संविधान के तहत राज्य सरकार चलाएंगे। जो कल तक स्वयं वकीलों के भरोसे थे, अब सीएम बनकर राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। जिस पुलिस ने कल आपको हथकड़ी डाली थी, आज वे उसके तबादले करेंगे। किस प्रकार की विडंबना है हमारे देश में कि कल जीरो बना दिए गए थे, आज हीरो हो गए। आम आदमी को इतनी सुविधा नहीं है कि कल को किसी झूठे आरोप में जेल चला जाए और जेल से लौटकर आए तो कलेक्टर बन जाए। एक बार जेल जाने मात्र से तो छोड़िए, थाने की चौखट या फाइल में नाम दर्ज होते ही आम आदमी का मामूली नौकरी का नियुक्ति पत्र भी पुलिस वेरिफिकेशन में खारिज हो जाएगा, परंतु राजनीति में आपको यह सुविधा है कि आप जेल से बेल लेकर, कुर्सी के खेल में कामयाब हो सकते हैं।

पोस्ट

अब तक भारतीय सेना पाकिस्तानियों द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज की हवा निकालती थी, पर अब उसी सेना को राहुल गांधी द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज का फैक्ट चेक भी करना पड़ रहा है। अजी हां@AjiHaaan

यह आज तक समझ नहीं आया कि भाजपा की लीगल सेल काम क्या करती है? सरकार के खिलाफ झूठ, भाजपा के खिलाफ झूठ और फर्जी एजेंडा जारी है। फिर भी, उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कदम उठते नहीं दिख रहे।
विपुल मिश्रा@vipulmishra_1

ऋषि सुनक ने जिस सहजता से हार की जिम्मेदारी ली और जीतने वाले दल को बधाई दी, क्या भारत में वैसा दिखा? तीसरी करारी शिकस्त ने यहां तो कांग्रेस और विपक्ष को विक्षिप्त सा कर दिया है। वे तीसरी बार पीएम बनने वाले मोदी को बधाई देने की औपचारिकता तक नहीं निभा सके।
ओमकार चौधरी@omkarchaudhary

सुनक ने हार की माफी के साथ विजेता को बधाई दी, वह भारत-अमेरिका के लिए मिसाल है। पुतिन के हमले से महंगाई और लिज ट्रस की नीतियों से लोन महंगे हो गए। सुनक ने उन पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया। शिव कांत@shivkant

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनने का फैसला सही है?

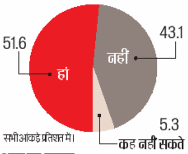

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन समाप्त होना आइएनडीआइए के टूटने की शुरुआत है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

किस मिट्टी से आजकल पुल गढ़ रहा बिहार,
बने-अधबने ढह रहे हर हफ्ते दो-चार।
हर हफ्ते दो चार अजब है ये बीमारी,
सब लोहा-सीमेंट खा रहे भ्रष्टाचारी।
लोगों का ईमान बना रोड़ी-गिट्टी से,
बना रहे पुल लोग न जाने किस मिट्टी से!
- ओमप्रकाश तिवारी

आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

नीतीश तो बने रहे, मुरेठा उतर गया

राजनीति में पत्ते हमेशा सीधे नहीं पड़ते, कभी-कभी उलटे भी पड़ जाते हैं। अब बिहार भाजपा के अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ही ले लीजिए, बिना सोचे-समझे (हो सकता है कि सोच-समझ कर) नीतीश कुमार को हटाने के लिए सिर पर मुरेठा (साफा) बांध लिया। समय ने पलटा खाया, नीतीश मुख्यमंत्री भी बने रहे और उनका दल भी साथ हो गया। तो बेचारे करते क्या, सिर घुटा कर सिर से मुरेठा उतारना पड़ा। अब सवाल शुरू हो गया कि जब इसे उतारना ही था तो छह महीने क्यों लगे? नीतीश कुमार को कुर्सी संभाले छह महीने हो गए, बीच में लोकसभा चुनाव भी बीत गए, तब उतरा मुरेठा। प्रदेश तो छोड़िए, भाजपा में ही इस प्रकरण को लेकर नकारात्मक चर्चा है।

सम्राट चौधरी तेज-तर्रार नेता हैं। कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और उसमें खासा दखल रखते हैं। जब 2020 में बिहार में राजग की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी मंत्री बने। अपने तेवरों से अक्सर नीतीश कुमार को असहज करते रहे। उनकी छवि निखरती गई। इसी बीच 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने राजग से अलग होकर महागठबंधन से नाता जोड़ लिया। यहां तक तो ठीक रहा। सितंबर में सम्राट की पूर्व विधायक माता पार्वती देवी का निधन हुआ तो मुंडन कराया गया। आम तौर पर मुंडन के बाद लोग सिर पर टोपी या गमछा रखते हैं। सम्राट ने मुरेठा बांध लिया। जब लोगों ने इस पर जिज्ञासा प्रकट की तो बोल बैठे, यह मुरेठा नीतीश को सीएम की कुर्सी से उतारने के बाद खोलेंगे। उनका संकल्प बहुत प्रचारित हुआ। राजनीतिक चितेरों ने इसे नाहक ठहराया कि कसम लेनी ही थी तो नीतीश के गद्दी पर बैठते ही लेते। अब क्यों? बहरहाल, मुरेठा चर्चा का विषय बन गया। सम्राट के तेवरों में तेजी आ गई। हर सभा-बैठक में वह नीतीश पर खुलकर बोलने लगे। उनकी चर्चा भावी सीएम के रूप में भी होने लगी।

बुधवार को अयोध्या में सरयू स्नान करने के बाद अपना मुरेठा उतारते सम्राट चौधरी। जागरण आकाईव

लेकिन समय ने पलटा खाया। नीतीश इस साल जनवरी में फिर भाजपा के साथ आ गए। सम्राट का मुरेठा बंधा रह गया और नीतीश भाजपा के समर्थन से गद्दी पर बैठ गए। नंबर दो मंत्री के रूप में सम्राट उनकी कैबिनेट में शामिल हो गए। अब मुरेठा सबको मुंह चिढ़ाने लगा। इसके औचित्य को लेकर सवाल उठने लगे तो कह दिया कि अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के चरणों में वह अपना मुरेठा अर्पित करेंगे। इस बात के छह महीने बीत गए। लोकसभा चुनाव आ गया। नीतीश के बगल में मुरेठा बांधे सम्राट जगह-जगह दिखने लगे। नीतीश भी मुरेठा देख असहज होते, पर बोलते कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बाजी पलटी और नीतीश कुमार नरेन्द्र मोदी की बैसाखी बनकर उभरे। केंद्र में सरकार उनके सहारे हो गई। पलड़ा भारी देख धुर विरोधी लोजपा (रा) के चिराग पासवान सहित भाजपा के भी तमाम नेता अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े जाने की बात कहने लगे। तब मुरेठा असहनीय जान गत बुधवार गाजे-बाजे के साथ सम्राट चौधरी अयोध्या गए और मुंडन करा कर मुरेठा उतारा। अब वे पूर्व की स्थिति में हैं।

ऐसे में देखा जाए तो सम्राट के पत्ते उलटे ही पड़े। मुरेठा बांधने की कसम तो टूटी ही, पिछली बार से कम सीटें जीतने का भी झटका लगा। उनकी कुशवाहा बिरादरी के जो वोट भाजपा के माने जाते थे, उसमें फच्चर पड़ गया। कुशवाहा वोट टूटने के कारण कई सीटें हारते-हारते बचीं, तो कुछ में हार हो गई। भाजपा को जहां पिछली बार 17 सीटें लड़कर सभी मिली थीं, तो वहीं इस बार उसे 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। उनके साथ रहे कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक चुनाव हार गए। कुशवाहा जाति के वोट राजग के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यह इससे ही जाना जा सकता है कि हारने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को राजग राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहा है तो जदयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को रिक्त विधान परिषद की सीट दे दी है। यह लगने लगा है कि सम्राट चौधरी से काम नहीं चलने वाला। अन्य नेताओं को भी साधना जरूरी है। अब इन हालातों को देखकर भाजपाई ही कहने लगे हैं कि चुनाव बाद सम्राट की हालत थोड़ी पतली हो गई है। वैसे तो लोग तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं। समय ही सम्राट का भविष्य तय करेगा।

सहकारिता दिवस

नवाचार से मिलेगी मजबूती

देश की आर्थिकी में सहकारी क्षेत्र का व्यापक योगदान है। इस क्षेत्र को पूंजी एवं तकनीक उपलब्ध कराने के साथ ही नवाचार एवं नियमन को मजबूती प्रदान कर इस योगदान को बढ़ाया जा सकता है

अरविंद कुमार मिश्रा
लोकनीति विश्लेषक

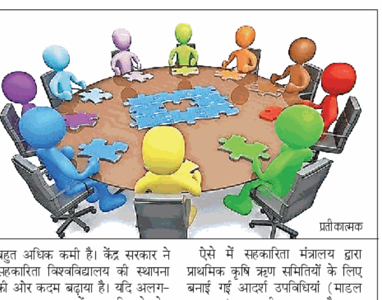

प्रतीकात्मक

देश में सहकारिता आंदोलन का इतिहास लगभग 125 वर्ष का हो गया है। आज के दिन यानी छह जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अपनी इस यात्रा के दौरान सहकारी समितियों ने सहकार से समृद्धि के अनेक सफल उपक्रम खड़े किए हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की तीन सौ सहकारी समितियों में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) पहले और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (अमूल) दूसरे पायदान पर है। दूध, चीनी, उर्वरक, बीज के उत्पादन और वितरण से लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत लगभग आठ लाख सहकारी समितियां हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं।

मोदी सरकार ने पिछले दस साल में सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। छह जुलाई 2021 सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ इन प्रयासों को न केवल बल मिला, बल्कि सहकारी समितियां उन क्षेत्रों में कदम रख रही हैं, जो नवाचार पर आधारित हैं। एथेनाल उत्पादन से लेकर बैंकिंग सेवाओं के विस्तार जैसे क्षेत्र में सहकारिता की मजबूत उपस्थिति ने इसकी प्रासंगिकता सिद्ध की है। देश में सहकारिता माडल पर विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्थापित की जा रही है।

केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की है। इससे सहकारी समितियों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। एनसीईएल द्वारा निर्यात प्रमाणन की सुविधाएं मिलने से कुटीर उद्योग से तैयार होने वाली वस्तुएं वैश्विक गुणवत्ता हासिल कर सकेंगी। आज देश में 25 हजार से अधिक पैक्स सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सहकारिता की अनेक सफलताओं के बावजूद इस क्षेत्र लिए यह समय आत्मचिंतन का है।

संबंधित नीति की प्रतीक्षा : सहकारिता क्षेत्र को लंबे समय से एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति का इंतजार है। वर्ष 2002 से चली आ रही वर्तमान नीति समय के साथ इस क्षेत्र में आई चुनौतियों के समाधान में अप्रासंगिक हो चुकी है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ ही नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर सुझाव व परामर्श का दौर शुरू हो गया था। अगले कुछ ही महीनों में इसे लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति में इस क्षेत्र से जुड़े चार बड़े मुद्दों के समाधान की दरकार है। पहला, सहकारिताओं को अपना उद्यम बढ़ाने के लिए पूंजी का संकट एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए शहरी सहकारी बैंकों की तर्ज पर यदि दुग्ध, चीनी व अन्य क्षेत्रों के लिए भी अंब्रेला (क्षत्र) संगठन बने तो अल्पकालीन पूंजी व निवेश आकर्षित कर सकेंगे। इससे छोटी सहकारी समितियां अपने कार्यक्षेत्र की बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी।

दूसरा, सहकारी समितियों में तकनीक व डिजिटल अनुप्रयोग बढ़ाने होंगे। तकनीक आधारित अवसंरचना में पिछड़ने की वजह से सहकारिताएं युवा मानव संसाधन को भी आकर्षित नहीं कर पातीं। मोदी सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की पहल का असर सहकारिताओं में आई पारदर्शिता के रूप में देखा जा सकता है। राज्य यदि सहकारिताओं के डिजिटलाइजेशन और तकनीकी उन्नयन में आगे बढ़ते हैं तो इसका प्रत्यक्ष लाभ उनकी अर्थव्यवस्था को होगा। तीसरा, सहकारिताओं को बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए शोध और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। अभी इस क्षेत्र में नवोन्मेष की बहुत अधिक कमी है। केंद्र सरकार ने सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया है। यदि अलग-अलग राज्य सरकारें सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के साथ मिलकर शोध, प्रशिक्षण को बढ़ावा दें तो इस क्षेत्र की श्रम शक्ति की दक्षता बढ़ेगी। उदारीकरण के दौर सहकारिताओं को टिकाऊ बनाना है तो उन्हें वित्तीय आत्मनिर्भरता के साथ उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाना होगा। चौथा, सहकारिता को नियमन में एकरूपता लानी होगी। इससे सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी कम होगा। राज्य का विषय होने की वजह से विभिन्न दलों के अपने हित और लोग सहकारिताओं पर थोप दिए जाते हैं।

ऐसे में सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए बनाई गई आदर्श उपविधियां (माडल बाइलाज) सराहनीय पहल है। इन उपविधियों का यदि सही तरीके से पालन सुनिश्चित कर लिया जाता है तो भारतीय सहकारिताओं की पेशेवर दक्षता बढ़ेगी। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से मिले तथ्य सहकारिता नीति के साथ इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी नियमन के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। राष्ट्रीय सहकारिता नीति में सहकारिताओं की श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को अपनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में सहकारिताओं को टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें निवेश अनुकूल तथा नवाचार और नियमन के मोर्चे पर भी मजबूती देनी होगी।

****

सट्टा व्यापार पर अंकुश लगाए सरकार : नीलेश शाह

कोलकाता: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने कहा कि सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने और लंबी अवधि के लिए निवेश की संस्कृति विकसित करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। कलकत्ता चैंबर आफ कामर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शाह ने बताया कि कैसे लंबी अवधि का पूंजी निवेश खुदरा निवेशकों और भारतीय कंपनियों के लिए संपत्ति निर्माण का काम कर सकता है। (प्रेट्र)

पीएलआइ योजना का उद्देश्य उद्योग को गति देना है। यह कोई स्थायी सब्सिडी नहीं है। हमारा लक्ष्य इंडस्ट्री को सरकारी मदद पर निर्भर बनाना नहीं है।
–पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

सेंसेक्स	79,996.60	▼ 53.07
निफ्टी	24,323.85	▲ 21.70
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 73,310	▲ ₹200
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 93,400	▲ ₹350
डालर	₹83.49	▼ ₹0.01
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 87.26	

एक नजर में

सेबी ने रेटिंग एजेंसियों से जुड़े नए निर्देश जारी किए

नई दिल्ली: सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये संशोधन एक अगस्त से लागू होंगे। अब एजेंसियों को रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर कंपनियों को रेटिंग भेजनी होगी। कंपनियों के पास रेटिंग निर्णय की समीक्षा का अनुरोध करने के लिए तीन कार्य दिवस होंगे। (प्रेट्र)

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.713 अरब डालर घटा

मुंबई: 28 जून को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.713 अरब डालर घटकर 651.997 अरब डालर रह गया। इस दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.252 अरब डालर घटकर 572.881 अरब डालर रह गईं। इसके पिछले सप्ताह में कुल भंडार 2.922 अरब डालर घटकर 652.895 अरब डालर के स्तर पर आ गया था। सात जून को विदेशी मुद्रा भंडार 655.817 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर था। (प्रेट्र)

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए मानक हुए अनिवार्य

नई दिल्ली: सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम से बने रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने कहा कि ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर बीआइएस मानक चिह्न न हो। (प्रेट्र)

एयरटेल का ग्राहकों से जुड़ी जानकारी में सेंध से इन्कार

नई दिल्ली: भारती एयरटेल ने अपने ग्राहकों से जुड़ी जानकारी में सेंध की खबर को शुक्रवार को खारिज कर दिया। उसने कहा कि इस तरह का दावा ब्रांड की छवि को खराब करने का एक हताश प्रयास है। कंपनी का यह बयान ऐसे समय आया है जब डार्क वेब पर 'एक्सईएनजेर्डईएन' नाम के एक अकाउंट से दावा किया गया था कि उसके पास एयरटेल के 37.5 करोड़ से अधिक ग्राहकों के आंकड़ों तक पहुंच है। (प्रेट्र)

अब आलू, प्याज और टमाटर ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी

तीनों सब्जियों की बढ़ती कीमतों से खुदरा महंगाई दर पर बढ़ा दबाव, काम नहीं आई सरकार की आपरेशन ग्रीन स्कीम

राजीव कुमार ● जागरण

- अगस्त में होने वाली है मौद्रिक नीति समिति की बैठक, ब्याज दरों में कटौती करना नहीं होगा आसान
- सरकार का दावा, प्याज और आलू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, कर्नाटक से टमाटर आने पर दाम होंगे कम

एक महीने के अंदर कीमतों में आया तेज उछाल (प्रतिशत में)

आलू	25
प्याज	35
टमाटर	70

नई दिल्ली : खुदरा महंगाई सरकार के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। दाल के बाद अब आलू, प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों से खुदरा महंगाई दर पर दबाव बढ़ने लगा है। इसका नतीजा यह होगा कि अगले महीने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआइ के लिए ब्याज दरों में कटौती करना आसान नहीं होगा। क्योंकि पिछले एक महीने में आलू, प्याज व टमाटर की खुदरा कीमतों में क्रमशः 25 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए प्याज और आलू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कुछ दिनों में कर्नाटक के टमाटर की सप्लाई बाजार में होने लगेगी जिससे टमाटर की कीमतों में नरमी आएगी।

मंत्रालय के कीमत नियंत्रण डिविजन केमुताबिक इस माह चार तारीख को दिल्ली में आलू की खुदरा कीमत 37 रुपये, प्याज 50 रुपये तो टमाटर की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम रही जबकि इस साल चार जून को आलू 28 रुपये, प्याज 32 रुपये और टमाटर 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहे थे। हालांकि कई खुदरा बाजार में आलू के भाव 50 रुपये तो टमाटर के 60 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच चुके हैं।

2019 में आई थी आपरेशन ग्रीन स्कीम : आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों को हमेशा एक समान स्तर पर रखने के लिए सरकार की तरफ से वर्ष 2019 में आपरेशन ग्रीन स्कीम लांच की गई थी। स्कीम का उद्देश्य 22,000 हाटों को वैल्यू चेन में लाना था ताकि आलू, टमाटर व प्याज जैसे जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादों की सप्लाई बनी रहे। इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

इस साल रबी सीजन में 191 लाख टन प्याज उत्पादन का अनुमान

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इस साल खरीफ सीजन में आलू, प्याज और टमाटर तीनों की खेती पिछले साल की तुलना में अधिक क्षेत्रफल में की जा रही है। हालांकि 70 प्रतिशत प्याज का उत्पादन रबी सीजन में होता है, लेकिन खरीफ के उत्पादन से सप्लाई का संतुलन बना रहता है। मंत्रालय के मुताबिक अभी रबी सीजन का प्याज बाजार में उपलब्ध है और इस साल रबी सीजन में 191 लाख टन प्याज के उत्पादन का अनुमान है। घरेलू खपत प्रतिमाह 17 लाख टन की है। किसान अब बारिश में खराब होने के डर से रबी सीजन के प्याज की सप्लाई तेज कर रहे हैं जिससे प्याज की कीमत में नरमी आएगी। मंत्रालय के मुताबिक इस साल खरीफ सीजन में 12 प्रतिशत अधिक एरिया में आलू की खेती हो रही है तो टमाटर की खेती के एरिया में भी इजाफा हुआ है।

आपरेशन ग्रीन स्कीम आलू, प्याज और टमाटर के किसानों को अच्छी कीमत दिलवाने के साथ इन वस्तुओं की पूरी एक वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। हाट को जोड़ने का काम भी पूरा नहीं हो सका। हर साल जून से अगस्त के दौरान इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। पिछले साल जुलाई में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई थी।
–उदय देवलंकर, कृषि विशेषज्ञ एवं महाराष्ट्र सरकार के सलाहकार

जून में महंगी हुई शाकाहारी थाली

मुंबई, प्रेट्र : शाकाहारी थाली की कीमत जून में औसतन 10 प्रतिशत बढ़कर 29.4 रुपये प्रति थाली हो गई, जो जून 2023 में 26.7 रुपये थी। मई 2024 में यह 27.8 रुपये थी। शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जियां (प्याज, टमाटर तथा आलू), चावल, दाल, दही और सलाद शामिल है। वहीं ब्रायलर मुर्गे की कीमत में गिरावट से मांसाहारी थाली की कीमत जून में घटकर 58 रुपये रह गई। मई में इसकी कीमत 55.9 रुपये प्रति थाली थी। इसमें सामग्री शाकाहारी थाली के समान होती हैं, लेकिन दाल की जगह चिकन होता है।

वर्ष 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2047 तक भारत को उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। हालांकि तब तक देश उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स के टिप्पणीकार और अर्थशास्त्री मार्टिन वुल्फ ने भारत के 2047 तक एक महाशक्ति बन जाने पर भी विश्वास जताया।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वुल्फ ने कहा कि भविष्य में आने वाले व्यवधान भारत के उत्थान को मुश्किल बना देंगे। ऐसे में उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने पास मौजूद अवसरों का फायदा उठाने के लिए खुद को भी आकार देना होगा। भारत वर्तमान में एक विकासशील राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है। एक विकसित देश की पहचान आमतौर पर अपेक्षाकृत उच्च स्तर की आर्थिक वृद्धि, सामान्य जीवन स्तर, उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ मानव विकास सूचकांक (एचडीआइ) पर अच्छे प्रदर्शन से होती है। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के समय भारत को 'तीसरी दुनिया' के देश के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

शीर्ष 30 मझोले शहरों में घरों की बिक्री 11% बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: आवासीय मांग में वृद्धि केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गत वित्त वर्ष 2023-24 में 30 मझोले शहरों में भी आवासीय संपत्तियों की बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर करीब 2.08 लाख इकाई हो गई। रियल एस्टेट डेटा विश्लेषक कंपनी प्रापइक्विटी ने मझोले शहरों के आवासीय बाजार पर शुक्रवार को एक रिपोर्ट जारी की।

2023-24 में आवासीय बिक्री 11 प्रतिशत बढ़कर 2,07,896 इकाई हो गई, जबकि 2022-23 में यह 1,86,951 इकाई थी। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, नासिक, गांधीनगर, जयपुर, नागपुर, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और मोहाली का कुल बिक्री में 80 प्रतिशत का योगदान रहता है। इन 10 शहरों में 2023-24 में कुल 1,68,998 इकाइयों की बिक्री हुई, जो 2022-23 में 1,51,706 की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। अन्य मझोले शहर भोपाल, लखनऊ, गोवा, कोयंबटूर, रायपुर, विजयवाड़ा, इंदौर, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर, गुंटूर, भिवाड़ी, देहरादून, लुधियाना, चंडीगढ़, आगरा, मैसूर, सोनीपत, पानीपत और अमृतसर हैं।

संपत्ति की कम कीमतों और वृद्धि की संभावनाओं के दम पर मझोले शहरों ने बड़े शहरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।
–समीर जसूजा, एमडी, प्रापइक्विटी

स्टार्टअप से एंजल कर हटाने की सिफारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र: उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बजट आने से पहले स्टार्टअप कंपनियों से एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की है।

आयकर विभाग ने पिछले साल सितंबर में नए एंजल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया था जिसमें निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप की तरफ से जारी शेयरों का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्था भी शामिल है। उचित बाजार मूल्य से ऊपर किसी स्टार्टअप के शेयरों की बिक्री से हासिल पूंजी पर लगने वाले कर को एंजल टैक्स कहा जाता है। पहले एंजल कर केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन अब विदेशी निवेशक भी इसके दायरे में आते हैं। टेस्ला के सवाल पर कहा, 'भारी उद्योग मंत्रालय ईवी के लिए जारी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।'

यात्री वाहनों की बिक्री जून में सात प्रतिशत घटी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में जून में सालाना आधार पर सात प्रतिशत की गिरावट आई। भीषण गर्मी के कारण शोरूम में आने वाले लोगों की संख्या में 15 प्रतिशत गिरावट इसकी बड़ी वजह रही। उद्योग संगठन फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार, कुल यात्री वाहन पंजीकरण पिछले महीने 2,81,566 इकाई रहा, जबकि जून 2023 में यह 3,02,000 इकाई था।

जून में दोपहिया वाहनों का पंजीकरण सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर 13,75,889 इकाई हो गया। मानसून में देरी और चुनाव से संबंधित बाजार मंदी ने विशेष रूप से ग्रामीण बिक्री को प्रभावित किया, जो मई में 59.8 प्रतिशत से गिरकर जून में 58.6 प्रतिशत पर आ गई। कुल खुदरा बिक्री जून में सालाना आधार पर मामूली बढ़कर 18,95,552 इकाई हो गई।

- भीषण गर्मी से शोरूम में आने वाले लोगों की संख्या में 15 प्रतिशत की गिरावट
- कुल खुदरा बिक्री जून में सालाना आधार पर मामूली बढ़कर 18,95,552 यूनिट रही

इस दौरान डीलरों ने ग्राहकों के वाहनों के बारे में कम जानकारी लेने और खरीद निर्णय में देरी जैसी चुनौतियों का सामना किया। त्योहारी सीजन में अभी कुछ समय बाकी है, इसलिए यात्री वाहन मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के लिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है।
–मनीष राज सिंघानिया, प्रेसिडेंट, फाडा

बजाज आटो ने लांच की दुनिया की पहली सीएनजी बाइक

नई दिल्ली, आइएएनएस : बजाज आटो ने शुक्रवार को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक 'बजाज फ्रीडम' लांच की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। उन्होंने इसे गेमचेंजर बताया। इसकी शुरुआती कीमत 95,000 रुपये तय की गई है। सीएनजी टैंक को सीट के नीचे जगह दी गई है। कंपनी ने दो लीटर का फ्यूल टैंक और दो किलो की क्षमता का सीएनजी टैंक दिया है। कंपनी का दावा है कि, ये बाइक फुल टैंक (पेट्रोल+सीएनजी) में 330 किमी तक की चल सकती है। ये बाइक पेट्रोल और सीएनजी दोनों मोड में ड्राइव की जा सकती है। इसके लिए कंपनी ने हैंडलबार पर एक स्विच दिया है, जिसमें मोड बदलने का बटन मिलता है।

एमएसएमई में काम करने वालों की संख्या 20.2 करोड़ से ज्यादा

नई दिल्ली, आइएएनएस: देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) में काम करने वालों की संख्या 20.2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, पिछले साल इसी समयावधि में इस तरह के उद्योगों में काम करने वालों की संख्या 12.1 करोड़ थी। इन उद्यमों में कार्यरत कुल श्रमिकों में 4.54 करोड़ महिला कर्मचारी हैं।

वर्तमान में 4.68 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें से 4.6 करोड़ सूक्ष्म उद्यम हैं। वित्त मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में एक मासिक आर्थिक रिपोर्ट में यह बताया था कि जुलाई, 2020 में सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्यम पोर्टल के बाद से एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में 5.3 गुना की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय फलक

चीन से ताल्लुक रखने वाले एक अमेरिकी व्यवसायी ने बनवाई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ: वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया है कि चीन से ताल्लुक रखने वाले एक अमेरिकी व्यवसायी ने हिंडनबर्ग रिसर्च से एक रिपोर्ट बनवाई थी, जिसके चलते पिछले साल अदाणी समूह की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई। उन्होंने दावा किया कि किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी के पीछे अमेरिकी व्यवसायी मार्क किंगडन हैं और इन्होंने ही हिंडनबर्ग रिसर्च से रिपोर्ट बनवाई थी।

जेठमलानी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट में आरोप लगाया, 'जासूस' अनला चेंग और उनके पति मार्क किंगडन ने अदाणी समूह की कंपनियों पर एक रिपोर्ट को हिंडनबर्ग रिसर्च से तैयार कराया और बाद में अदाणी के शेयरों को शार्ट सेल करने और भारतीय खुदरा निवेशकों की कीमत पर लाखों का मुनाफा कमाने के लिए कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (केएमआइएल) का इस्तेमाल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए किया।' महेश जेठमलानी ने अपने पोस्ट में अनला चेंग को 'स्मोकिंग गन' कहा है। चेंग एक चीनी-अमेरिकी हैं। उनकी किंगडन मास्टर फंड में बड़ी हिस्सेदारी है और अमेरिका में चीनी हितों के लिए लांबिंग करती हैं।

मारीशस मार्ग से अदाणी शेयरों में बड़ी शार्ट पोजिशन ली: जेठमलानी ने कहा है कि किंगडन ने कोटक की अंतरराष्ट्रीय निवेश शाखा कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (केएमआइएल) से संपर्क किया। इसके बाद एक आफशोर फंड के साथ-साथ अदाणी शेयरों में व्यापार के लिए आफशोर अकाउंट भी खोले। इसके चलते कोटक इंडिया आपर्च्युनिटी फंड (केआइओएफ) बनाया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट तैयार होने से पहले केआइओएफ ने मारीशस मार्ग से अदाणी शेयरों में बड़ी शार्ट-पोजिशन ली। व्यापार के लिए चार करोड़ डालर की राशि किंगडन के मास्टर फंड द्वारा प्रदान की गई, जिसका स्वामित्व अनला चेंग सहित किंगडन परिवार के पास है। शार्ट-सेलिंग के माध्यम से किंगडन ने अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों के बाजार पूंजीकरण को कम करने और भारतीय खुदरा निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान की कीमत पर लाखों डालर कमाए गए।

- वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बोले, अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट से लाखों डालर कमाए
- अमेरिकी व्यवसायी की पत्नी चीनी नागरिक, अमेरिका में चीनी हितों के लिए करती हैं लांबिंग

महेश जेठमलानी। फाइल

जेठमलानी ने सेबी को टैग करते हुए तीन प्रमुख सवाल भी उठाए

- उन्होंने पूछा कि किंगडन को केएमआइएल से किसने मिलवाया। किंगडन के संबंध में केएमआइएल ने क्या जांच-पड़ताल की और क्या उसने शार्ट सेल में भाग लिया था।
- क्या हिंडनबर्ग की मदद करने वाले सभी भारतीय लोगों, संगठनों और संस्थाओं को शार्ट-सेलिंग के बारे में पता था और क्या उन्हें इससे कोई फायदा हुआ।
- जेठमलानी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए विशेष रूप से राजनेताओं का उल्लेख किया, जिन्होंने कई मौकों पर अदाणी-हिंडनबर्ग मुद्दे का इस्तेमाल समूह और सरकार को निशाना बनाने के लिए किया है। जेठमलानी ने यह भी पूछा कि क्या इन लोगों और संस्थाओं को चीनी लिंक के बारे में पता था।

बिना नियमन मोबाइल कंपनियों को शुल्क बढ़ाने की अनुमति कैसे मिली : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : तीन निजी कंपनियों द्वारा मोबाइल सेवा शुल्क बढ़ाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को उस पर 109 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को लूटने का आरोप लगाया। पार्टी ने सवाल किया कि कंपनियों को बिना किसी निगरानी और नियमन के एकतरफा तरीके से दरें बढ़ाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह भले ही मोदी 3.0 है, लेकिन मित्र पूंजीपतियों को बढ़ावा देना जारी है। निजी कंपनियों को लाभ कमाने की मंजूरी देकर मोदी सरकार 109 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को लूट रही है। उन्होंने कहा कि तीन निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने तीन जुलाई से शुल्क में औसतन 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इन तीनों कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 91.6 प्रतिशत या 31 दिसंबर, 2023 तक कुल 119 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं में से इनके 109 करोड़ उपयोगकर्ता थे।

- पार्टी का आरोप, 109 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं से की जा रही लूट
- कहा, सरकार एकतरफा तरीके से दरें बढ़ाने की अनुमति कैसे दे सकती है

नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। प्रेट्र

सुरजेवाला ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) का हवाला देते हुए कहा कि कनेक्टिविटी चाहने वाले आम लोगों की जेब से कुल अतिरिक्त वार्षिक भुगतान 34,824 करोड़ रुपये होगा। भारत में मोबाइल बाजार पर रिलायंस जियो (48 करोड़ उपयोगकर्ता), एयरटेल (39 करोड़ उपयोगकर्ता), वोडाफोन आइडिया (22.37 करोड़ उपयोगकर्ता) का एकाधिकार है। सुरजेवाला ने कहा, "दो बातें स्पष्ट हैं? पहली बात शुल्क में वृद्धि की घोषणा की तिथि स्पष्ट रूप से तीनों निजी मोबाइल फोन कंपनियों द्वारा परामर्श कर तय की गई है। दूसरी बात बढ़े हुए शुल्क के क्रियान्वयन की तिथि एक ही है।" उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार व ट्राई ने 109 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ लिया। क्या चुनाव संपन्न होने तक मोबाइल फोन की शुल्क में वृद्धि रोककर नहीं रखी गई? साथ ही सवाल किया कि क्या मोदी सरकार या ट्राई ने दूरसंचार नीति, 1999 के तहत देय समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर रियायतों के पिछले सेट या 20 नवंबर, 2019 को मोदी 2.0 द्वारा "स्पेक्ट्रम नीलामी किस्तों" को स्थगित करने या अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए नीलामी से स्पेक्ट्रम की खरीद से लाभप्रदता पर प्रभाव या पूंजीगत व्यय की आवश्यकता पर कोई अध्ययन किया है।

सरकार ने कहा, बाजार तय करता है सेवाओं की दरें

नई दिल्ली, प्रेट्र : मोबाइल सेवाओं की दरों में हालिया वृद्धि पर कांग्रेस के दावों को सरकार ने भ्रामक बताकर खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि भारत का मोबाइल सेवा बाजार मांग और आपूर्ति की ताकतों से संचालित होता है, जिसमें तीन निजी दूरसंचार कंपनियां और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी शामिल हैं। साथ ही कहा कि देश के ग्राहकों को दुनियाभर में सबसे कम दरों पर मोबाइल सेवाएं प्राप्त होती हैं।

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले दो दशकों में मोबाइल सेवाओं की दरों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने संयमित रखा था और सरकार की नीतियों व नियामक की ओर से अधिसूचित नियामक ढांचे के परिणामस्वरूप भारत मोबाइल सेवा ग्राहकों के लिए सबसे कम दरों वाले देशों में से एक है। मंत्रालय ने इस संदर्भ में अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस और अन्य देशों में प्रचलित दरों का तुलनात्मक चार्ट उपलब्ध कराया। भारत के मामले में 1.89 अमेरिकी डालर प्रतिमाह की औसत कीमत पर व्यावहारिक रूप से असीमित वायस काल और 18 जीबी डाटा मोबाइल ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

मंत्रालय ने कहा, "दूरसंचार सेवाओं की दरें बाजार की ताकतों द्वारा तय की जाती हैं, जो स्वतंत्र नियामक यानी ट्राई द्वारा अधिसूचित नियामक ढांचे के भीतर होती हैं। सरकार मुक्त बाजार के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करती।"

'प्रमाण के बिना वाट्सएप वार्तालाप को साक्ष्य नहीं माना जा सकता'

विनीत त्रिपाठी ● जागरण

- डेल इंटरनेशनल की याचिका पर हाई कोर्ट का राहत देने से इन्कार
- राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग के आदेश को डेल ने दी थी चुनौती

नई दिल्ली : वाट्सएप पर हुए वार्तालाप को साक्ष्य के रूप में पेश करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत अनिवार्य उचित प्रमाणपत्र के बिना वाट्सएप वार्तालाप को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि एक रिट याचिका पर विचार करते समय वाट्सएप वार्तालाप के स्क्रीनशाट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जबकि यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि बातचीत राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। पीठ ने इस टिप्पणी के साथ डेल इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया।

डेल ने याचिका में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में राज्य आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के उस निर्णय को बरकरार रखा था, जिसमें कंपनी के लिखित बयान को तय समय-सीमा में दायर नहीं करने पर रिकार्ड पर लेने से इन्कार कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि डेल ने 31 जनवरी, 2023 को ही लिखित बयान दाखिल कर तर्क दिया था कि उसे समन के साथ दस्तावेज का पूरा सेट नहीं मिला था, जबकि वास्तव में उसे पूरा सेट दिया गया था। 2022 में आदिल फिरोज ने जिला उपभोक्ता फोरम में डेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डेल ने फिरोज व कंपनी के बीच हुए संवाद के लिए एक वाट्सएप स्क्रीनशाट पेश किया।

पाक्सो केस में मेडिकल जांच से तय हो पीड़िता की आयु : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाक्सो केस में ट्रायल कोर्ट की ओर से आयु निर्धारण संबंधी मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किए बिना जमानत अर्जियों को एकतरफा खारिज करने पर गंभीर टिप्पणी की है। निर्देश दिया है कि पाक्सो केस में पीड़िता की आयु मेडिकल जांच से तय की जाए। कहा है कि ट्रायल कोर्ट पीड़िता की आयु पर विचार किए बिना जमानत अर्जियों को तय कर रही हैं, यह न्यायिक प्रणाली के लिए गर्भपात जैसा है। यह रवैया उनके पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करता है।

कोर्ट ने इसमें सुधार के लिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ, जिला जजों, पुलिस महानिदेशकों और अभियोजन कार्यालय को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। डीजीपी को सर्कुलर जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जालौन के अनिरुद्ध की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि सतत लर्निंग प्रोग्राम के तहत संबंधितों को प्रशिक्षित कर उनको कार्य संस्कृति या मानसिक रूप से योग्य बनाया जाए ताकि न्यायिक व्यवस्था में बदलाव आ सके और निर्दोष अनावश्यक रूप से जेल में न बंद रहे। जमानत का संबंध अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मूल अधिकार से है। यह न केवल विधिक अपितु संवैधानिक अधिकार है। ट्रायल कोर्ट को पाक्सो के तहत जमानत अर्जियों को निस्तारित करते समय पीड़िता की आयु को महत्व देना चाहिए। उससे जुड़े सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करना चाहिए। तथ्यों के अनुसार जालौन निवासी याची के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। पीड़िता ने बयान दिया कि दोनों सहमति से संबंधों में रह रहे हैं। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता की उम्र को लेकर विरोधाभास है। स्कूल रिकार्ड में उम्र 13 साल दो माह दर्ज है जबकि बयान में उसने उम्र 15 साल बताई और चिकित्सकीय रिपोर्ट में यह 18 साल मिली। कोर्ट ने कहा, अक्सर लोग स्कूल में वास्तविकता से विपरीत कम आयु लिखाते हैं। इस विरोधाभास पर मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए।

****

39 हजार से ज्यादा लोग फलस्तीन और इजरायल में मारे गए है। दोनों देश करीब 29 महीने से युद्धरत है। दोनों तरफ की भीषण नागरिक और सैन्य तबाही हुई है।

पूर्ण बहुमत वाली लेबर पार्टी की सरकार भारत–ब्रिटेन रिश्तों के लिए शुभ

पीएम मोदी ने लेबर पार्टी के नेता स्टार्मर को दी बधाई, साथ काम करने का संदेश दिया

भारत–ब्रिटेन के बीच एफटीए वार्ता अंतिम चरण में, लेबर पार्टी की सरकार देगी समर्थन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ब्रिटेन में सत्ता बदलने के बावजूद भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की तैयारियों पर कोई बड़ा झटका लगने की संभावना नहीं है। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव विजयी लेबर पार्टी के विचार एफटीए के जरिये भारतीय प्रोफेशनलों को ज्यादा तरजीह देने को लेकर कुछ सख्त है। इसके बावजूद जानकार बता रहे हैं कि एफटीए को अंतिम सहमति बनाने में दिक्कत नहीं होगी। लेबर पार्टी के नेता किएर स्टार्मर को जीत की बधाई दे कर पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी यह संदेश दे दिया है कि भारत भी ब्रिटेन की नई सरकार के साथ काम करने को पूरी तरह से तैयार है। किएर स्टार्मर ही ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। एफटीए को लेकर वार्ता दोनों देशों के आम चुनाव की वजह से प्रभावित हुई हैं लेकिन अब जबकि दोनों तरफ मजबूत सरकार सत्ता में आ गई हैं तो इस पर जल्द सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है।

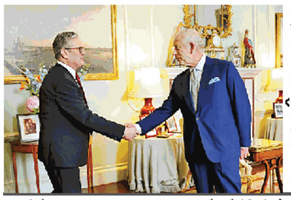

भारतीय प्रोफेशनलों को ब्रिटेन में ज्यादा अवसर देने संबंधी प्रस्ताव पर कुछ आपत्ति संभव

चुनाव में जीत के बाद ब्रिटेन के राजा से मुलाकात करते किएर स्टार्मर। किएर की लेबर पार्टी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है।

कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि लेबर पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई है। यह भारत के साथ रिश्तों के लिए शुभ है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन की राजनीतिक अस्थिरता का असर भी द्विपक्षीय रिश्तों पर पड़ा है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर बातचीत बहुत जल्द (अगले कुछ हफ्तों में) शुरू हो सकती है। लेबर पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारत के साथ एफटीए करने को लेकर अपना समर्थन देने की बात कही है। भारत और ब्रिटेन के बीच वर्ष 2021 में वर्ष 2030 तक के द्विपक्षीय रिश्तों का एजेंडा तय किया गया है। इसमें कारोबार, निवेश और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संबंधों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए हैं। एफटीए करने की सहमति इसी रोडमैप का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर शोध रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी जीटीआरआइ ने शुक्रवार (05 जुलाई) को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि ब्रिटेन की नई लेबर पार्टी की सरकार को प्रस्तावित एफटीए में भारतीय प्रोफेशनलों को ज्यादा सहूलियत देने संबंधी बातों के अलावा अन्य किसी बात पर दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यह ब्रिटेन की कंपनियों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश करने का रास्ता खोलेगा। वैसे भी स्टार्मर ने पूर्व में कई बार भारतीय पीएम मोदी के साथ काम करने की इच्छा जताई है। रिपोर्ट में भारत को सलाह दी गई है कि नई ब्रिटिश सरकार के साथ एफटीए को लेकर होने वाली आगामी वार्ताओं में अपने हितों से जुड़े मुद्दों पर डट कर खड़ा रहना चाहिए। यह समझौता ऐसा होना चाहिए कि दोनो देशों को फायदा हो।

एफटीए पर तेजी से बातचीत आगे बढ़ने के साथ ही ब्रिटेन की नई सरकार से भारत को यह भी उम्मीद रहेगी कि वह खालिस्तान समर्थक संगठनों पर लगाम लगाने में ज्यादा तेजी दिखाए। हाल के वर्षों में देखा गया है कि कई बार खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के सामने हिंसक प्रदर्शन किए हैं जिसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ा है। खालिस्तान समर्थकों के संगठनों की गतिविधियो की वजह से अभी भारत का रिश्ता कनाडा के साथ काफी खराब हो चुका है जबकि अमेरिका के साथ रिश्तों में भी असहजता आई है। लेबर पार्टी ने भारत के साथ नए रणनीतिक संबंध बनाने की बात कही है जिसे भारत के लिहाज से काफी सकारात्मक माना जा रहा है। हाल के वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने प्रौद्योगिकी और फिनटेक क्षेत्र में ब्रिटेन ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया है। नई सरकार इसे और धार दे सकती है।

जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं कामगार के बेटे किएर

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

ब्रिटेन के आम चुनाव में ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी की करारी हार हुई है। इस चुनाव में किएर स्टार्मर के नेतृत्व ने लेबर पार्टी ने प्रचंड जनादेश हासिल किया है। पेशे से वकील कीएर स्टार्मर ब्रिटेन में मौजूदा सबसे बड़े विपक्षी दल लेबर के अध्यक्ष हैं। लेबर पार्टी के अनुसार, वह जरूरतमंदों को न्याय दिलाते रहे हैं। पूर्वी इंग्लैंड के सरी में आक्सटेड नामक एक छोटे से शहर में पले-बढ़े स्टार्मर के पिता एक कारखाने में कामगार थे और उनकी मां एक नर्स थीं। उनकी मां ने जीवन भर एक दुर्लभ बीमारी से संघर्ष किया।

वेश्यालय के ऊपर रहते थे स्टार्मर: स्टार्मर का जीवन चुनौतियों से भरपूर रहा। उन्होंने स्थानीय ग्रामर स्कूल में दाखिला लिया। जब वह 18 वर्ष के थे तो उन्हें लीड्स यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने का मौका मिला। 'कीर स्टार्मरः द बायोग्राफी' में दावा किया गया है कि किएर स्टार्मर स्नातक होने के बाद एक वेश्यालय के ऊपर बने एक गोलाकार बिस्तर पर रहते थे। इस इमारत में स्टार्मर और उनके मित्र बीती सदी के नौवें दशक में रहते थे।

बतौर बैरिस्टर शुरू की पेशेवर जिंदगी : किएर को फुटबाल और संगीत का शौक है। कीएर ने 1987 में वकील के रूप में योग्यता प्राप्त की और बैरिस्टर के रूप में पेशेवर करियर शुरू किया। उन्होंने

- 18 वर्ष के थे तो लीड्स यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने का मौका मिला
- संगीत और फुटबाल के शौकीन हैं कीएर स्टार्मर

काफी समय गरीब लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह देने में बिताया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर काम किया। उसके बाद किएर स्टार्मर पांच साल तक उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड के कानूनी सलाहकार रहे। इसी दौरान कीएर की मुलाकात विक्टोरिया से हुई। कीएर और विक्टोरिया का विवाह 2007 में हुआ। उनके दो बच्चे हैं। विक्टोरिया अब ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए काम करती हैं।

2008 में किएर लोक अभियोजन निदेशक बन गए। उन्होंने यौन और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए बेहतर सहायता के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव किया और खर्चों के दुरुपयोग के लिए सांसदों पर मुकदमा चलाया। कीएर को 2014 में नाइटहुड की उपाधि मिली।

पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद मिली बुरी हार

अप्रैल 2020 में किएर स्टार्मर को लेबर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि, स्टार्मर के अध्यक्ष बनने के ठीक बाद पार्टी को 85 वर्षों में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने तुरंत पार्टी को फिर से विजयी बनाने को मिशन घोषित कर दिया। अब 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। लेबर पार्टी ने कहा कि वह एक ऐसे ब्रिटेन का निर्माण करेगी जो आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं रह रहा है। एक ऐसा ब्रिटेन जहां अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, कड़ी मेहनत को बढ़ावा देती है। स्टार्मर लेबर पार्टी को ब्रिटिश राजनीति के केंद्र में वापस लाने और मतदाताओं में व्यापक अपील लाने के उनके प्रयास सफल रहे। अब 61 वर्षीय स्टार्मर ब्रिटेन के शीर्ष पद पर आसीन होंगे।

किएर स्टार्मर पहली बार 2015 में 52 साल की उम्र में संसद के लिए चुने गए। वर्तमान में वह साउथ सेंट्रल लंदन के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होलबोर्न और सेंट पैनक्रास के सांसद हैं। वह 2015 से 2016 तक ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट में आव्रजन मंत्री थे।

भारत को असहज करने वाली रही हैं लेबर पार्टी की नीतियां

ब्रिटेन के आम चुनाव में बड़ी जीत के साथ लेबर पार्टी सरकार बनाने जा रही है। समय के साथ लेबर पार्टी ने भारत को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव किया है। लेकिन यह तथ्य है कि बीते वर्षों में पार्टी की नीतियां भारत को असहज करने वाली रही हैं। खास कर कश्मीर के मसले पर। आइये जानते हैं उस घटनाक्रम के बारे में जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने ब्रिटेन को तीसरे दर्जे की ताकत बताया था।

कूटनीतिक आपदा साबित हुई क्वीन एलिजाबेथ की यात्रा

वर्ष था 1997। भारत अपनी आजादी की 50 वीं वर्षगांठ मना रहा था। ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी की सरकार थी। ब्रिटेन और भारत ने इस समारोह के लिए ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की यात्रा की योजना बनाई। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ की भारत यात्रा एक कूटनीतिक आपदा साबित हुई।

कश्मीर पर मध्यस्थता के प्रस्ताव से भड़का भारत

अक्टूबर में क्वीन एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान में रुके। राजकीय भोज में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को पाकिस्तान पर अपने मतभेदों को सुलझाने की जरूरत है। उनके साथ ब्रिटेन के विदेश मंत्री राबिन कुक भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ निजी बातचीत में कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर दी। इससे माहौल ज्यादा ही खराब हो गया। भारत में उनके इस प्रस्ताव की भर्त्सना की गई और प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने ब्रिटेन को तीसरे दर्जे की ताकत बताया। कश्मीर पर बयानबाजी से भारत भड़क गया था और क्वीन एलिजाबेथ की भारत यात्रा एक औपचारिक यात्रा बन कर रह गई। जाहिर है कि भारत की तरफ से किसी तरह की गर्मजोशी नहीं दिखाई गई।

2019 में लेबर पार्टी का भारत विरोधी प्रस्ताव

जेरेमी कार्बिन की अगुवाई में लेबर पार्टी ने 2019 में एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का समर्थन किया गया और संयुक्त राष्ट्र की देख रेख में जनमत सर्वेक्षण की मांग की गई। यह प्रस्ताव कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आया था। इसके अलावा लेबर पार्टी में कुछ लोगों की राय खालिस्तान के पक्ष में रही है। यह एक और मुद्दा है जिसकी वजह से भारत और लेबर पार्टी के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं।

क्यों हारे सुनक

- नेशनल हेल्थ सर्विस का ढांचा चरमरा गया था।
- ब्रिटेन की खराब अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था।
- लोग महंगाई और बढ़ती कीमतों से परेशान थे।
- अवैध प्रवासियों पर अंकुश नहीं लगा सकी सरकार

कैसे होंगे भारत- ब्रिटेन के रिश्ते

- लेबर पार्टी ने माना है, अतीत में कश्मीर के मुद्दे पर गलतियां हुई हैं
- कीएर का भारत संग नई रणनीतिक साझेदारी का वादा
- भारतीय प्रवासियों के साथ रिश्ते सुधारने की पहल कर चुकी लेबर पार्टी
- प्रवासी नीतियों और व्यापार समझौते को लेकर स्टार्मर की नीतियां हैं चुनौती
- भारत अपने वर्कर्स के लिए कर रहा है अस्थाई वीजा की मांग

इजरायल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में की सैन्य कार्रवाई, सात फलस्तीनी मारे गए

यरुशलम, एपी : वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सैन्य अभियान के दौरान शुक्रवार को सात लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत यह हमला किया था। इसमें हवाई हमला भी शामिल था। इजरायली सैनिकों ने एक इमारत को घेर लिया, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। सैनिकों ने अंदर मौजूद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। हवाई हमले में क्षेत्र में कई सशस्त्र आतंकवादी मारे गए। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमले में सात लोग मारे गए हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि वे गोलीबारी में मरे या हवाई हमले में। इजरायली निगरानी समूह की ओर से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 5,300 नए घर बनाने की योजना की घोषणा के बाद जेनिन में यह कार्रवाई हुई है। इस बीच, हमास ने अपने सहयोगी हिजबुल्ला को जानकारी दी है कि वह गाजा पट्टी में युद्धविराम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है।

भारतीय विमान हाईजैक करने वाले आतंकी की पाक में मौत

जागरण संवाददाता, अमृतसर

आतंकी जरनैल सिंह भिंडरांवाला की गिरफ्तारी के विरोध में 29 सितंबर, 1981 को दिल्ली से एयर इंडिया के विमान को हाइजैक कर लाहौर ले जाने वाले आतंकी गजिंदर सिंह की गत तीन जुलाई को पाकिस्तान में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसकी पुष्टि करते हुए दल खालसा के प्रवक्ता कंवरपाल सिंह बिट्टू ने बताया कि दल खालसा इंटरनेशनल के संरक्षक गजिंदर का चार जुलाई को पाकिस्तान में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। शव को मुखाग्नि उसकी बेटी बिक्रमजीत कौर ने दी।

बता दें कि भिंडरांवाला के भतीजे स्वर्ण सिंह पर लाला जगत नारायण की हत्या के आरोप थे। पुलिस का मानना था कि यह साजिश भिंडरांवाला ने ही रची थी। 20 सितंबर, 1981 को भिंडरांवाला को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में गजिंदर ने एक हफ्ते बाद ही 29 सितंबर को दिल्ली से श्रीनगर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 423 को हाईजैक कर लिया था। वह फ्लाइट को दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर ले गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विमान हाईजैक के मामले में वह 14 साल पाकिस्तान की जेल में रहा। उसके जेल से रिहा होने के बाद भारत सरकार लगातार पाकिस्तान से उसे सौंपने की बात कहती रही, लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसके वहां होने से इनकार करता रहा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में जारी 20 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में गजिंदर का नाम भी शामिल था।

1981 में एयर इंडिया के विमान को दिल्ली से हाईजैक लाहौर ले गया था गजिंदर

14 साल जेल में सजा भुगतने के बाद भी गजिंदर को पाक ने भारत को नहीं सौंपा

अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मना रहे लोगों पर चढ़ाई गाड़ी, दो की मौत

न्यूयार्क, एपी : अमेरिका के मैनहट्टन में एक पार्क में स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मना रहे लोगों पर एक शख्स ने पिकअप वाहन चढ़ा दी। दो लोगों की मौत हो गई जबकि नौ अन्य घायल हो गए। यह घटना गुरुवार रात नौ बजे के आसपास की है।

न्यूयार्क पुलिस विभाग के चीफ जैफ्री मेड्रे ने कहा कि फोर्ड एफ 150 काफी तेज गति से आया और चौराहे को पार करते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया। इसके बाद वह मैनहट्टन के कार्लियर्स हुक पार्क में जश्न मना रहे लोगों को टक्कर मार दी। दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों में चार की हालत गंभीर है। तीन बुरी तरह घायल हुआ है और दो को मामूली चोटें आई हैं।

अमेरिकी जांचकर्ताओं ने किसी भी आतंकी हमले की आशंका को खारिज किया है। पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहीं चालक ने शराब तो नहीं पी रखी थी।

बाइडन ने कहा, कहीं नहीं जा रहा...चुनाव लड़ूंगा

वाशिंगटन, रायटर : राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर उठ रहे सवालों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने साफ कर दिया है कि वह कहीं नहीं जा रहे, सक्रिय राजनीति में रहेंगे और नवंबर में होने वाला चुनाव लड़ेंगे। बाइडन ने यह बात तब कही है जब उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता, सांसद और चंदा देने वाले उनकी उम्मीदवारी को कमजोर बताते हुए उन्हें (बाइडन को) चुनाव मैदान से हटाने की आवश्यकता जता चुके हैं।

81 वर्षीय बाइडन ने कहा, वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं। इसलिए उनके चुनाव में उम्मीदवारी से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। 27 जून को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई सार्वजनिक बहस में कमजोर पड़ने के बाद बाइडन की लोकप्रियता में गिरावट आई है और उनकी क्षमता पर डेमोक्रेटिक पार्टी में ही सवाल उठ रहे हैं। बाइडन ने अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर चार जुलाई को व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर अपनी उम्मीदवारी की जोरदार ढंग से वकालत की।

उन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे से अपने वक्तव्य की शुरुआत की और उसके बात अमेरिकी इतिहास से जुड़ी कई बातों के साथ अपनी उम्मीदवारी की भी बात कही। टेलीप्रोम्पटर के जरिये दिए गए इस वक्तव्य में एक मौके पर वह गड़बड़ाए लेकिन बाद में संभल गए।

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ

चंदादाताओं ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर प्रत्याशी बदलने का बढ़ाया दबाव

दक्षिण कोरियाई नेता पर हमला करने वाले को 15 वर्ष की सजा

सियोल, एपी : दक्षिण कोरियाई की एक अदालत ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पर हमला करने वाले शख्स को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। यह हमला इस वर्ष जनवरी में किया गया था। हमलावर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता की हत्या के प्रयास और चुनाव कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। हमलावर के पास अपील के लिए एक सप्ताह का समय है।

अदालत ने व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की है। हालांकि, पुलिस ने पहले कहा था कि हमलावर 67 वर्ष का है। जनवरी में एक कार्यक्रम के दौरान हमलावर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख ली जे-म्युंग से आटोग्राफ मांगने पहुंचा था। उनके पास पहुंचते ही उसने ली पर चाकू से हमला बोल दिया था। पुलिस पूछताछ के दौरान, हमलावर ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों पर ली के खिलाफ अधिकारियों की जांच से नाखुश था।

मास्को पहुंचे आर्बन, यूक्रेन में शांति की कोशिश

मास्को, एपी : यूरोपीय संघ में शामिल लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नजदीक माने जाने वाले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर आर्बन शुक्रवार को मास्को पहुंचे। माना जा रहा है कि आर्बन यूक्रेन में शांति के प्रस्ताव के साथ मास्को पहुंचे हैं। इससे कुछ दिन पहले आर्बन ने यूक्रेन का अचानक दौरा कर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी और वहां दोनों नेताओं में युद्धविराम के कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी।

आर्बन ने कहा है कि हंगरी यूरोप का इकलौता देश है जो सभी से बात कर सकता है। हंगरी निष्पक्ष है। सूत्रों के अनुसार आर्बन से मुलाकात से पहले पुतिन को बताया गया है कि हंगरी के प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रतिनिधि के तौर पर मास्को आए हैं। वैसे उनके मास्को दौरे की कई यूरोपीय नेताओं ने निंदा भी की है। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता एरिक मेमर ने कहा है कि यह दौरा शांति के लिए नहीं बल्कि तुष्टीकरण के लिए है। आर्बन ही वह नेता हैं जो 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में रूस पर प्रतिबंध लगाने पर सबसे अंत में तैयार हुए। उससे पहले उन्होंने प्रतिबंधों को टालने की हर संभव कोशिश की। शुक्रवार को आर्बन की पुतिन से 14 वीं बार मुलाकात हुई है। सूत्रों के अनुसार पुतिन ने आर्बन से कहा है कि युद्धविराम और उसकी शर्तों को लेकर पहले वह यूरोपीय सहयोगियों में आमराय कायम करें। इसके बाद शांति प्रस्ताव पर द्विपक्षीय वार्ता होगी।

- हंगरी के पीएम ने चंद रोज पहले की थी जेलेंस्की से मुलाकात
- पुतिन के सबसे करीबी यूरोपीय नेता हैं विक्टर आर्बन

मास्को में शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर आर्बन (बाएं)। एएफपी

रूसी हमलों में तीन यूक्रेनी मरे, 22 घायल

यूक्रेन में शुक्रवार को रूसी हमले में तीन लोग मारे गए और 22 घायल हुए। रूसी सेना ने यह हमला डोनेस्क प्रांत के नियंत्रण वाले इलाके में किया है। हमले में सेलिदोव कस्बे में दो लोग मारे गए हैं और दो घायल हुए हैं। नजदीक के ही कोमर गांव में रूसी सेना के गाइडेड बमों से एक महिला की मौत हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं। जबकि रूस के क्रैस्नोडर इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक बच्चा मारा गया है। इस बीच शुक्रवार को यूक्रेन को तीसरा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जर्मनी से मिले इस सिस्टम से रूसी हमलों से बहुत से यूक्रेनी नागरिकों की रक्षा हो पाएगी। बता दें दोनों देश दो साल से ज्यादा समय से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं।

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर मनी लांड्रिंग का आरोप लगा

साओ पाउलो, रायटर : ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर सऊदी अरब की ओर से दी गई लक्जरी आइटम के साथ ही देश के प्रमुख के रूप में प्राप्त हीरे के उपहार के कथित दुरुपयोग का आरोप लगा है। यह दूसरी बार है, जब पुलिस ने बोल्सोनारो पर औपचारिक रूप से किसी अपराध का आरोप लगाया है। इससे पहले मार्च में उन पर अपने कोविड-19 वैक्सीन रिकार्ड में जालसाजी का आरोप लगाया गया था।

उपहार में मिले आभूषणों का मूल्य 32 लाख डालर था। इनमें सऊदी सरकार द्वारा बोल्सोनारो और पूर्व प्रथम महिला मिशेल बोल्सोनारो को दिया गया हीरे का हार, अंगूठी, घड़ी और बालियां शामिल थीं। कुछ आभूषण अक्टूबर 2021 में साओ पाउलो के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिए गए थे, जब वे रियाद से लौट रहे एक सरकारी सहयोगी के बैकपैक में पाए गए थे। पुलिस ने बोल्सोनारो पर मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया है।

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। फाइल/एएफपी

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट को अभी तक नवीनतम अभियोग के साथ पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद अभियोजक जनरल पाउलो गोनेट दस्तावेज का विश्लेषण करेंगे और निर्णय लेंगे कि क्या आरोप दायर किया जाए और बोल्सोनारो पर ट्रायल चलाया जाए। इसे लेकर बोल्सोनारो ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है।

वेटिकन ने आर्कबिशप कार्लो मारिया विगानो को बहिष्कृत किया

रोम, एपी : वेटिकन ने अमेरिका में अपने पूर्व राजदूत आर्कबिशप कार्लो मारिया विगानो को फूट डालने का दोषी पाते हुए बहिष्कृत कर दिया है। वेटिकन के सिद्धांत कार्यालय ने गुरुवार को अपने सदस्यों की बैठक के बाद यह प्रतिबंध लगाया। इसमें विगानो द्वारा सर्वोच्च पोप को मान्यता देने और उनके अधीन रहने से इन्कार करने, अपने अधीनस्थ चर्च के सदस्यों के साथ संवाद को अस्वीकार करने और द्वितीय वेटिकन परिषद की वैधता और न्यायिक अधिकार को अस्वीकार करने का हवाला दिया गया।

फूट डालने का मामला तब होता है, जब कोई व्यक्ति पोप के प्रति या उनके अधीन कैथोलिकों की संगति से समर्पण वापस ले लेता है। आर्कबिशप को शुक्रवार को फैसले की जानकारी दी गई। इसके बयान में पोप का उल्लेख नहीं था, लेकिन इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है कि सजा फ्रांसिस की मंजूरी के बिना दी गई हो।

म्यांमार में मिलिशिया ने सैन्य शासन के खिलाफ फिर से हमले शुरू किए

बैंकाक, एपी : पूर्वोत्तर म्यांमार में एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई है, जिससे चीन की मध्यस्थता में किया गया संघर्ष विराम खत्म हो गया है। सैन्य शासन पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि देश में कई मोर्चों पर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। मिलिशिया संगठनों में से एक ता आंग नेशनल लिबरेशन आर्मी (टीएनएल) ने पिछले हफ्ते शान में शासन के ठिकानों पर फिर से हमला बोला था। वहीं मिलिशिया की संयुक्त सेना ने कथित तौर पर शासन के उत्तरपूर्वी सैन्य कमान के मुख्यालय लशियो को शुक्रवार तक घेर लिया था। टीएनएलए के प्रवक्ता लवे याय ओ ने कहा कि यह अक्टूबर के आक्रमण का अगला चरण है।

उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि सेना ने संघर्ष विराम के बावजूद तोपखाने और हवाई हमले कर जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सैन्य शासन को उखाड़ फेंकना और लोगों की सुरक्षा है।

नेपाल में 12 को विश्वास मत के लिए प्रस्ताव रखेंगे प्रचंड

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 12 जुलाई को संसद में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के प्रमुख प्रचंड इसी सप्ताह 78 सांसदों वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) का समर्थन खो चुके हैं और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है लेकिन प्रचंड ने पद छोड़ने से इन्कार कर दिया है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने संसद के सचिवालय को पत्र लिखकर 12 जुलाई को विश्वास मत के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा है। प्रचंड ने संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सहयोगी दलों की समर्थन वापसी के बाद प्रतिनिधि सभा में बहुमत साबित करने के लिए यह पहल की है। सहयोगी दलों की समर्थन वापसी के 30 दिन के भीतर प्रधानमंत्री को संसद में अपना बहुमत साबित करना होता है।

नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन (यूएमएल) ने 89 सांसदों वाली नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का फैसला किया है। नई सरकार में डेढ़ वर्ष के लिए ओली प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद शेष कार्यकाल के लिए नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा सरकार का नेतृत्व करेंगे।

प्रचंड की पार्टी के प्रतिनिधि सभा में 32 सदस्य हैं। उन्हें दस सांसदों वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (यूएस) का समर्थन प्राप्त है। माना जा रहा है कि प्रचंड को प्रतिनिधि सभा में 63 सांसदों का समर्थन मिल सकता है। लेकिन सरकार को बचाने के लिए प्रचंड को 138 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

पुष्प कमल दहल प्रचंड। फाइल/रायटर

सरकार को अधिकतम 63 सांसदों का समर्थन मिलने के आसार

इमरान खान ने फवाद चौधरी से मिलने से किया इन्कार

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के संस्थापक इमरान खान ने अपनी पार्टी के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी से जेल में मिलने से इन्कार कर दिया। एआरवाई न्यूज के 'आफ दी रिकार्ड' कार्यक्रम में पीटीआइ के प्रवक्ता रऊफ हसन ने कहा कि फवाद चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान से मिलना चाहते थे। हसन ने कहा कि पीटीआइ के सदस्य अली जैदी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी को पार्टी से बर्खास्त किए जाने के कारण से अवगत हैं। इस समय फवाद के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। इमरान खान अपनी रिहाई के बाद पार्टी छोड़ने वालों की वापसी के बारे में फैसला लेंगे।

****

हम बहुत भाग्यशाली हैं कि सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ी हमारी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वह बहुत अनुभवी हैं और हम चाहते हैं कि वह सामने से टीम का नेतृत्व करें।
– **जस्टिन सैमंस**, मुख्य कोच, जिंबाब्वे

प्रधानमंत्री ने पूछा, नृत्य कर ट्राफी लेना क्या चहल का आइडिया था

नई दिल्ली, जेएनएन : विश्व कप जीतने के बाद स्वदेश लौटने पर भारतीय टीम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ फाइनल मुकाबले को लेकर बात की। इस दौरान खूब हंसी मजाक हुआ और ठहाके भी लगे। खासतौर पर युजवेंद्रा चहल के साथ पीएम मोदी का तालमेल सबसे मजेदार था।

प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शुक्रवार को इस मुलाकात का वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इस यादगार जीत के लिए आप सभी को मेरी ओर से बधाई। आमतौर पर मैं दफ्तर में देर रात काम करता रहता हूं, लेकिन खिताबी मुकाबले के समय मैं काम के साथ-साथ टीवी पर मैच भी देख रहा था। आपने टीम भावना, हुनर और हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत दिखाई है। पूरी टीम में आत्मविश्वास झलक रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रोहित से पूछा कि ये नृत्य करते हुए ट्राफी लेने का आइडिया किसका था। इस पर रोहित ने कहा कि ये मेरा अंतिम विश्व कप था और साथी खिलाड़ी चाहते थे कि मैं ट्राफी लेने ऐसे ही नहीं जाऊं और कुछ विशेष करूं। इस पर मोदी ने पूछा क्या यह चहल का आइडिया था तो रोहित कहते हैं हां, यह चहल और कुलदीप का आइडिया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने पिच पर मिट्टी चखने के पीछे का कारण पूछा। इस पर रोहित ने कहा, कई बार हम विश्व कप जीतने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन इस बार सभी की वजह से हम यह हासिल कर पाए। इसलिए यह पिच मेरे लिए यादगार है और बहुत मायने रखती है इसलिए मैंने ऐसा किया।

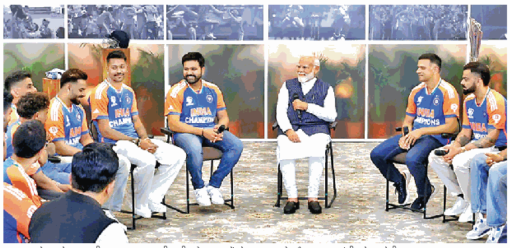

गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर भारतीय टीम के सदस्यों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● आइएएनएस

रिषभ पंत की चोट और टीम में वापसी पर पीएम मोदी ने कहा, मुझे आप पर गर्व है कि आपने इतने मुश्किल समय से लड़कर वापसी की। जब आपके साथ हादसा हुआ था तो मैंने आपकी मां से भी बात की थी। मैं आपकी प्रगति पर लगातार नजर रख रहा था। टीम के हर खिलाड़ी से प्रधानमंत्री ने बात की। उन्होंने मैच के हर क्षण को याद किया और उनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि उन्होंने पूरे मुकाबले का लुत्फ उठाया। चाहे वो हार्दिक का मैच टर्निंग विकेट हो या बुमराह की सटीक गेंदबाजी या फिर सूर्या का मैच जिताऊ कैच... पीएम मोदी ने हर निर्णायक क्षण के बारे में खिलाड़ियों से बात की।

सूर्य कैच छोड़ता तो मैं उसे बैठा देता : रोहित

- महाराष्ट्र विधान भवन में रोहित, सूर्य, यशस्वी और शिवम को किया गया सम्मानित
- भारतीय टीम को महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिलेगा 11 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, मुंबई : टी-20 विश्व कप जीतने वाले टीम में शामिल मुंबई के क्रिकेटरों को शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित किया। इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मराठी में फाइनल में सूर्यकुमार के मैच जिताऊ कैच का किस्सा सुनाते हुए कहा कि सूर्य ने अभी बताया कि कैच उसके हाथों में आकर बैठ गई। अच्छा हुआ कि गेंद आकर उसके हाथ में बैठ गई नहीं तो मैं उसे बैठा देता (टीम से बाहर)। इस पर विधान भवन में बैठे सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे।

महाराष्ट्र सरकार ने रोहित, यशस्वी, शिवम दुबे और सूर्यकुमार, गेंदबाजी कोच पारस म्हांब्रे को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय टीम को 11 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की भी घोषणा की। रोहित ने कहा कि हमने विश्व कप जीतने के लिए 2013 से 11 साल इंतजार किया। यह पूरी टीम, कोच व सपोर्ट स्टाफ की सफलता है। कप्तान ने गुरुवार शाम को विजय परेड के दौरान भीड़ को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए मुंबई पुलिस को धन्यवाद दिया।

रोहित-सूर्य का महाराष्ट्र विधानसभा में स्वागत हुआ ● एएनआइ

विजय परेड के दौरान प्रशंसकों के असीम प्यार ने साबित कर दिया कि टी-20 विश्व कप सिर्फ उनकी टीम के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिये क्या मायने रखता है। आप इस रोमांच से अनुमान लगा सकते हैं। मुझे खुशी है कि हम इस तरह का कुछ हासिल कर सके। - **रोहित शर्मा**, बीसीसीआइ टीवी से

एक नजर में

दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने सीरीज में बनाई बढ़त

चेन्नई : दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने तजमिन ब्रिट्स (81 रन) और मारिजाने कैप (57 रन) के अर्धशतकों की मदद से शुक्रवार को यहां पहले टी-20 में भारत को 12 रन से शिकस्त देकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। ब्रिट्स ने 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में 10 चौके और तीन छक्के जड़े जबकि कैप ने 33 गेंद की पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया। दक्षिण अफ्रीका ने 189 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया जिसके जवाब में भारतीय टीम जेमिमा (नाबाद 53 रन) के अर्धशतक के बावजूद चार विकेट पर 177 रन ही बना सकी। (प्रेट्र)

प्रगनानंद ने खेला ड्रा

बुखारेस्ट : भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनानंद ने सुपरबेट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट के आठवें दौर में अमेरिका के फाबियानो कारुआना से ड्रा खेला, जबकि विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश ने नीदरलैंड्स के अनीश गिरि से बाजी बराबरी पर खत्म की। चौथी बार एक भी मुकाबले का नतीजा नहीं निकला और सभी बाजियां ड्रा रही। कारुआना ने 10 खिलाड़ियों के राउंड राबिन टूर्नामेंट में आधा अंक की बढ़त बना रखी है। (प्रेट्र)

आडवाणी फाइनल में पहुंचे

रियाद : भारत के क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी एशियाई बिलियर्ड्स में हैट्रिक बनाने के करीब हैं, जिन्होंने हमवतन सौरव कोठारी को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आडवाणी ने हर फ्रेम में 100 का स्कोर किया। उन्होंने 100-29, 100-33, 101-38, 100-21, 100-0 से जीत दर्ज की। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में उन्होंने भारत के ही सूर्यनारायणन को हराया था। (प्रेट्र)

राजावत क्वार्टर फाइनल में

कैलगरी : भारत के उदीयमान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए जापान के ताकुमा ओबायाशी को सीधे गेम में हराकर कनाडा ओपन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने इस मुकाबले में 33वीं रैंकिंग वाले ओबायाशी को 38 मिनट में 21-19, 21-11 से हराया। (प्रेट्र)

जिंबाब्वे में नई शुरुआत करने उतरेगी टीम

गिल की अगुआई में आज खेलेगी पहला टी-20 मैच रजा कर रहे मेजबान का नेतृत्व

हरारे, प्रेट्र : रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना की युवा ब्रिगेड जिंबाब्वे के विरुद्ध शनिवार से शुरू हो रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज में उतरेगी तो इस प्रारूप में यह भारतीय क्रिकेट के नए दौर का सूत्रपात भी होगा।

भारत में टी-20 विश्व कप की जीत के सतत जारी जश्न के बीच शुभमन गिल की कप्तानी वाली आइपीएल सितारों से सजी यह युवा टीम जीत का अपना सिलसिला शुरू करना चाहेगी। आइपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले पंजाब के अभिषेक शर्मा और राजस्थान रायल्स के लिए खेलने वाले असम के रियान पराग इस सीरीज के जरिये पदार्पण करेंगे।

पिछले कुछ वर्ष में रोहित और कोहली टी-20 क्रिकेट में कई द्विपक्षीय सीरीज से बाहर रहे हैं। अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दोनों के संन्यास के बाद उनकी कमी जरूर खलेगी। इसकी भरपाई करना तो मुश्किल है, लेकिन फिर परिवर्तन संसार का नियम है। जिंबाब्वे मजबूत टीम नहीं है, लेकिन टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच बहुत गहरा अंतर नहीं है। आइपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले सिकंदर रजा भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं।

शिवम दुबे, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल तीसरे मैच से ही उपलब्ध होंगे। भारत के भावी टी-20 कप्तान हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, रिषभ पंत, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव भी भविष्य में इस प्रारूप में लौटेंगे लिहाजा अंतिम एकादश में ज्यादा जगह खाली नहीं है। अब से 2026 टी20 विश्व कप तक भारतीय टीम इस प्रारूप में 34 मैच खेलेगी।

कप्तान गिल पारी का आगाज करेंगे और देखना होगा कि उनके अजीज दोस्त अभिषेक शर्मा को पदार्पण का अवसर मिलता है या चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ खेलते हैं। अभिषेक पारी की शुरुआत करते हैं तो गायकवाड़ तीसरे नंबर पर उतर सकते हैं। पराग चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं लिहाजा उनके चयन की संभावना अधिक है। टी-20 क्रिकेट के आक्रामक फिनिशर रिंकू सिंह पांचवें नंबर पर उतर सकते हैं जबकि छठे नंबर पर जितेश शर्मा या ध्रुव जुरेल को उतारा जा सकता है। गेंदबाजी में आवेश खान और खलील अहमद का खेलना तय है जबकि डैथ ओवरों के खतरनाक गेंदबाज मुकेश कुमार तीसरे तेज गेंदबाज होंगे।

सिकंदर रजा ● शुभमन गिल ●

अलकराज ने रोमांचक मैच में टियाफो को दी शिकस्त

लंदन, एपी : गत चैंपियन कार्लोस अलकराज ने शुक्रवार को रोमांचक मैच में वापसी करते हुए फ्रांसेस टियाफो को 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (2), 6-2 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। पुरुषों के अन्य मुकाबले में डेनमार्क के होल्गर रुने ने ब्राजील के थियागो सेबोथ को हराकर तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली।

तीसरी वरीयता प्राप्त अलकराज को नंबर 29 टियाफो ने काफी समय तक संघर्ष करने पर मजबूर किया, लेकिन गत चैंपियन ने अंत में वापसी करते हुए मैच को अपने नाम किया। टियाफो उस जीत को प्राप्त नहीं कर पाए, जो उनके लिए आश्चर्यजनक जीत होती, क्योंकि चोट के बाद विंबलडन में पहुंचे थे और इस सीज़न में हार का रिकार्ड बनाया था। हालांकि, वह निश्चित रूप से जीत के करीब आ गए थे। वहीं, अन्य मुकाबले में डेनमार्क के होल्गर रुने ने ब्राजील के थियागो सेबोथ के विरुद्ध 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 से जीत प्राप्त की और तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली।

कार्लोस अलकराज ● एएफपी

जीत के साथ पाओलिनी चौथे दौर में पहुंचीं : जैस्मिन पाओलिनी ने सातवीं वरीयता प्राप्त पूर्व अमेरिकी ओपन चैंपियन बियांका आंद्रीस्कु को 7-6(4), 6-1 से हराकर पहली बार चौथे दौर में जगह बनाई। फ्रेंच ओपन की उपविजेता शुरुआती तीन प्रमुख ग्रैंड स्लैम के अंतिम 16 में पहुंचने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गईं।

पुरुष डबल्स के पहले दौर में थमा एंडी मरे का सफर

एंडी मरे को पुरुष डबल्स के पहले दौर में रिंकी हिजिकाटा और जान पीयर्स के विरुद्ध 7-6(6), 6-4 से हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके लिए निराशाजनक था। इस हार के बाद वह काफी भावुक नजर आए। मुकाबले के बाद प्रशंसकों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। मरे के लिए टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक और वीनस विलियमस ने विदाई संदेश भेजा।

भारोत्तोलन में मीराबाई पर होगा दरोमदार

पेरिस ओलिंपिक 20 दिन शेष

सुकांत सौरभ ● जागरण

नई दिल्ली : टोक्यो में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू पर एक बार फिर पेरिस में भारत्तोलन का दारोमदार होगा। वह पेरिस ओलिंपिक के लिए कोटा प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। पेरिस 2024 मीराबाई चानू का तीसरा ओलिंपिक होगा। रियो 2016 में निराशाजनक शुरुआत के बाद, 30 वर्षीय मणिपुरी एथलीट ने वैश्विक प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के साथ प्रभावशाली वापसी की और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। हालांकि, टोक्यो ओलिंपिक के बाद चोट उनके लिए समस्या रही, पर इस वर्ष विश्व कप में 12वें स्थान पर रहकर उन्होंने देश के लिए ओलिंपिक कोटा प्राप्त कर लिया और अब दूसरे पदक की तलाश में हैं।

मीराबाई चानू ●

विशेष बातचीत में चानू ने बताया, 'विगत कुछ महीनों में मेरे प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ है। हालांकि, अब से लेकर सात अगस्त तक, जिस दिन पेरिस में भारोत्तोलन प्रतियोगिता शुरू होगी, मेरे शरीर की सभी मांसपेशियों को देख-भाल करने और स्नैच में कम से कम 90 किलोग्राम उठाने की तकनीक में सुधार के लिए समर्पित करूंगी।'

वहीं, पेरिस में 49 किग्रा भार वर्ग में स्नैच और क्लीन एंड जर्क भारोत्तोलन स्पर्धा में सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी के संबंध में चानू ने कहा, 'यह सबसे मुश्किल भार वर्ग है। टोक्यो में स्वर्ण जीतने वाली चीन की होऊ झिहुई इस बार भी शीर्ष फार्म में हैं। मेरा प्रयास यही होगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूं।'

मेसी के पेनाल्टी चूकने के बावजूद जीता अर्जेंटीना

ह्यूस्टन, एपी : गत चैंपियन अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका 2024 के क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान इक्वाडोर के विरुद्ध जीत दर्ज करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। टीम ने निर्धारित समय तक 1-1 से बराबरी के बाद पेनाल्टी शूटआउट में इक्वाडोर को 4-2 से हराया।

लियोन मेसी ने गुरुवार को अर्जेंटीना के लिए पेनाल्टी शूटआउट में पहला प्रयास ही गंवा दिया, लेकिन उनकी इस गलती पर गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने इक्वाडोर के शुरुआती दो प्रयास विफल कर पर्दा डाल दिया। अर्जेंटीना की ओर से लिसांद्रो मार्टिनेज ने 35वें मिनट में गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी थी, परंतु दूसरे हाफ के स्टापेज टाइम में इक्वाडोर के केविन रोड्रिग्ज ने टीम को बराबरी दिला दी। इससे पहले 62वें मिनट में कप्तान एनर वैलेंसिया ने रोड्रिगो के फाउल पर मिली पेनाल्टी अवसर गंवा दिया था। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई।

आज का मैच
वेनेजुएला vs कनाडा
सुबह 6.30 बजे स्थान: आर्लिंगटन

पेनाल्टी शूटआउट में गोल का बचाव करते एमिलियानो मार्टिनेज ● एएफपी

इंग्लैंड के सामने स्विस चुनौती

डुसेलडोर्फ, एपी : यूरो 2024 में अब तक बेपटरी दिखी इंग्लिश टीम के सामने शनिवार को मजबूत स्विस चुनौती होगी। इंग्लिश टीम की फार्म अब तक पटरी पर नहीं रही है। प्री-क्वार्टर फाइनल में भी स्लोवाकिया के विरुद्ध जूड बेलिंघम ने इंग्लैंड को स्टापेज टाइम में गोल दागकर बचाया था। इसके बाद अतिरिक्त समय में टीम जीत गई पर अब तक एक भी प्रभावशाली जीत प्राप्त करने में विफल रही है। वहीं, दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स की भिड़ंत तुर्किये से होगी।

राष्ट्रीय फलक

ऐसा उमड़ा जनसैलाब, लगा जूतों का अंबार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

- जूते और चप्पलों को पांच जीपों में एकत्र किया गया, कचरा हटाने के लिए दो डंपरों का भी किया उपयोग
- टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के स्वागत के लिए मरीन ड्राइव पर उमड़ा था जनसैलाब

टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का गुरुवार शाम अद्भुत, अविश्वसनीय स्वागत किया गया। चैंपियन टीम के स्वागत के लिए उमड़े जनसैलाब का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वागत कार्यक्रम के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव पर भीड़ द्वारा छोड़े गए जूतों, पानी की बोतलों सहित 10-12 मीट्रिक टन कचरे को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने सात वाहनों में इकट्ठा किया। बीएमसी ने शुक्रवार को बताया कि विजय परेड के बाद गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि तक सफाई अभियान चलाया गया।

बीएमसी के अनुसार सफाई अभियान के दौरान बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के रैपर और पानी की बोतलों के साथ-साथ भारी मात्रा में जूते और चप्पल भी एकत्र किए गए। कचरे में से जूते और चप्पलों को पांच जीपों में एकत्र किया गया तथा मौके से कचरा उठाने के लिए दो डंपरों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सफाई अभियान गुरुवार रात 11.30 बजे से शुक्रवार सुबह आठ बजे तक चला।

इसमें नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के सौ कर्मचारियों सहित कुछ गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। बीएमसी ने कहा कि कचरे को डंपिंग ग्राउंड में भेजने के बजाय रिसाइक्लिंग प्लांट में भेजा जाएगा।

टी-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम की विजय परेड में उमड़ी भीड़ द्वारा छोड़े गए जूते-चप्पल। प्रेट्र

बता दें कि विजय परेड के मार्ग पर भारी भीड़ के कारण 11 लोगों को मामूली चोटें आने या चक्कर आने के कारण अस्पताल भी भेजना पड़ा था।

बलिदानी अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को नहीं मिला मुआवजा : राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दोहराया कि बलिदानी अग्निवीर अजय कुमार के स्वजन को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। मोदी सरकार अग्निवीरों के साथ भेदभाव कर रही है।

कांग्रेस नेता ने बलिदानी अजय कुमार के पिता का कथित वीडियो भी एक्स पर साझा किया जिसमें वह कह रहे हैं कि उनके परिवार को निजी बैंक से बीमा राशि के रूप में 50 लाख रुपये और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 48 लाख रुपये मिले हैं। वीडियो में राहुल ने सवाल उठाया कि बलिदानी के स्वजन को मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया गया, उसके परिवार के बैंक खाते में वेतन का बकाया क्यों नहीं भेजा गया।

राहुल ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'मुआवजे एवं बीमे की राशि में अंतर होता है। बलिदानी के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी से भुगतान प्राप्त हुआ है।' वीडियो में बलिदानी के पिता ने कहा, परिवार को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला है। उनका कहना है कि परिवार को सभी सुविधाएं एवं पेंशन मिलनी चाहिए।

मां वैष्णो देवी भवन पर हृदयगति रुकने से उप्र के श्रद्धालु की मौत

जागरण संवाददाता, कटड़ा : मां वैष्णो देवी के दर्शन करने को स्वजन के साथ आए एक श्रद्धालु की भवन पर हृदयगति रुक जाने से मौत हो गई। श्रद्धालु की पहचान दिलीप कुमार निवासी बाबूगंज, जीटी रोड, एटा, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, श्रद्धालु दिलीप कुमार गुरुवार देर रात भवन पर दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। तभी प्राचीन गुफा के पवित्र आरती स्थल के पास वह अचेत हो गए। उन्हें पुलिस के जवान व श्राइन बोर्ड कर्मी उठाकर तुरंत भवन स्थित डिस्पेंसरी लाए, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डाक्टरों ने मौत की वजह हृदयगति रुकना बताई है। कटड़ा के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

शिवखोड़ी में हृदय गति रुकने से श्रद्धालु की मौत

जागरण संवाददाता, रियासी : जम्मू संभाग के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी में शुक्रवार को दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के एक श्रद्धालु की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। पुलिस ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के तिलक नगर की सैनिक कालोनी के रहने वाले अनिल कुमार पोरवाल परिवार सहित शिवखोड़ी धाम में दर्शन के लिए आए थे। शिवखोड़ी गुफा से 50 मीटर पहले उनको दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर गए।

संतकबीर नगर में ट्रैक्टर से गिरकर की मृत्यु

जासं, संतकबीर नगर : उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर में बोरिंग का काम कर रहे पंजाब के व्यक्ति की गुरुवार रात ट्रैक्टर से गिरकर मृत्यु हो गई।

पंजाब के मानसा जिले के सरदार लाली सिंह करीब पांच माह से खलीलाबाद क्षेत्र में अजीत पांडेय के यहां रहकर बोरिंग करने का काम कर रहे थे। गुरुवार रात करीब 11.30 बजे वह मालिक के ट्रैक्टर से गिर गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक के स्वजन को अवगत करा दिया गया है।

बरेली में हत्याकांड के बाद महिलाओं के अकेले खेत जाने पर रोक

जागरण संवाददाता, बरेली : पिछले वर्ष बरेली के शाही-शेरगढ़ क्षेत्र में सात महिलाओं की हत्या हुई थी। सभी को गला घोटकर या दबाकर मारा गया था। अब उसी तरह का एक और हत्याकांड मंगलवार को हुआ। हत्यारे का सुराग लगाने में जुटी पुलिस ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया। शुक्रवार को ग्रामीणों के बीच पहुंचे एसपी ने सलाह दी कि महिलाएं अकेले खेतों पर न जाएं। पूर्व में प्रमुख रास्तों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी सही कराया जा रहा है।

शाही-शेरगढ़ क्षेत्र में पिछले वर्ष एक-एककर सात महिलाओं की हत्या हुई थी। सभी के शव खेतों के किनारे मिले थे। हत्या का तरीका भी समान था। उस समय गांवों में अफवाह फैल गई कि कोई सिरफिरा अकेली महिलाओं की हत्या कर जाता है। हालांकि, बाद में पांच महिलाओं की हत्या का राजफाश करते हुए पुलिस ने उनके परिचितों को जेल भेजा था। सतर्कता के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे। छह महीने कोई वारदात नहीं हुई। मंगलवार को अनीता देवी का शव रात शाही-शेरगढ़ मार्ग पर मिला। उनका भी गला घोटा गया था।

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग

जोश नई राहों का

शनिवार, 6 जुलाई, 2024

आनलाइन लर्निंग

इंटरव्यू में यूं करें प्रभावित

बीते दिनों जारी नौकरीडाटकाम की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, करीब 92 प्रतिशत नियोक्ता इस साल नई हायरिंग या रिप्लेसमेंट हायरिंग के बारे में विचार कर रहे हैं। ये सभी हायरिंग ह्वाइट कालर जाब्स के लिए होने वाली हैं। नई तकनीकों के आने से पिछले साल की तुलना में इस साल टेक हायरिंग भी अधिक होने की उम्मीद की जा रही है। कारपोरेट क्षेत्र में कोई भी नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। लेकिन बहुत से लोग इसे क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आइए जानें, कुछ वेबसाइट की मदद से कैसे हम इंटरव्यू की बेहतर तैयारी कर सकते हैं...

जाब इंटरव्यू की बात आते ही तकरीबन हर किसी की घबराहट बढ़ जाती है। क्योंकि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछ लिए जाएंगे, इस बारे में किसी को नहीं पता होता है। लेकिन यदि आप पहले से अपने डोमेन के अनुसार इंटरव्यू की तैयारी करके किसी भी नियोक्ता के सामने जाएंगे, तो आपकी सफलता के अवसर ज्यादा होंगे। इसके लिए यहां दी गई वेबसाइट्स की मदद ले सकते हैं:

इंटरव्यू गाइज: जाब इंटरव्यू की तैयारी के लिए यह एक अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाब सर्च, करियर एडवाइस, जाब इंटरव्यू तथा रेज्यूमे व कवर लेटर राइटिंग जैसे फीचर्स की मदद से खुद को तैयार कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइज (theinterviewguys.com) की इस वेबसाइट पर लोगों को इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाता है, जैसे कि आपकी बाडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इंटरव्यू में कैसे सफल हो सकते हैं, फील्ड के हिसाब से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका सही जवाब कैसे देना चाहिए आदि।

इंटरव्यू स्कूल: यह वेबसाइट भी माक इंटरव्यू को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है। इंटरव्यू स्कूल (interviewschool.com) में आपको एआइ फीडबैक, लाइव इंटरव्यू कोचिंग और जाब ट्रैकिंग के टूल्स मिलते हैं। एआइ माक इंटरव्यू साफ्टवेयर की मदद से अपने अगले इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना यहां ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि वीडियो माक इंटरव्यू से यह पता चल जाएगा कि इंटरव्यू के दौरान आपकी बाडी लैंग्वेज कैसी रहती है और कहां आपको सुधार करने की जरूरत है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंटरव्यू के परफार्मेंस को मार्क्स भी दे सकते हैं। यदि चाहें, तो यहां पर अपने माक इंटरव्यू को रिकार्ड भी कर सकते हैं।

धीरेंद्र पाठक

एक्स्ट्रा शाट

टी-20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की बड़ी जीत टीम के हर खिलाड़ी के जज्बे की ऐसी सच्ची कहानी है, जिसमें युवाओं के लिए आगे बढ़ने की बड़ी सीख है। कैसे, बता रहे हैं अरुण श्रीवास्तव...

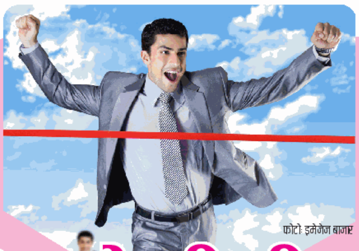

फोटो: इमेजेज बाजार

जज्बे की जीत

गत शनिवार को वेस्टइंडीज के बारबाडोस में टी-20 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में जब भारत के 176 रनों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम को 30 गेंदों पर मात्र 30 रन बनाने थे, तो जैसे सभी भारतीयों की सांसें अटक गई थीं। सबको यही लग रहा था कि अब मैच और विश्व कप हाथ से गया। ज्यादातर लोगों ने तो निराशा और हताशा में अपने टीवी तक बंद कर दिए। पर नहीं। मैच अभी बाकी था। यही वह क्षण था, जब पासा पलटना शुरू हो गया। कूल कप्तान रोहित शर्मा ने अपने जांबाजों को एकत्रित कर उन्हें मंत्र दिया कि हमें हार नहीं माननी है, हर गेंद पर लड़ना है और हर हाल में जीतना है। फिर क्या था। सभी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। इसका नतीजा भी दिखने लगा। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे और रन रेट दक्षिण अफ्रीका के काबू से बाहर होता गया। मैच का रुख बदलता गया। मिलर के बल्ले से जो गेंद छह रन के लिए मैदान से बाहर जा रही थी, उसे सूर्यकुमार यादव ने ऐन सीमा रेखा पर जिस धैर्य और फुर्ती से लपका, उसे शायद ही कोई भुला सकेगा। उन्होंने अप्रत्याशित कारनामा कर दिखाया। गेंद यदि छह रन के लिए बाहर चली जाती, तो न केवल दक्षिण अफ्रीका जीत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता, बल्कि आक्रामक मिलर नाटआउट रहते हुए आसानी से जीत दिला देते। इसके बाद तो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने संयम रखते हुए अपनी गेंदबाजी के हुनर का कमाल दिखाया। जिन्होंने अपने टीवी बंद कर दिए थे, शोर और पटाखों की आवाज सुन जब फिर टीवी खोला, तो सुखद आश्चर्य से भर गए। हालांकि 2007 (टी-20 के पहले विश्व कप) के बाद दूसरी बार विश्व कप जीतने वाली टीम के सबसे होनहार बल्लेबाज विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा के इस प्रारूप से संन्यास की घोषणा से प्रशंसकों को धक्का तो लगा, लेकिन सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर ऐसा सुविचारित निर्णय लेना सही ही कहा जाएगा। स्वाभाविक है कि इसके बाद ये धुरंधर अपना पूरा ध्यान भारत को टेस्ट और वनडे विश्व कप जिताने पर लगा पाएंगे। जीत के बाद जिस तरह लगभग सारे खिलाड़ी भावुक हो रो रहे थे, उससे उनकी तपस्या दिख रही थी। यही कारण है कि भारत ही एकमात्र ऐसी टीम रही, जो पूरे टूर्नामेंट में आखिर तक अजेय रही।

हार से ली जीत की प्रेरणा: यह जीत इसलिए भी और बड़ी कही जाएगी, क्योंकि पिछले वर्ष एकदिवसीय विश्वकप के फाइनल तक अजेय रहने वाली भारतीय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिर में लड़खड़ा गई। इस बार टीम ने वह गलती नहीं की। इसका प्रमाण इस बार का रोमांचक फाइनल है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से भारतीय खिलाड़ियों ने जीत को खींच लिया। लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रही टीम को हार से निराशा-हताशा तो होती है, पर खिलाड़ियों को इन सबसे उबरते हुए न केवल अगले मैच और टूर्नामेंट के लिए तैयार होना पड़ता है, बल्कि उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ भी देना होता है।

सीख है बड़ी: टी-20 विश्व कप में भारत की जीत में उन सभी लोगों, खासकर युवाओं के लिए बड़ी सीख और प्रेरणा है, जो जीवन की आपाधापी में छोटी-छोटी मुश्किलों से परेशान-निराश होकर अपनी नियति को कोसते हुए हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। दरअसल, हर हार या असफलता में कोई न कोई सीख छिपी होती है। भारतीय टीम ने जिस तरह अपनी पिछली असफलता को भुलाते हुए उससे सीख ली और जीत की पटकथा लिखी, वह हम सभी के लिए बड़ी सीख है। ध्यान रखें, हर अंधेरी रात के बात उजाले की सुबह जरूर होती है। इसलिए अपनी गलतियों-भूलों पर गौर करें, उसे सुधारें और फिर दूने उत्साह के साथ लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाएं।

54 की उम्र में कायम है जोश

जज्बे और हौसले का नमूना भारतीय क्रिकेट टीम की ताजा जीत तो है ही, इसका एक और ताजा उदाहरण पांच बार शतरंज के विश्व चैंपियन रहे हमारे विश्वनाथन आनंद भी हैं जो हाल ही में 54 की उम्र में लियोन मास्टर्स के फाइनल में स्पेन के जैमे सैंटोस को हराकर दसवीं बार विजेता बने। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि अपने प्रोफेशन के प्रति आपके भीतर जुनून है, तो कोई भी बाधा आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती।

एसएससी एमटीएस भर्ती

स्मार्ट तैयारी के लिए उपयोगी एप

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से आगामी मल्टी टास्किंग (नान-टेक्निकल) स्टाफ तथा हवलदार एग्जामिनेशन- 2024 के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्टूबर/नवंबर में प्रस्तावित है। इस भर्ती के माध्यम से ही विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में सहायक, चपरासी, माली और क्लीनर जैसे पदों पर भर्ती की जाती है। हर साल लाखों की संख्या में 10वीं योग्यता वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण कम ही उम्मीदवार इस परीक्षा को क्लियर कर पाते हैं। आइए जानें, एप्स की मदद से कैसे एमटीएस की स्मार्ट तैयारी की जा सकती है...

एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी 2024: केवल एमटीएस ही नहीं, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए यह एक उपयोगी एप है। क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर की सुविधाएं यहां मिल सकती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सुविधा के लिए ये सभी कंटेंट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। यहां पर मैथ्स, रीजनिंग तथा इंग्लिश आदि विषयों के अलग-अलग नोट्स दिए गए हैं। एप की रेटिंग भी अच्छी है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर: पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का बारीकी से अवलोकन करके तैयारी करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि इससे परीक्षा के ट्रेंड का पता चलता है कि किन विषयों से कितने प्रश्न इस प्रश्नपत्र में पूछे जाते हैं और इनकी प्रकृति किस तरह की होती है। इससे कुछ खास महत्वपूर्ण विषयों और उनके चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देने से अच्छे अंक पाने के अवसर बढ़ जाते हैं और इससे प्रैक्टिस भी होती रहती है। यह एप इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें आपको 2016 से लेकर अभी तक के सभी शिफ्ट के प्रश्नपत्र मिल सकते हैं। इसके लिए इसमें एसएससी एमटीएस के लिए 40 प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं। यह एप भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट 2024: किसी भी परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ उसकी नियमित अंतराल पर प्रैक्टिस करते रहने से बेहतर तैयारी में काफी मदद मिलती है। इससे प्रैक्टिस के दौरान सामने आए कमजोर एरिया को ठीक करने का भी समय मिल जाता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस एप में भी प्रैक्टिस के लिए कई सेट्स मिल जाएंगे, जिससे तैयारी को और मजबूत किया जा सकता है। यह एप भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

धीरेंद्र पाठक

महत्वपूर्ण जानकारियां

कुल रिक्तियों की संख्या: 8326। इसमें एमटीएस के लिए 4887 पद तथा हवलदार के लिए 3439 पद निर्धारित हैं।

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार के पास हाईस्कूल की योग्यता होनी चाहिए।

उम्र सीमा: एमटीएस पदों के लिए उम्र सीमा 18-25 वर्ष के बीच होनी चाहिए यानी आपका जन्म 2 अगस्त, 1999 से 1 अगस्त, 2006 के बीच हुआ हो। वहीं, हवलदार के लिए 18-27 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए।

आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2024 तक

चयन प्रक्रिया: एमटीएस के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) होगी। वहीं हवलदार पदों के लिए सीबीई के अलावा पीईटी/फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूमेरिकल एंड मैथमैटिकल एबिलिटी (20 प्रश्न), रीजनिंग एबिलिटी एंड प्राब्लम साल्विंग (20 प्रश्न), जनरल अवेयरनेस (25 प्रश्न) तथा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कांप्रिहेंशन (25 प्रश्न) से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि: अक्टूबर/नवंबर, 2024

कैसे करें आवेदन: इसके लिए वेबसाइट https://ssc.gov.in देखें।

वर्ग पहेली-2682

बाएं से दाएं
2. लड़ना, सामना करना (2,2)। 4. समसामयिक व्यक्ति, मित्र, सखा (4)। 6. बांग्लादेश की मुद्रा (2)। 7. गुण-दोष, स्वाद आदि जानने की शक्ति (4)। 9. एक प्रकार की दाल (4)। 10. सोना, धतूरा (3)। 12. कड़ी और भयंकर आवाज (3)। 15. उथल-पुथल, शोर-गुल (4)। 17. बेपर्दा (4)। 19. चमड़ा (2)। 20. खून का दबाव (4)। 21. नाव के पीछे की ओर लगी तिकोनी लकड़ी (4)।

ऊपर से नीचे
1. काट कर हटा देना (4)। 2. संसार का चाल-चलन (4)। 3. बही-खाता लिखने वाला कर्मचारी (4)। 5. छोटी कथा, कथासार (4)। 8. समाधान, खेती करने का एक यंत्र (2)। 9. घमंड, कड़ापन (3)। 11. लेख आदि की प्रतिलिपि (3)। 13. चंद्रमा, कलाओं का ज्ञाता (4)। 14. दंड (2)। 15. हिरासत, कैद (4)। 16. जड़ और चेतन (4)। 18. अनेक पैरों वाला (4)।

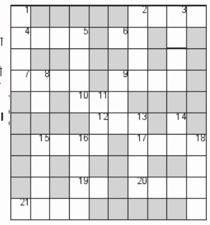

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

जागरण सुडोकू-2682

	9	1		4		6		3
				3			7	
2	3		8		6		9	
1	7		3			2		6
	6			2	5		8	
4		2		7				9
	5		1		2		3	7
		3		5		8		
9	2		7		3		1	5

कल का हल

8	6	1	2	5	7	9	3	4
9	5	2	4	3	6	1	8	7
4	7	3	8	9	1	2	5	6
3	1	4	6	7	2	8	9	5
2	9	7	5	8	4	3	6	1
5	8	6	3	1	9	4	7	2
1	3	8	7	2	5	6	4	9
7	4	9	1	6	3	5	2	8
6	2	5	9	4	8	7	1	3

आज का भविष्यफल- 06 जुलाई, 2024 शनिवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आज का राहुकाल: प्रात: 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक। आज का दिशाशूल: पूर्व।
आज का पर्व एवं त्योहार: गुप्त नवरात्र। विशेष: शुक्र कर्क राशि में।

कल 07 जुलाई, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल: पश्चिम
पर्व एवं त्योहार: श्री जगन्नाथ रथ यात्रा
विशेष: रवि पुष्य योग
विक्रम संवत 2081 शके 1946 उत्तरायण, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया 29 घंटे तक, तत्पश्चात तृतीया पुष्य नक्षत्र हर्षण योग तत्पश्चात वज्र योग कर्क में चंद्रमा।

मेष: किसी से तनाव मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होगा।
वृष: रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।
मिथुन: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। किया गया प्रयास सार्थक होगा।
कर्क: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
सिंह: उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है। रिश्तों में निकटता आएगी।
कन्या: सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्य सफल होंगे।
तुला: व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
वृश्चिक: किसी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
धनु: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।
मकर: दांपत्य जीवन सुखमय होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
कुंभ: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
मीन: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बिफरे रामनगरी के संत

जागरण संवाददाता, अयोध्या

रामनगरी अयोध्या के संतों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। संतों ने राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने और अखिलेश यादव द्वारा सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहे जाने को अनर्गल व अक्षम्य बताया। शीर्ष पीठ बड़ा भक्तमाल के सभागार में अयोजित बैठक में संतों-महंतों ने निर्णय किया कि यदि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सार्वजानिक रूप से माफी नहीं मांगते, तो अयोध्या के सभी साधु-संत और हिंदू समाज के लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

बैठक में मधुरोपासना की शीर्ष पीठ रंगमहल के महंत रामशरणदास ने कहा कि जो हिंदू पूरी दुनिया में शांति-सौमनस्यता के लिए विख्यात हैं, उन्हें हिंसक बताना भारतीय संस्कृति के प्रति घात है। जानकीघाट बड़ास्थान के पीठाधीश्वर महंत जन्मेजयशरण ने कहा कि अयोध्या के राजा तो श्रीराम हैं और हम उनके अतिरिक्त किसी और को राजा कहा जाना स्वीकार नहीं कर सकते। महंत गौरीशंकरदास ने कहा कि राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकते हैं। उनके पूर्वजों ने अखंड भारत के टुकड़े करवा दिए। राहुल गांधी के जो आका हैं, उन्होंने भगवान श्रीराम को काल्पनिक बता दिया था। महंत जनार्दन दास ने कहा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सम्मान नहीं है। बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। हिंदू तो अहिंसावादी है, वह तो परोपकार करने वाला है।

हिंदू गौरवसभा में उपस्थित क्रमशः (बाएं से दाएं) महंत रामानंददास, डा. राघवाचार्य, महंत बृजमोहन दास, महंत वैदेहीवल्लभ शरण, महंत जनार्दन दास एवं अन्य विशिष्ट संत-महंत। जागरण

भोजशाला मामले में जैन समाज की याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: मप्र के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पर जैन समाज के दावा करने संबंधी याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिका निर्धारित प्रारूप में नहीं है। याचिकाकर्ता चाहें तो इसे दोबारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

नई दिल्ली के सलेक जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि एएसआइ द्वारा किए गए भोजशाला सर्वे में जैन समाज के तीर्थंकर और देवी-देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इससे जैन गुरुकुल और मंदिर होने के प्रमाण भी सामने आए हैं। याचिका में इन मूर्तियों को जैन समाज को सौंपने की मांग की गई थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने महज दो मिनट की सुनवाई में याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि जैन समाज के लोगों ने सलेक की याचिका में किए दावे पर आपत्ति जताई है। जैन समाज के लोग हर मंगलवार को भोजशाला परिसर में होने वाली पूजा में हिंदू समाज के साथ शामिल हो चुके हैं।

सुविधाएं बढ़ने व माहौल बदलने से सुगम हुई अमरनाथ धाम की यात्रा

- सात दिन में 46 हजार श्रद्धालु जम्मू से गए, किंतु लगभग डेढ़ लाख कर चुके दर्शन
- दूसरे राज्यों से जम्मू आने के बजाय श्रद्धालु सीधे बालटाल और पहलगाम पहुंच रहे

जागरण संवाददाता, जम्मू

कश्मीर में शांति और बदलाव से अनुकूल हुए वातावरण के बीच सुविधाएं बढ़ने से श्रद्धालुओं का अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा करने का तरीका ही बदल गया। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अधिकांश श्रद्धालु अब जम्मू स्थित यात्री निवास के बजाय अब सीधे बालटाल और पहलगाम आधार शिविर पहुंचकर तीर्थयात्रा में शामिल हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई है और जम्मू से पहला जत्था 28 जून को रवाना हुआ था। अब तक का आंकड़ा देखा जाए तो प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करने वाले कुल श्रद्धालुओं में से 30 प्रतिशत ही जम्मू यात्री निवास से दैनिक जत्थे के साथ गए हैं। बाकी 70 प्रतिशत श्रद्धालु सीधे बालटाल व पहलगाम आधार शिविर पहुंचे। बता दें कि बाबा अमरनाथ यात्रा पर गए 21686 और श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को पवित्र गुफा के दर्शन किए। इसके साथ ही अब तक 1,51,946 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं।

जम्मू यात्री निवास से शुक्रवार तक आठ जत्थे रवाना हुए हैं। इन जत्थों में 46,589 श्रद्धालु यात्रा के लिए गए, जबकि अब तक डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ धाम में पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं। इस बार अभी तक मौसम भी पूरा साथ दे रहा है। बारिश के बावजूद एक बार भी यात्रा को रोकना नहीं पड़ा। श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा तत्काल पंजीकरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारों से आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूरे आसार हैं कि इस बार रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु यात्रा करेंगे।

अब आतंक का भय नहीं, हाईवे पर सफर भी सुगम

एक समय था जब कश्मीर में आतंकी हिंसा के चलते भय के साये में अमरनाथ यात्रा होती थी। इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु जम्मू से जत्थे के साथ सुरक्षा घेरे में ही यात्रा करने को प्राथमिकता देते थे। पांच अगस्त, 2019 के बाद से कश्मीर के हालात तेजी से बदले हैं। आम लोगों में अब आतंक का भय नहीं रहा। इसलिए श्रद्धालु भी बेखौफ होकर निजी वाहनों से भी सीधे कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर आसान हुआ है। सुविधाएं बढ़ी हैं, इसलिए श्रद्धालु जम्मू में न रुक कश्मीर में घूमने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

बांग्लादेशी श्रद्धालुओं को रामनगरी में मिला 'भरोसे का प्रसाद'

प्रहलाद तिवारी ● जागरण

अयोध्या: रामनगरी आ रहे श्रद्धालुओं को रामलला का आशीर्वाद मिलने के साथ ही भरोसे का प्रसाद भी मिल रहा है। अयोध्या में जिस निश्चिंतता व भरोसे से वे आते हैं, वह भरोसा यहां टूटता नहीं। दर्शनार्थी आराम से दर्शन-पूजन और नगर भ्रमण कर पाते हैं। यदि कहीं कोई समस्या आती तो पुलिस बड़ा सहारा बनती है। एक घटना बांग्लादेश के श्रद्धालुओं के साथ हुई, लेकिन जाते-जाते उन्हें यहां के लोगों व प्रशासनिक तंत्र पर इतना यकीन हो गया कि वह मुस्कराते हुए रामलला का दर्शन कर वापस गंतव्य को रवाना हुए।

दरअसल, बांग्लादेश से तीन हिंदू चंदन कहार, दालिम मजूमदार व खुकूरानी मजूमदार रामलला के दर्शन के लिए बुधवार को यहां आए थे। राम मंदिर व हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन के बाद वह वापस जाने लगे। हनुमानगढ़ी चौराहे पर तीनों ई-रिक्शा पर सवार होकर लता मंगेशकर चौक गए। वहां चौक ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि वह बिना किसी की परवाह के उतर गए। उनका बैग ई-रिक्शे में छूट गया। बैग में पासपोर्ट के अलावा धनराशि भी थी। उन्होंने इसकी शिकायत नयाघाट पुलिस चौकी में की और सहायता मांगी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की पड़ताल की। ई-रिक्शा का नंबर पता किया। फिर उसके मालिक को फोन किया। ई-रिक्शा मालिक ने बैग होने की पुष्टि की। नयाघाट पुलिस चौकी पर मौजूद एसपी सिटी मधुबन सिंह ने एक आरक्षी को भेजकर बैग मंगवाया। प्रभारी निरीक्षक एमके शर्मा ने बैग उन्हें वापस किया तो बांग्लादेशी नागरिकों के चेहरे खिल उठे।

खोए हुए बैग के साथ नयाघाट पुलिस चौकी में बांग्लादेशी श्रद्धालु। जागरण

जम्मू-कश्मीर में भाजपा 90 सीट पर लड़ेगी विस चुनाव

श्रीनगर, एएनआइ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गत गुरुवार को नई दिल्ली में अहम बैठक में राजनीतिक हालात व विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों विशेषकर कश्मीर में भाजपा को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। बैठक में फैसला हुआ कि पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जम्मू-कश्मीर में भाजपा द्वारा अकेले अपने बूते सरकार बनाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू दौरे पर हैं। वह भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में शाह सहित प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक हुई। यह बैठक लगभग दो घंटे तक जारी रही। इसमें प्रदेश भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना, जम्मू-कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कौल आदि भी मौजूद रहे।

राम मंदिर के शिखर पर लगेगा 46 क्विंटल का 50 फीट ऊंचा ध्वजदंड

जागरण संवाददाता, अयोध्या: राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 46 क्विंटल का 50 फीट ऊंचा ध्वजदंड लगाया जाएगा। ध्वजदंड पीतल का है। इसे इसी वर्ष आठ जनवरी को अहमदाबाद से रामनगरी लाया जा चुका है और इसी वर्ष के अंत तक शिखर का निर्माण पूर्ण होने के बाद स्थापित किया जाना है। शुक्रवार को श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में इस पर विचार किया गया।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डा. अनिल मिश्र ने बताया कि ध्वजदंड को लेकर मंदिर निर्माण समिति पूरी सजगता बरत रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि आंधी-तूफान व बंदरों के उपद्रव से पार पाते हुए यह किस प्रकार पूरी स्थिरता और दृढ़ता से स्थापित किया जा सकता है।

मुख्य शिखर के अतिरिक्त पांच उप शिखर भी ध्वज से युक्त होंगे और इनके भी लिए 20-20 फीट ऊंचा पीतल का ध्वजदंड मुख्य दंड के साथ लाया जा चुका है। ध्वजदंडों का निर्माण अहमदाबाद की कंपनी अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स ने किया है।

मंदिर में 1.30 लाख घन फीट शिलाएं और लगेंगी: श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित कार्यदायी संस्था एलएंडटी के कार्यालय में हुई पाक्षिक बैठक में तय किया गया कि मंदिर निर्माण में 1.30 लाख घन फीट शिलाएं और प्रयुक्त होंगी। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के लाल बलुआ पत्थर से मंदिर का निर्माण हो रहा है।

25 और मूर्तियों की होगी स्थापना: बैठक के अन्य बिंदुओं पर विचार करते हुए मुख्य गर्भगृह में स्थापित रामलला के अतिरिक्त 25 अन्य मूर्तियों की स्थापना को लेकर कार्ययोजना बनाई गई है। इन 25 मूर्तियों में से छह प्रथम तल के गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी।

रामजन्मभूमि परिसर स्थित एलएंडटी के कार्यालय परिसर में मंदिर निर्माण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय (मध्य में), डा. अनिल मिश्र (मध्य में बाएं) व मंदिर कार्य में लगी संस्थाओं के पदाधिकारी। सौ. से श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट

बनासकांठा सीट हारने पर मंत्री पाटिल ने कार्यकर्ताओं से मांगी माफी

राज्य, अहमदाबाद: सारंगपुर में गुजरात प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने प्रदेश की बनासकांठा सीट हारने पर कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है, वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने पर उत्साहित हैं, लेकिन राहुल यह भूल गए कि कांग्रेस को ये सीटें 543 सीटों में से मिली हैं। कार्यकारिणी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने को संकल्पबद्ध हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है।

कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार देश की कमान संभालने पर प्रस्ताव पारित कर उन्हें बधाई दी गई। केंद्रीय मंत्री और गुजरात भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि गुजरात की 26 में से 25 सीट पर जीत दर्ज की लेकिन बनासकांठा सीट हार गए। उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए कार्यकर्ताओं से माफी मांगी।

****

फ्रांस में रेबीज के पहले सफल टीके का किया गया परीक्षण

1885 में आज ही फ्रांस में लुई पाश्चर द्वारा विकसित रेबीज के पहले टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसे एक नौ वर्षीय लड़के को कुत्ते के काटने के 60 घंटे बाद लगाया गया था। तीन सप्ताह तक 13 इंजेक्शन का कोर्स पूरा करने के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था।

ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने नौरोजी

1892 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रवादी दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटेन में सेंट्रल फिंस्बरी की सीट से लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। इसी के साथ ब्रिटिश हाउस आफ कामंस के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय बने। उन्होंने पांच वोटो के अंतर से जीत अपने नाम की थी।

रक्षा विज्ञान के वास्तुकार माने जाते हैं दौलत सिंह कोठारी

विज्ञानी दौलत सिंह कोठारी का जन्म 1906 में आज ही के दिन उदयपुर में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में करियर की शुरुआत की। 1934 में दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्रमुख बने और विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए। 1948 में रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए और भारत में रक्षा विज्ञान संगठन की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एनसीईआरटी जैसे संस्थाओं की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई थी और उनमें सुधार भी किया।

किसान ने उगाया अत्यधिक प्रोटीन युक्त जापानी आम

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

दुनिया के सबसे महंगे आमों में से एक जापानी आम मियाजाकी का उत्पादन किसान ने किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.70 लाख से तीन लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है। किसान का बाग आर्गेनिक है। इसकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है।

थरौली की ग्राम प्रधान रीता चौधरी के पति एवं किसान संदीप चौधरी ने बताया कि उन्होंने नौ महीने पहले कोलकाता से मंगाकर बाग में मियाजाकी के दो पौधे लगाए थे। अब इनकी ऊंचाई करीब तीन फीट हो गई है। अब तक एक पेड़ पर दो, दूसरे पर एक आम आया है। इसका वजन करीब 300 या 350 ग्राम होगा। उम्मीद है कि अगस्त में फल पक जाएगा। संदीप ने बताया कि उनके बाग में अन्य विदेशी किस्म के आम के पेड़ भी उगाए गए, जिसमें तुर्किए, चीन, अमेरिका, जापान, मिस्र और ताइवान जैसे देशों के आम के पौधे शामिल हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर मियाजाकी आम की जानकारी साझा की, जिसके बाद सूरत के व्यापारी प्रवीण गुप्ता ने खरीदने के लिए संपर्क किया। जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह ने बताया कि जापानी आम की प्रजाति अत्यधिक प्रोटीन युक्त होती है। इसमें सर्वाधिक विटामिन पाए जाते हैं। यह कैंसर के खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है।

- **जापानी आम मियाजाकी में पाए जाते हैं सर्वाधिक विटामिन**
- **कैंसर के खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है यह आम**

सहारनपुर के थरौली गांव में आर्गेनिक बाग में मियाजाकी के पौधे पर लगे आम। सौ स्वयं

ये है आम की खासियत : जापान के मियाजाकी शहर के नाम प्रजाति का नाम रखा गया है। इसमें कुछ प्रकार के एंटीआक्सिडेंट और बीटा-कैरोटीन व फोलिक एसिड जैसे अन्य रासायनिक घटक पाए जाते हैं। कैंसर की दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें जिंक, कैल्शियम, विटामिन सी व ए के अलावा कापर व मैगनीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं।

क्यों है महंगा : तेज धूप और अधिक बारिश में पैदा होने वाले मियाजाकी आम की शुरुआती कीमत करीब अस्सी हजार रुपये किलो से शुरू होती है। आम उत्पादन का कम प्रतिशत हिस्सा ही बाजार तक पहुंच पाता है। इसलिए फल की कीमत तीन लाख किलो तक पहुंच जाती है।

नवजात शिशुओं के लिए बड़ा खतरा बना जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन का गंभीर प्रभाव अब नवजात शिशुओं पर भी पड़ता दिख रहा है। जर्मनी के पाट्सडैम इंस्टीट्यूट फार क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च (पीआइके) सहित शोधकर्ताओं की अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए एक शोध में इस संदर्भ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार 2001 से 2019 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले 29 देशों में चार प्रतिशत से अधिक नवजात शिशुओं की मौत जलवायु परिवर्तन से होने वाले उच्च और निम्न तापमान की वजह से हुई। यह देश मुख्यत : उप-सहारा अफ्रीका और एशिया के हैं।

अत्यधिक ठंड से हुईं ज्यादा मौतें

शोधकर्ताओं के अनुसार अत्यधिक गर्मी की तुलना में अत्यधिक ठंड से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई। चार प्रतिशत में 1.5 प्रतिशत मृत्यु जहां अत्यधिक गर्मी की वजह से हुई वहीं लगभग तीन प्रतिशत मौतें अत्यधिक ठंड से जुड़ी थीं। इसके अलावा, 2001-2019 के बीच नवजात शिशुओं में गर्मी से संबंधित सभी मौतों में से 32 प्रतिशत यानी लगभग 1.75 लाख से अधिक मौतें जलवायु परिवर्तन के कारण हुईं।

तापमान में वृद्धि: अध्ययन में शामिल 29 देशों में 2001-2019 के दौरान वार्षिक तापमान में औसतन 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। अध्ययनकर्ताओं ने इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है।

इन देशों में मृत्यु दर सबसे अधिक

जलवायु परिवर्तन की वजह से नवजात मृत्यु दर सबसे अधिक पाकिस्तान, माली, सिएरा लियोन और नाइजीरिया में होने का अनुमान है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन देशों में तापमान से संबंधित नवजात शिशुओं की मृत्यु दर भी सबसे अधिक है। यहां प्रति एक लाख शिशुओं के जन्म पर 160 से अधिक की मृत्यु तापमान से संबंधित वजहों से होती हैं। अत्यधिक तापमान से जुड़ी नवजात शिशुओं की मौतों पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उप-सहारा अफ्रीकी देशों में देखा गया।

इन वजहों से होती है मृत्यु: नवजात शिशुओं में तापमान के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तेज मेटाबालिज्म और कम पसीना निकलने की वजह से शरीर से गर्मी नहीं निकल पाती और स्थिति अधिक जटिल हो जाती है। (स्रोत : प्रेट्र)

आम नागरिकों को स्पेसवाक पर ले जाने वाला मिशन इसी माह

नई दिल्ली, आइएएनएस : अरबपति जेरेड इसाकमैन और तीन अन्य को स्पेसवाक पर ले जाने के लिए पोलारिस डान मिशन पूरी तरह तैयार है। स्पेसवाक के लिए आम नागरिकों को शामिल करने वाली यह पहली उड़ान होगी। पोलारिस डान के 31 जुलाई को लांच होने की उम्मीद है। यह पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा, जिसमें स्पेसवाक शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अबतक मिशन की औपचारिक घोषणा नहीं की है।

यह शिफ्ट4 के संस्थापक इसाकमैन द्वारा पोलारिस कार्यक्रम के तहत पहला मिशन है। वह 2021 में लांच किए गए इंस्पिरेशन4 मिशन के कमांडर थे। उन्होंने स्पेसएक्स के साथ तीन अंतरिक्ष उड़ानें खरीदीं व श्रृंखला का नाम पोलारिस रखा। पृथ्वी से 700 किमी ऊपर स्पेसवाक के दौरान भविष्य के मिशनों के लिए स्पेसएक्स की ओर से डिजाइन स्पेससूट का भी परीक्षण होगा। पोलारिस डान के क्रू कक्षा में पांच दिन बिताएंगे। इसाकमैन के अलावा चालक दल के तीन यात्रियों में पायलट स्काट किड पोटेट, देखरेख करने वाली सारा गिलिस और चिकित्सा अधिकारी अन्ना मेनन शामिल हैं।

एक प्रतिशत से कम किशोर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद

अध्ययन में आठ एशियाई और यूरोपीय देशों के 13,000 से अधिक किशोरों को शामिल किया

28-50 प्रतिशत किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य का करना पड़ता है सामना

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत सहित मध्यम आय वाले देशों में एक प्रतिशत से भी कम किशोरों ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए पेशेवरों की मदद ली, जबकि 28-50 प्रतिशत किशोरों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। एक अध्ययन के अनुसार यह जानकारी सामने आई है।

शोध में यह भी पाया गया कि कई देशों में विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में किशोरों के बीच मदद के लिए अनौपचारिक स्रोतों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन मध्यम आय वाले देशों भारत, वियतनाम और चीन का उन्होंने अध्ययन किया, उनमें 0.6-0.9 प्रतिशत लड़कियों और 0.9-1.2 प्रतिशत लड़कों ने पेशेवर मदद ली। फिनलैंड में तुर्कू विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में आठ एशियाई और यूरोपीय देशों के 13-15 वर्ष की आयु के 13,000 से अधिक किशोरों को शामिल किया गया, जिन्होंने 2011 और 2017 के बीच सर्वेक्षणों का जवाब दिया। शोध में लड़कियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मदद लेने की संभावना लड़कों की तुलना में अधिक पाई गई।

किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर रखें नजर।

शोधकर्ताओं ने पाया कि उच्च आय वाले देशों में अधिक संख्या में किशोरों ने औपचारिक मदद मांगी। इनमें ग्रीस, इजराइल और जापान में 6-7 प्रतिशत और नार्वे व फिनलैंड में 21-25 प्रतिशत तक शामिल हैं। ये निष्कर्ष यूरोपियन चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री पत्रिका में प्रकाशित हुए। उन्होंने पाया कि किशोरों के बीच सहायता के अनौपचारिक स्रोतों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कई देशों में, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में सहायता के प्रमुख स्रोत हैं।

लेखक ने पाया कि सहायता मांगने वाले किशोरों में से लगभग 90 प्रतिशत ने एशियाई देशों में अनौपचारिक मदद मांगी, जिसमें लड़कियों के लिए लगभग 92 प्रतिशत (भारत) से 96 प्रतिशत (चीन) और लड़कों के लिए लगभग 88 प्रतिशत (भारत) से 96 प्रतिशत (चीन) शामिल हैं। भारत में लड़कियों की तुलना में अधिक लड़के शिक्षकों से सहायता मांगते पाए गए।

तुर्कू विश्वविद्यालय में डाक्टरेट शोधकर्ता व प्रमुख लेखक युको मोरी ने कहा कि किशोरों को अनौपचारिक स्रोतों जैसे कि दोस्तों, शिक्षकों व परिवार के सदस्यों या औपचारिक स्रोतों जैसे कि स्कूल की नर्सों, मनोविज्ञानियों और पेशेवरों से सहायता के लिए मदद मिल सकती है।

यूरेशियन चाइल्ड मेंटल हेल्थ स्टडी (ईएसीएमएचएस) के शिक्षक व प्रोफेसर आंद्रे सोरेंडर के अनुसार, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में मदद के लिए उपयोग किए जाने वाले अनौपचारिक स्रोत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रमों की वैश्विक आवश्यकता को उजागर करते हैं, जिसका यह शोध का हिस्सा था।

सोरेंडर ने कहा कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अंतर सांस्कृतिक अध्ययन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लगभग सभी मानसिक स्वास्थ्य शोध उच्च आय वाले पश्चिमी देशों से आते हैं। निम्न आय वाले देशों में किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है।

नई सर्जरी से ट्यूमर का आपरेशन होगा आसान

नई दिल्ली, आइएएनएस : जापानी शोधकर्ताओं ने ब्रेन सर्जरी के लिए एक नई तकनीक की खोज की है जो खोपड़ी के आधार पर मुश्किल ट्यूमर को निशाना बनाती है। यह ऐसा क्षेत्र जो नसों, रक्त वाहिकाओं, अन्य ऊतकों और मस्तिष्क स्टेम से घना होता है। खोपड़ी के आधार में होने वाले ट्यूमर न्यूरो सर्जरी में निकालने में सबसे कठिन होता है। वर्तमान इलाज पद्धति माइक्रोस्कोपिक एंटीरियर ट्रांसपेट्रोसल एप्रोच (एटीपीए) के रूप में जानी जाने वाली सर्जिकल तरीके से हटाने की है।

ओसाका मेट्रोपालिटन यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल रिसर्च टीम ने एक नई न्यूनतम इनवेसिव सर्जिकल तकनीक विकसित की है, जिसे विशुद्ध रूप से एंडोस्कोपिक सब टेम्पोरल कीहोल (एटीपीए) कहा जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य क्षति और पोस्टआपरेटिव जटिलताओं के जोखिम को कम करना है। इससे माइक्रोस्कोपिक एप्रोच की तुलना में खोपड़ी के औसतन केवल 11.2 सेमी2 बनाम 33.9 सेमी2 के एक छोटे क्षेत्र को सर्जरी द्वारा खोलने की आवश्यकता होती है। इससे मस्तिष्क के नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम होता है। टीम के सदस्यों ने द जर्नल आफ न्यूरो सर्जरी में शोध प्रकाशित किया है। एंडोस्कोपिक एप्रोच ने आपरेटिव समय को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया, जो औसतन 410.9 मिनट से 252.9 मिनट हो गया। इसी तरह ब्लड का नुकसान भी औसतन 193 मिली से घटकर 90 मिली हो गया। ट्यूमर रिसेक्शन (सर्जिकल हटाने) की डिग्री माइक्रो स्कोपिक विधि जितनी ही उच्च थी। न्यूरोलाजिकल फंक्शन पारंपरिक एप्रोच के बराबर या उससे अधिक दर पर संरक्षित किए गए थे।

- **इसमें एक छोटे क्षेत्र को सर्जरी में खोलने की होती है आवश्यकता**
- **एंडोस्कोपिक एप्रोच ने आपरेटिव समय को कम कर दिया, ब्लड का नुकसान भी कम हुआ**

सिर का ट्यूमर। फाइल

इधर-उधर की

अमेरिका में सड़क पर दौड़ता दिखा 'यूएफओ'

यूएफओ फेस्टिवल के लिए डिजाइन किया गया था वाहन। इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी: अब तक यूएफओ यानी अज्ञात उड़न तस्तरी को लेकर सिर्फ बातें ही सुनी होगी। लेकिन अमेरिका में ओक्लाहोमा हाईवे पर यूएफओ को दौड़ते हुए देखा गया। इसे देखकर वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस हैरान रह गई। जब पुलिस ने इसे रोका तो कुछ और ही बात निकलकर सामने आई। दरअसल, यह कोई यूएफओ नहीं बल्कि यूएफओ जैसी डिजाइन वाला वाहन था। इसमें दो व्यक्ति सवार थे। जब पुलिस ने वाहन को रोका तो ऊपर बने ढक्कन को खोलकर एक व्यक्ति बाहर आया। उसने बताया कि दोनों न्यू मैक्सिको में रोसवेल यूएफओ फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर पुलिस ने इस घटना को शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा है कि ऐसा हर दिन नहीं होता कि आप के सामने से एक यूएफओ निकल जाए। पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर जाने दिया।

वजन घटाने वाली दवाओं से आखों की रोशनी पर पड़ सकता है प्रभाव

अनुसंधान

मोटापा बड़ी समस्या बनती जा रही है। वजन कम करने के लिए लोग क्या-क्या जतन नहीं करते। सुबह उठकर टहलने के लेकर दौड़ तक लगाते हैं। यही नहीं लोग जिम में भी पसीना बहाते नजर आते हैं। उसके बाद भी अगर लाभ नहीं हो तो वे दवा लेने से भी नहीं हिचकते। हालांकि, दवा लेना खतरनाक भी हो सकता है। एक शोध में सामने आया है कि मोटापे की दवा से आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है।

अमेरिका के मैसाचुसेट्स आई एंड ईयर अस्पताल के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि मोटापे से ग्रस्त जिन मरीजों को वजन घटाने वाली दवाएं दी गईं, उनमें नान-आर्टेरिटिक एन्टीरियर इस्केमिक आप्टिक न्यूरोपैथी (एनएआइओएन) होने की आशंका सात गुना अधिक थी। इसके कारण अचानक आंखों की रोशनी जा सकती है। उन्होंने पाया कि मधुमेह के मरीज जो ये सेमाग्लूटाइड युक्त दवाएं ले रहे थे, उनमें एनएआइओएन होने की संभावना चार गुना अधिक थी। यह निष्कर्ष द जर्नल आफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन आप्थल्मोलाजी में प्रकाशित हुए हैं।

प्रतीकात्मक

मैसाचुसेट्स आई एंड ईयर में न्यूरो-नेत्र विज्ञान सेवा के निदेशक जोसेफ रिजो ने कहा कि यह जानकारी हमारे पास पहले नहीं थी। इसे रोगियों और उनके डाक्टरों के बीच चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। खासकर अगर रोगियों को ग्लूकोमा जैसी आप्टिक तंत्रिका समस्याएं हैं या यदि अन्य कारणों से पहले से ही रोशनी प्रभावित हुई हो। हालांकि, रिजो ने जोर देकर कहा कि यह जोखिम एक अपेक्षाकृत असामान्य विकार से संबंधित है और आगे के अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि शोधकर्ताओं को यह नहीं पता है कि वजन घटाने वाली दवाओं और आंखों की स्थिति के बीच संबंध क्यों या कैसे मौजूद है। (प्रेट्र)

पशु अधिकार के लिए...

सैन फर्मिन फेस्टिवल से पहले शुक्रवार को स्पेन के पैंपलोना में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने बुलफाइटिंग तथा बुल-रनिंग के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ज्ञातव्य है कि यह फेस्टिवल विशेकर बुल-रनिंग के लिए जाना जाता है। नौ दिवसीय फेस्टिवल शनिवार से आरंभ हो रहा है। एएफपी

स्क्रीन शाट

हमारे भीतर कई लोग बसे होते हैं : रसिका दुग्गल

मिर्जापुर 3 में बीना त्रिपाठी की निगेटिव भूमिका में हैं रसिका। इंस्टाग्राम - @rasikadugal

जो सपने असल जिंदगी में पूरे नहीं होते हैं, वह कई बार फिल्मों में आने के बाद पूरे हो जाते हैं। यहां कलाकार को अलग-अलगे पेशे से जुड़ी भूमिकाओं के साथ ही अलग व्यक्तित्व वाले लोगों की के किरदार निभाने का मौका मिलता है। ऐसा ही किरदार अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने निभाया है वेब सीरीज मिर्जापुर 3 में। बीना त्रिपाठी की निगेटिव भूमिका में उन्हें पसंद किया गया है। हालांकि इस रोल को करने के लिए रसिका को उस किरदार को काफी समझना पड़ा था। दैनिक जागरण से बातचीत में वह कहती हैं कि रोल अगर आपके व्यक्तित्व से अलग हो, तो उसे निभाने में मजा आता है, लेकिन आपको यह समझना पड़ता है कि इस इंसान के भीतर की वायरिंग कैसी है, जो आपसे बिल्कुल अलग है। वह एक कलाकार के लिए बहुत अलग सा अभ्यास भी हो जाता है। मुझे लगता है कि हम सब के अंदर बहुत सारे लोग बसे हुए होते हैं। हम अपनी वह साइड दुनिया को दिखाते हैं, जो अच्छा है। उसी साइड का अभ्यास भी ज्यादा करते हैं। वहीं दूसरी साइड को दबाकर रखते हैं, उसका कारण शर्म हो सकती है या फिर समाज की वजह से ऐसा करना पड़ता है। बीना के रोल के जरिए मुझे अपने उस स्वरूप का अभ्यास करने का मौका मिला, जो मैं दुनिया को नहीं दिखा सकती हूं। इसलिए मुझे इसकी शूटिंग के दौरान बहुत मजा आया। जिस तरह से बीना चालाकी से अपना काम निकाल लेती है, ढेर सारी योजनाएं बनाती है, यह करना दिलचस्प होता है। वह मुझसे अलग हैं, इसलिए मुझे ढूंढना पड़ता है कि कैसे मैं अपने और उस किरदार के बीच कनेक्शन बनाऊं।

फिल्में मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूं : काजल अग्रवाल

फिल्म इंडस्ट्री में काफी अनिश्चितता होती है। ऐसे में कलाकार प्लान बी यानी दूसरे पेशे में भी अपने हाथ आजमाते हैं। हालांकि दूसरे कामों के साथ उनका अभिनय के लिए भी प्यार बना रहता है। सिंघम, स्पेशल 26 फिल्मों की अभिनेत्री काजल अग्रवाल को भी फिल्मों से प्यार है, हालांकि वह इसके साथ ही होम डेकोर के व्यवसाय में भी व्यस्त हैं। हाल ही में एक समारोह में काजल से जब पूछा गया कि बिजनेस और अभिनय दोनों के बीच में वह कैसे संतुलन बना पा रही हैं? वह कहती हैं कि दोनों ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मेरे पति का बिजनेस में अच्छा अनुभव है। मैं जिस परिवार से आती हूं, वहां भी बिजनेस वाला ही माहौल रहा है। यह करने का सपना बचपन से रहा था। सिनेमा मेरे लिए प्राथमिक पेशा है और रहेगा। फिल्में मेरा पहला प्यार है, जो मैं कभी छोड़ने वाली नहीं हूं। लेकिन अपने समय को दोनों कामों के बीच बांटकर और मजबूत सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। वह कहती हैं कि मेरा बेटा नील घर में खुशियां लेकर आए हैं, वह मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। जो भी समस्या जिंदगी में हो, नील को देखकर एक सेकेंड में मिट जाती है।

अभिनय संग बिजनेस में सक्रिय हैं काजल। @kajalaggarwalofficial

अगर ऐसा हुआ तब म्यूजिक बनाना बंद कर देंगे बादशाह

कई बार जो सोचा है, वह हो नहीं पाता है और जो नहीं सोचा होता है, वह हो जाता है। हालांकि कहा जाता है कि जो होता है, अच्छे के लिए ही होता है। ऐसा ही कुछ रैपर बादशाह के साथ भी हुआ है। उनकी दिलचस्पी शेफ बनने में थी, वह कई रेस्तरां खोलना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें संगीत की तरफ ले आई। एक साक्षात्कार में बादशाह कहते हैं कि मैं अब भी शेफ हूं। खाना बनाना पसंद करता हूं। मेरे कई रेस्तरां भी हैं। मैं म्यूजिक इसलिए बनाता हूं, क्योंकि मैं इसे बनाना चाहता हूं।

हर सुबह उठता हूं, तो संगीत बनाने की चाहत होती है। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसा महसूस करता हूं। जिस दिन सुबह उठकर ऐसा महसूस नहीं होगा, मैं संगीत बनाना छोड़ दूंगा। मैं वैसा ही हूं, जो करने का मन नहीं करता है, मैं नहीं करता हूं। सच कहूं, तो एक समय के बाद आपको अहसास होता है कि आपके हाथों में कुछ नहीं है। सब ईश्वर की मर्जी से होता है। मैं एक वक्त पर सोचता था कि 35 साल की उम्र में काम से रिटायर हो जाऊंगा। अब लगता है कि योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता है। आप योजनाएं बनाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वह योजनाएं आपके हिसाब से नहीं पूरी होती हैं, तो उससे दुखी नहीं होना चाहिए।

अभिनय में भी हाथ आजमा चुके हैं बादशाह। इंस्टाग्राम - @badboyshah

ट्रोलर्स को वीडियो पोस्ट करके दिया दृष्टि ने करारा जवाब

टीवी के साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर भी काम कर रही हैं दृष्टि। इंस्टाग्राम - @dhamidrashti

कलाकारों का बिना बात ट्रोल हो जाना कोई नई बात नहीं है। कई बार ट्रोलर्स सितारों से ऐसे सवाल कर देते हैं, जिनका जवाब ना चाहकर भी उन्हें देना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ करना पड़ा दुरंगा वेब सीरीज की अभिनेत्री दृष्टि धामी को भी। पिछले महीने दृष्टि ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वह मां बनने वाली हैं। ट्रोलर्स ने उनकी प्रेग्नेंसी और बेबी बंप को नकली बताया था। अब दृष्टी ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों से बना एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनका बेबी बंप साफ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने जो पोस्ट लिखा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो ट्रोलर्स को जवाब दे रही हैं। दृष्टि लिखती हैं, 'ये सबूत है कि मेरा बेबी बंप एक बहुत बड़ा लंच (उनका इशारा था कि खाना खाने के कारण उनका वजन नहीं बढ़ा है) नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटेग के साथ लिखा कि हां मैं प्रेग्नेंट हूं। उन सभी लोगों के लिए, जो मुझसे पूछ रहे थे। क्या अब आप इसे (बेबी बंप) देख सकते हैं?' दृष्टि के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद कई प्रशंसक उनके सपोर्ट में आए। एक यूजर ने लिखा कि नफरत करने वालों को क्या करारा तमाचा मारा है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हम आप पर विश्वास करते हैं और आपके लिए खुश हैं।

****